2 राजधानी
पुलिस भर्ती परीक्षा आज से

6 अभिमत
कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव

10 राष्ट्रीय
सदस्यों ने कई प्रावधानों पर उठाए सवाल

11 विदेश
अमेरिका में हनुमान की विशाल मूर्ति स्थापित

RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 14 अंक 298
लखनऊ, शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ
नगर संस्करण

लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

कभी कभार आपको थोड़े से भाग्य की जरूरत होती है

स्पोर्ट्स-12

एफआईआर में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

लोहरदगा जिले में अल कायदा से जुड़े एक व्यक्ति के घर के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी।

कोलकाता में डॉक्टर रेप और हत्या मामला

राजेश कुमार। नई दिल्ली

नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आंदोलनरत डॉक्टर। हालांकि उच्चतम न्यायालय के अनुरोध के बाद डॉक्टरों ने जारी हड़ताल वापस ले ली। फोटोः रंजन डिमरी

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की अप्राकृतिक मौत दर्ज करने में कोलकाता पुलिस की देरी को 'बेहद परेशान करने वाला' करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को '14 घंटे की देरी' के बारे में कड़ी फटकार लगाई। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में देरी और पुलिस द्वारा आयोजित कानूनी औपचारिकताओं के अनुक्रम और समय पर सवाल उठाते हुए स्थिति रिपोर्ट में विसंगतियों को चिह्नित किया गया। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, जो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा की तीन पीठ के न्यायाधीशों का हिस्सा हैं, ने कहा कि उन्होंने अपने 30 वर्षों के जीवन में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली इस तरह की प्रक्रिया नहीं देखी है।.

इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि अप्राकृतिक मौत के रूप में मामला दर्ज करने से पहले 9 अगस्त को शाम 6.10 बजे से 7.10 बजे के बीच पीड़िता का पोस्टमॉर्टम किया गया था, शीर्ष अदालत ने मामले में एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की 'अस्पष्ट' देरी पर कोलकाता पुलिस की खिंचाई की। पीठ ने कहा, ऐसा कैसे हुआ कि पोस्टमार्टम 9 अगस्त को शाम 6.10 बजे किया गया और फिर भी अप्राकृतिक मौत की सूचना ताला पुलिस स्टेशन को 9 अगस्त को रात 11.30 बजे पोस्टमॉर्टम के बाद भेजी गई और रात 11.45 बजे एफआईआर दर्ज की गई। यह बेहद परेशान करने वाली बात है। पुलिस द्वारा की जाने वाली कानूनी औपचारिकताओं के अनुक्रम और समय पर सवाल उठाते हुए, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, आपके राज्य (पश्चिम बंगाल) द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया कुछ ऐसी है जो मैंने अपने जीवन के 30 वर्षों में नहीं देखी है। पहली बात यह है कि क्या यह सच है कि यूडी (अप्राकृतिक मृत्यु) सुबह 10.30 बजे (सुबह 10.30 बजे) दर्ज की गई थी? दूसरा, यह सहायक अधीक्षक नॉन मेडिकल (व्यक्ति) कौन है, इसका आचरण भी बेहद संदिग्ध है। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया?

इसने कोलकाता पुलिस अधिकारी को, जिन्होंने देश को झकझोर देने वाली घटना के बारे में पहली प्रविष्टि दर्ज की थी, अगली सुनवाई में पेश होने और प्रविष्टि के समय का खुलासा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई है। इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले पर एक स्थिति रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया कि अपराध स्थल को बदल दिया गया और छेड़छाड़ की गई, जिससे मामले में आगे की जांच में बाधा उत्पन्न हुई। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि प्रशिक्षु डॉक्टर के दाह संस्कार के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि कोलकाता के अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ-साथ पीड़िता के सहकर्मियों ने भी वीडियोग्राफी की मांग की थी, जिसका मतलब है कि उन्हें भी लगा कि कोई ढका हुआ है- जिस पर पश्चिम बंगाल के वकील ने जवाब दिया, 'हर चीज़ की वीडियोग्राफी की गई है, कोई बदलाव नहीं किया गया है।' मेहता ने कहा (पीड़िता के) पिता एफआईआर दर्ज करने पर जोर देते हैं। अस्पताल एफआईआर दर्ज नहीं कराता है। पिता ने जिद की और एफआईआर दर्ज हुई। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। यह कवर करने का एक प्रयास है। हम अंदर गए पांचवें दिन जांच के लिए, (शेष पृष्ठ 9)

सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद काम पर लौटे डॉक्टर

राजेश कुमार। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कोलकाता बलात्कार और हत्या की घटना पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को काम पर लौटने का निर्देश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके दोबारा काम पर लौटने के बाद कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि न्यायाधीश और डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा सकते क्योंकि वे जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों से निपटते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा, 'न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। क्या हम (न्यायाधीश) अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बैठ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद, एम्स, दिल्ली आरएमएल अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रेजीडेंट डॉक्टरों ने घोषणा की कि वे अपनी 11 दिवसीय हड़ताल वापस ले रहे हैं। रेजीडेंट डॉक्टर्स, ऐसोसिएशन, एम्स नई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम सुप्रीम कोर्ट की अपील और आरजी कार घटना में हस्तक्षेप और डॉक्टरों की सुरक्षा के आश्वासन के बाद ड्यूटी को फिर से शुरू कर रहे हैं। हम अदालत की कार्रवाई की सराहना (शेष पृष्ठ 9)

अल कायदा का माड्यूल ध्वस्त तीन राज्यों से 14 पकड़े गए

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बृहस्पतिवार को झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 11 लोगों को गिरफ्तार करने और तीन अन्य को हिरासत में लेने के बाद अल कायदा से प्रेरित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, राजस्थान के भिवाड़ी से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जब वे हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे थे। उनकी पहचान झारखंड के मूल निवासी हसन अंसारी, इनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारूक और शाहबाज अंसारी के रूप में की गई है। अधिकारी ने कहा, वे पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में रह रहे थे। उनके पकड़े जाने के बाद, झारखंड के रांची से पांच और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी पहचान डॉ. इश्तियाक अहमद, मोतिउर, रिजवान, मुफ्ती रहमतुल्लाह और फैजान के रूप में की गई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों के पुलिस बलों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऑपरेशन चलाया था। दिल्ली पुलिस के एक बयान में कहा गया, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य पुलिस बलों के सहयोग से दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा चलाए गए एक समन्वित, खुफिया आधारित ऑपरेशन में, अल कायदा (एक्यू) से प्रेरित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। आतंकी मॉड्यूल का लक्ष्य देश में 'खिलाफत' घोषित करना था और वह पूरे भारत में आतंकवादी (शेष पृष्ठ 9)

दिल्ली में ऑटो और टैक्सी हड़ताल ने बढ़ाई परेशानी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

ऑटो-टैक्सी चालकों की दो दिवसीय हड़ताल से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के आह्वान पर दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार को चक्का जाम था। शुक्रवार को भी इसका असर देखा जा सकता है। आज हड़ताल की वजह से लोगों को ऑटो-टैक्सी बहुत कम मिली। काफी देर तक प्रयास करने के बाद ऑटो-टैक्सी मिलने के बाद उसके चालकों ने मनमाने किराया वसूला जो यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। अगर आपको को एनसीआर में किसी जरूरी काम से शुक्रवार को जाना हो तो पूरी तैयारी के साथ निकलें अन्यथा ऑटो-टैक्सी चालकों की हड़ताल परेशान कर सकती है। कुछ स्थानों पर टैक्सी चालकों और ऑटोरिक्शा चालकों को धमकाया गया और यात्रियों को उतारने के लिए कहा गया। टैक्सी और ऑटो यूनियनों ने कहा कि अपर्याप्त भुगतान के साथ-साथ एग्रीगेटर्स द्वारा मोटरसाइकिल टैक्सी सेवाएं शुरू किए जाने से उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन (डीएटीटीसीयू) के अध्यक्ष किशन वर्मा ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में 80 प्रतिशत ऑटोरिक्शा और टैक्सियां सड़कों से नदारद हैं। उन्होंने घोषणा की कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

वहीं, एक कैब चालक आदर्श तिवारी ने कहा, कंपनियां हमें हमारी सेवाओं के लिए बहुत कम भुगतान करती हैं। इसके कारण हम अपने वाहनों की किस्त भरने और अन्य खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हैं। हम अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अपने परिवारों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर कैब मिलने में देरी और बुकिंग रद्द होने के बारे में शिकायत की। सोशल मीडिया एक्स पर उपयोगकर्ता प्रशुष ने पोस्ट किया, पिछले 35 मिनट नोएडा में दिल्ली के लिए कैब लेने की कोशिश में गुजार दिए। ओला कैब, उबर इंडिया, रैपिडो बाइक ऐप में क्या समस्या है। मानसी पांडे ने कहा कि हड़ताल में भाग नहीं लेने वाले ऑटोरिक्शा चालकों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं अपने घर से अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी और ईस्ट ऑफ कैलाश के पास एक ऑटो लिया। पहले तो ऑटो मिलना मुश्किल था, लेकिन जब मुझे एक ऑटो मिला, तो चालक ने अधिक किराया मांगा। देरी के कारण मैं अधिक भुगतान करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन कुछ मीटर आगे पहुंचने पर लगभग पांच से 10 लोगों ने ऑटो रोक दिया और हड़ताल का हवाला देकर मुझे बाहर निकलने के लिए कहा। (शेष पृष्ठ 9)

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-नेकां में गठबंधन

मोहित कंधारी। जम्मू

श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के घर पर बैठक करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

पूर्व गठबंधन सहयोगियों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव पूर्व गठबंधन बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव 'एकजुट होकर' लड़ने का फैसला किया। अंतत: समझौते पर हस्ताक्षर करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर स्थित मुख्यधारा की क्षेत्रीय पार्टी द्वारा नई दिल्ली में सत्तारूढ़ सरकार के साथ चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना के बारे में हवा में चल रही सभी अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। गठबंधन सहयोगियों ने चुनाव पूर्व गठबंधन के नियमों और शर्तों के अनुसार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। श्रीनगर में डॉ. फारूक अब्दुल्ला के आवास पर दोनों पक्षों के बीच डील हुई। इस अहम बैठक में उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीनगर के एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के बाद डॉ. अब्दुल्ला के गुपकर रोड स्थित आवास का दौरा किया, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की और चुनाव पूर्व गठबंधन की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक के तुरंत बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन अंतिम है, और आज शाम तक इसे मंजूरी दे दी जाएगी। गठबंधन सही रास्ते पर है और भगवान की कृपा से यह अच्छा चलेगा। यह अंतिम है और आज शाम तक इसे मंजूरी दे दी जाएगी।

नेकां अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस, नेकां और सीपीआई (एम) एकमत हैं और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि गठबंधन के सामूहिक प्रयासों से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल होने और देश की संस्थाओं और इसके धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने वालों को करारा जवाब देने के लिए सभी के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों पार्टियों के नेताओं को यह तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि एनसी घाटी में कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ने को तैयार है और जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितनी सीटें छोड़ने को तैयार है।

इस बीच, श्रीनगर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक में हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की उम्मीद कर रही थी लेकिन चुनावों की घोषणा कर दी गई जो एक कदम आगे है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र बहाल होगा। उन्होंने दोहराया कि आजादी के बाद यह पहली बार है कि किसी राज्य को घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।राहुल ने कहा, मैंने केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यों में परिवर्तित होते हुए सुना और देखा है लेकिन जम्मू-कश्मीर एक अपवाद है। हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में स्पष्ट कर (शेष पृष्ठ 9)

परंपरागत स्वागत

वारसॉ में पोलैंड के अपने समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए

असम ने मुस्लिम विवाह, तलाक कानून पर बिल पेश किया

पायनियर समाचार सेवा। गुवाहाटी

असम सरकार ने बृहस्पतिवार को मुसलमानों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसमें कहा गया कि इसमें समुदाय के नाबालिगों के विवाह की अनुमति देने की गुंजाइश है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम निरसन अध्यादेश 2024 को खत्म करने के लिए विधानसभा में असम निरसन विधेयक, 2024 पेश किया। उन्होंने निरसन विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा, 21 वर्ष (पुरुष के मामले में) और 18 वर्ष (महिला के मामले में) से कम उम्र के इच्छित व्यक्ति के विवाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इसमें शायद ही कोई प्रावधान था और इसने अदालत में भारी मात्रा में मुकदमेबाजी को आकर्षित किया।

मोहन ने कहा, कम उम्र/नाबालिग विवाह के लिए अधिकृत लाइसेंसधारी (मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार) के साथ-साथ नागरिकों द्वारा दुरुपयोग की गुंजाइश है और पार्टियों की सहमति के बिना जबरन विवाह आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था और पंजीकरण तंत्र अनौपचारिक था जिससे मानदंडों के गैर-अनुपालन की काफी गुंजाइश थी। मंत्री ने कहा, यह मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए तत्कालीन असम प्रांत के लिए ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अपनाया गया एक स्वतंत्रता-पूर्व अधिनियम है। बुधवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा (शेष पृष्ठ 9)

त्रिपुरा के बांध से बांग्लादेश में बाढ़ आने की खबर को भारत ने खारिज किया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश में आई उन खबरों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया कि देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने बांध को खोलने के कारण हुई है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि दोनों देशों के बीच आम नदियों में बाढ़ एक साझा समस्या है जिससे दोनों पक्षों के लोगों को परेशानी हो रही है और इसे हल करने के लिए करीबी आपसी सहयोग की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा, हमने बांग्लादेश में यह चिंता व्यक्त होते देखी है कि बांग्लादेश की पूर्वी सीमा पर स्थित जिलों में बाढ़ की वर्तमान स्थिति त्रिपुरा में गुमती नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित डंबूर बांध के फाटक खोलने के कारण उत्पन्न हुई है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। उसने कहा, हम यह बताना चाहेंगे कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गुमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में इस वर्ष की सबसे भारी बारिश हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में बाढ़ मुख्य रूप से बांध के नीचे की ओर इन बड़े जलग्रहण क्षेत्रों के पानी के कारण आई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डंबूर बांध (बांग्लादेश की)सीमा से 120 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह कम ऊंचाई (करीब 30 मीटर) का बांध है, जो बिजली पैदा करता है और वह बिजली ग्रिड में जाती है जिससे बंग्लादेश को भी त्रिपुरा से 40 मेगावाट बिजली मिलती है।

अगरतला के बाहरी इलाके में बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करते त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा।

मंत्रालय ने कहा, करीब 120 किलोमीटर लंबे नदी के रास्ते में अमरपुर, सोनामुरा और सोनामुरा 2 में तीन जल-स्तर निगरानी स्थल हैं। पूरे त्रिपुरा और बांग्लादेश के आसपास के जिलों में 21 अगस्त से भारी बारिश जारी है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अधिक प्रवाह होने पर पानी स्वत: तरीके से छोड़ा जाता है। उसने कहा कि अमरपुर स्टेशन द्विपक्षीय प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसके तहत बांग्लादेश को भारत की ओर से वास्तविक समय में बाढ़ के आंकड़े भेजे जाते हैं। उसने कहा, 21 अगस्त को अपराह्न तीन बजे तक बांग्लादेश को बाढ़ के बढ़ते रुझान को दर्शाने वाले आंकड़े भेजे गए। शाम 6 बजे बाढ़ के कारण बिजली गुल हो गई, जिससे संचार में समस्या आई। मंत्रालय ने कहा, फिर भी, हमने डेटा के तत्काल प्रसारण के लिए बनाए गए अन्य माध्यमों से संचार बनाए रखने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश 54 आम सीमा पार नदियों को साझा करते हैं और नदी-जल सहयोग द्विपक्षीय जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने कहा, हम द्विपक्षीय परामर्श और तकनीकी चर्चाओं के माध्यम से जल संसाधनों और नदी जल प्रबंधन में मुद्दों और आपसी चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अगले दो साल में दो लाख नौजवानों को देंगे सरकारी नौकरी

मुजफ्फरनगर में आयोजित ऋण मेला में शामिल हुए सीएम, 5000 युवाओं को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ मुजफ्फरनगर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार अगले दो साल में दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि पहले नौकरियां निकलती थीं तो पश्चिमी यूपी के युवाओं को उससे वंचित रखा जाता था, मगर आज यहां के युवा और बेटियां नौकरियां प्राप्त कर रही हैं।

सीएम योगी ने कहा कि शुक्रवार से प्रदेश में पुलिसकर्मियों की 60 हजार से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निकलने वाली सरकारी नौकरियों में यहां के युवाओं को बढ़चढ़ कर भाग लेना होगा। कोई माई का लाल युवाओं की योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। उन्होंने आगाह किया कि किसी ने भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे जेल भेजने के साथ ही उसकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों में बांट दिया जाएगा।

सीएम योगी गुरुवार को यहां बीआईटी कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेला में शामिल हुए। इस दौरान 5 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों एवं एमएसएमई उद्यमियों में ?30 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत एक हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जनपदों में हर तीन माह में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर को सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। खासकर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर वही स्थान है, जो 10 साल पहले दंगों की आग में झुलसता था। आज ये दंगामुक्त हो चुका है और यहां धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकलती है। सीएम ने कहा कि यहां की नई पहचान विकास, सुरक्षा, नौजवानों को काम, सरकारी नौकरी के रूप में बन रही है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उनके उस बॉन्ड का क्या हुआ, जिसमें एक लाख रूपए देने के लिए भरवाया गया था। मुख्यमंत्री ने सपा मुखिया को लेकर कहा कि उनके लोग प्रदेश की बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं और वह दुष्कर्मियों के साथ खड़े रहते हैं। सीएम योगी ने इसे सपा का मॉडल बताया। सीएम ने आश्वस्त किया कि बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज करते मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुजफ्फरनगर के 38 मार्गों के लिए यहां के विधायकगणों ने प्रस्ताव दिया है। यहां मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। हमारी सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लाने वाली यूपी की बेटी पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी दी है। प्रदेश के युवाओं की खेल प्रतिभा को आकार देने के लिए मेरठ में प्रदेश का पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा हैं। जब ये बनकर तैयार होगा तो यहां का नौजवान ओलम्पिक में गोल्ड और सिल्वर लेकर आएगा। सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश के 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है और जो भी नौजवान देश के लिए मेडल जीतेगा, यूपी में सरकारी नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी में कोई आना नहीं चाहता था। यहां से लोग भागते थे, कैराना से पलायन हो रहा था। आज यहां से उद्योग भागते नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है।

आज से प्रारंभ होगी अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा

बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को मिलेगी परीक्षा केंद्र में एंट्री

- किए गए कड़े सुरक्षा प्रबंध, हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती, सभी 1174 परीक्षा केंद्रों के बाहर लगाए जाएंगे जैमर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार ने प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए फूलप्रूफ प्लान बनाया है। इसके तहत योगी सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती की 23 अगस्त शुक्रवार से दो पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किये हैं। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है जबकि केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। वहीं सीसीटीवी कैमरों से गहन निगरानी की जाएगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के बाद भी उन्हे परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मालूम हो कि योगी सरकार पुलिस बल को और मजबूती देने के लिए 60,244 पुलिस आरक्षी पदों पर भर्ती कर रही है, जिसकी परीक्षाएं 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को प्रदेश के सभी 67 जनपदों के 1174 सेंटर पर आयोजित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) की अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परीक्षा के लिए विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वहीं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जनपदीय पर्यवेक्षक (मजिस्ट्रेट) के रूप में कार्य करेंगे। उनके द्वारा परीक्षा केन्द्र ड्यूटी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती समेत अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गयी हैं। इसके तहत जिलाधिकारी द्वारा हर सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ सहायक केंद्र पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी (प्रशासन) के रूप में नियुक्त किया गया है जबकि 3 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई है। इतना ही नहीं नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए उड़ान दस्ते भी मुस्तैद रहेंगे। वहीं केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगे। प्रदेश के जिन सेंटर पर एक हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे, वहां पुलिस उपाधीक्षक तैनात रहेंगे। वहीं एक हजार तक अभ्यर्थी वाले सेंटर पर इंस्पेक्टर और पांच सौ तक अभ्यर्थी वाले सेंटर पर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त कर्मियों में से 50 प्रतिशत जिलाधिकारी और शेष 50 प्रतिशत केन्द्र व्यवस्थापक (प्रधानाचार्य) द्वारा नियुक्त किये गये हैं। इनमें परीक्षा सहायक प्रथम एवं द्वितीय जिलाधिकारी और केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा नियुक्त किये जाएंगे जबकि 12 अभ्यर्थियों पर एक अंतरीक्षक को तैनात किया जाएगा। इसके साथ सहयोगी अंतरीक्षक भी तैनात रहेंगे।

परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए, इसके लिए तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की चैकिंग, फ्रिस्किंग एवं पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था की गई है। केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश फिजिकल फ्रिस्किंग, एचएचएमडी द्वारा फ्रिस्किंग, बायोमैट्रिक फिंगर प्रिन्ट एवं फेशियल रिकॉग्निशन के बाद ही दिया जायेगा। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन न होने पर एफआरआईएस कैप्चर करने की भी व्यवस्था की गई है। फेशियल रिकॉग्निशन में संशय होने पर अभ्यर्थी का आधार ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा। इसके अलावा सभी केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक डिवाइसेज जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ को निष्क्रिय करने के लिये जैमर लगाए जाएंगे। परीक्षा कक्ष एवं केन्द्र में सीसीटीवी लगाकर निगरानी की जा रही है।

पायनियर वर्गीकृत

सूचना

सूचित हो मै मो. इदरीश पुत्र मुन्ना नि० 647 वी/आई–पी० एन–01 ए ख. नं. 965 मडियांव। मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में DAKSHRA D/o MODH IDRISH है जो गलत है। सही नाम DARAKSHA D/o IDRISH है। अब से इसी नाम से जाना पहचाना जाय ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे बच्चे सूर्यांश पाल के स्कूल दस्तावेजों में मेरा नाम गलती से कपिल पाल लिख गया है जबकि सही नाम कपिल कुमार पाल है कपिल पाल और कपिल कुमार पाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है सूर्यांश पाल पुत्र कपिल कुमार पाल निवासी 549/279 बड़ा बरहा आलमबाग लखनऊ

सूचना

मूल प्रदेशन पत्र संख्या 1775 दिनांक 21.06.1990 भवन संख्या H-442 सत्यम विहार आ.वि.–1 कल्याणपुर, कानपुर निर्गत नाम श्री जगदीश सिंह यादव कहीं खो गया है – जारीकर्ता सत्यरूपा देवी

सूचना

सूच्य हो कि मेरे इंडियन बैंक के शेयर प्रमाण पत्र में मेरा नाम भानु प्रकाश दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड पर मेरा नाम भानु प्रकाश वर्मा दर्ज है।भानु प्रकाश व भानु प्रकाश वर्मा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो कि मेरे हैं। मुझे इन दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। भानु प्रकाश वर्मा पुत्र गया प्रसाद वर्मा निवासी–म.नं.413/2,माधव नगर, मुंशीगंज,तहसील व जिला–सीतापुर

सूचना

सूच्य हो कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम शिल्पी अग्रवाल दर्ज है जबकि हाईस्कूल प्रमाण पत्र,आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम शिल्पी खेतान दर्ज है।शिल्पी अग्रवाल व शिल्पी खेतान दोनों एक ही महिला के नाम हैं जो कि मेरे हैं। मुझे इन दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। शिल्पी खेतान पुत्री सुनील कुमार अग्रवाल निवासी–101,नई बस्ती,तहसील व जिला–सीतापुर

सूचना

सूच्य हो कि मैंने पुत्र मो.आदिल का चाल–चलन ठीक न होने के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अब से उसके किसी भी कृत्य व लेन–देन से मेरा व मेरे परिवार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहेगा। शाहजहां खातून पत्नी स्व. मो.असलम सिद्दीकी निवासी– म.नं. 473,शेख सरांय पटिया,थाना–कोतवाली नगर, तहसील व जिला–सीतापुर

Required

Required
Adharshila Law College of Professional Courses (ALC)
Raj Nagar NH-232 Raibareli
Posts:- Principal-01 Asst. Professors for L.LB 3 years-03 & B.A. L.LB-5 years Economics-01, English-01, Sociology-01 & Law-04
Eligibility:- Principal 15 years experience in any Law college/University with Ph.D. as per BCI and Lucknow University norms. Asst. Professors 55% in L.LM with NET/Ph.D.
Pay scale:- As per Bar Council Of India / Lucknow University norms. **Contacts:-** 9454855857, 9453848622, 8299214485,
Manager : Chandra Prabha Singh

अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामला

आरोपी के मल्टी कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ अयोध्या

भदरसा कस्बे (अयोध्या) में नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े फरमान के बाद जिला प्रशासन ने घटना के मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि व तालाब पर बनाए गए मल्टी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इससे पहले तहसील प्रशासन की जांच मे आरोपी की बेकरी तालाब की भूमि पर पाए जाने के बाद तहसील प्रशासन ने बेकरी निर्माण इकाई पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त करा दिया था।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इस बिल्डिंग का निर्माण अवैध ढंग से तालाब की जमीन पर और चकरोड की जमीन पर कब्जा करके किया गया था। विकास प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस दी जा चुकी थी। उसके बाद उनके द्वारा मानचित्र नहीं दाखिल किया गया। न तो किसी प्रकार की रुचि ही दिखाई गई। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जून में ही पारित कर दिया गया था। इस आदेश का तामीला कराते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को एक्टिवेट कराया गया है। एसडीएम के द्वारा आगे जांच की जा रही है, आगे भी जो अवैध संपत्ति पाई जाएगी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है।

यूपी में समाजवादी पार्टी ही है भाजपा का एकमात्र विकल्पः अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया अब भविष्य की तैयारी का समय है। देश में भाजपा को रोकने की ताकत समाजवादी पार्टी में ही है। उत्तर प्रदेश में वही एक मात्र विकल्प है। पीडीए ही भाजपा को मात देगा।

अखिलेश यादव गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ के डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के कारण संविधान खतरे में है। वह आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। भविष्य में नई पीढ़ी के लिए काम करना ही होगा। यादव ने कहा कि पीडीए से भाजपा घबराई हुई है। इसलिए वह षडयंत्र करने से बाज नहीं आ सकती है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को बदनाम करने और निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम भाजपा कर रही है। उत्तर प्रदेश का विकास ठप्प है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सत्ता लोलुप भाजपा नई-नई चालें चलती रहेगी। उससे सावधान रहना है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में जनता त्रस्त है। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी से नौजवान परेशान है। भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है। उनकी फसलों को एमएसपी नहीं मिल रही है। उनकी आय दुगनी करने का दावा भी धोखा साबित हुआ है। प्रदेश में पूंजी निवेश के नाम पर हवाई दावे किए गए हैं। प्रदेश में एक भी नया उद्योग या बिजली घर नहीं लगा।

यादव ने आह्वान किया कि प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। भाजपा ने प्रदेश को दशकों पीछे धकेल दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही जीवन में बदलाव आएगा और गांव की तस्वीर में भी परिवर्तन आएगा। यादव ने कहा कि भाजपा जनता के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। सड़कों के गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए हैं। करोड़ों का बजट कहां गया पता नहीं चल रहा है। वृक्षारोपण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा ने पूरी व्यवस्था को तहत नहस कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को और भी ज्यादा मेहनत से जुटे रहना हैं। समाजवादी पार्टी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का समयबद्ध तरीके किया जा रहा भुगतानः जीएस प्रियदर्शी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत कराये गए कार्यों के समयबद्ध मजदूरी भुगतान को लेकर उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में समयबद्ध मजदूरी भुगतान (ज्पउमसल च्ंलउमदज) 96 प्रतिशत पहुंच गया है जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस साल प्रदेश में अब तक मजदूरी भुगतान के लिए 96 प्रतिशत फंड ट्रांसफर आर्डर (एफटीओ) समय-सीमा में जारी किया गये हैं।

उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मुख्यालय स्तर पर मनरेगा की सतत मानीटरिंग की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश ने समयबद्ध मजदूरी भुगतान में निरंतर प्रगति हो रही है। आयुक्त, ग्राम्य विकास जीएस प्रियदर्शी द्वारा बताया गया कि प्रदेश में मांग के अनुसार अधिक से अधिक श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समयबद्ध मजदूरी भुगतान (टाइमली पेमेंट) बीते 5 वर्षों की बात करें, तो मनरेगा अंतर्गत कराये गये कार्यो के समयबद्ध मजदूरी भुगतान को लेकर वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक प्रगति देखने को मिली है।

वर्ष 2019-20 में 85 फीसदी समयबद्ध मजदूरी भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 में 87 फीसदी, वर्ष 2021-22 में 86 फीसदी, वर्ष 202-23 में 80 फीसदी तो, वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 92 फीसदी से ज्यादा का समयबद्ध मजदूरी भुगतान किया गया। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो अब 2024 तक 96.51 फीसदी समयबद्ध मजदूरी भुगतान किया गया।

अडानी के खिलाफ जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

- पुलिस के साथ तीखी नोक-झोंक के बाद नाराज प्रदेश अध्यक्ष राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की प्रमुख माधवी बुच के इस्तीफे और अडाणी समूह से जुड़े मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर गुरुवार को राजधानी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार राय के नेतृत्व में ईडी कार्यालय का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बल पूर्वक रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। जिसके बाद नाराज अजय राय कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।अजय राय ने कहा कि यह बात आइने की तरह साफ हो गई कि अडानी का साम्राज्य केन्द्र सरकार के संरक्षण और सरकारी एजेन्सियों की मिलीभगत के दम पर खड़ा हुआ। इतना ही नहीं तमाम जांच एजेन्सियों का दुरूपयोग कर अड़ानी को कई फायदे पहुंचाये गये। कौड़ियों के भाव बन्दरगाह और एयरपोर्ट दिये गये। अभी हाल ही में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने न सिर्फ एक बार फिर अडानी की काली करतूतों का पर्दा फॉश किया बल्कि सेबी की चेयरमैन और अडानी के मध्य एक भ्रष्ट नेक्सस की पोल भी खोली। दुर्भाग्य यह है कि जिन जांच एजेन्सियों पर अडानी के खिलाफ जांच करने का दारोमदार था वह खुद उस भ्रष्टाचार का हिस्सा थीं। नतीजा अडानी का क्रोनी कैप्टिलिज्म जारी रहा और सरकार उस पर पर्दा डालती रही।

राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के आम जन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार इस अनैतिक गठजोड़ के खिलाफ आवाज उठाती रही। एक बार फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जेपीसी के गठन की मांग की है।

एक लाख का ईनामी कुख्यात अपराधी झारखंड से गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एसटीएफ ने एक लाख के ईनामी कुख्यात अपराधी अंकित यादव निवासी लक्ष्मीकुण्ड, थाना लक्सा, जनपद वाराणसी को झारखंड से गिरफ्तार किया।

एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि जनपद वाराणसी के थाना दशाश्वमेध क्षेत्रान्तर्गत दिन-दहाड़े अंकित यादव द्वारा गैंग के साथियों के साथ मिलकर अपने प्रतिद्वंदी दिनेश यादव के घर पर चढ़कर जान मारने की नियत से अन्धाधुन्ध फायरिंग की गयी थी। जिसमें दिनेश यादव सहित कुल 3 लोग गोली लगने से बुरी तरह से घायल हो गये। मौके पर दहशत का माहौल पैदा हो गया था। इस संबंध में थाना दशाश्वमेध, वाराणसी पर अंकित यादव और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके कई साथियों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मुख्य अभियुक्त अंकित यादव घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसपर जनपद वाराणसी पुलिस द्वारा एक का पुरस्कार घोषित किया गया था। विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि अंकित यादव झारखंड के पाकुर जिले में है। इसके बाद एक टीम वहां भेजी गई। जिसने मुहल्ला अन्नपूर्णानगर कॉलोनी के पास से अंकित यादव को गिरफ्तार कर थाना पाकुर जनपद पाकुर(झारखंड) में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ से पाया गया कि वह एक मनबढ किस्म का दबंग अपराधी है। इसका अपने क्षेत्र के कुछ मनबढ़ किस्म के लड़को का एक गैंग बनाया है। यह गैंग आस-पास को लोगों से वसूली आदि का काम करता है। आस-पास के लोगों में इसका इतना भय है कि लोग इसकी शिकायत पुलिस से करने में डरते थे। इसके विरुद्ध मारपीट आदि के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त को थाना पाकुर नगर कोतवाली (झारखंड) में दाखिल कर न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

यूपी में और बढ़ेगा अनाजों की रानी मक्के का जलवा

- अगले तीन साल में उत्पादन दोगुना करने का प्रदेश सरकार का लक्ष्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में मक्के का उत्पादन 2027 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तय अवधि में इसे बढ़ाकर 27.30 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। इसके लिए रकबा बढ़ाने के साथ प्रति हेक्टेयर प्रति कुंतल उत्पादन बढ़ाने पर भी बराबर का जोर होगा।इसके लिए योगी सरकार ने 'त्वरित मक्का विकास योजना' शुरू की है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023/2024 में 27.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अभी प्रदेश में करीब 8.30 लाख हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है। कुल उत्पादन करीब 21.16 लाख मिट्रिक है। प्रदेश सरकार की मदद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संबद्ध भारतीय मक्का संस्थान भी कर रहा है। धान और गेंहू के बाद यह खाद्यान्न की तीसरी प्रमुख फसल है। उपज और रकबा बढाकर 2027 तक इसकी उपज दोगुना करने के लक्ष्य के पीछे मक्के का बहुपयोगी होना है। अब तो एथनॉल के रूप में भविष्य में इसकी संभावनाएं और बढ़ गई हैं।

बात चाहे पोषक तत्वों की हो या उपयोगिता की। बेहतर उपज की बात करें या सहफसली खेती या औद्योगिक प्रयोग की। हर मौसम (रबी, खरीफ एवं जायद) और जलनिकासी के प्रबंधन वाली हर तरह की भूमि में होने वाले मक्के का जवाब नहीं। मालूम हो कि मक्के का प्रयोग ग्रेन बेस्ड इथेनॉल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों,कुक्कुट एवं पशुओं के पोषाहार,दवा, कास्मेटिक, गोद, वस्त्र, पेपर और एल्कोहल इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा मक्के कोआटा, धोकला, बेबी कार्न और पाप कार्न के रूप में तो ये खाया ही जाता है। किसी न किसी रूप में ये हर सूप का अनिवार्य हिस्सा है। ये सभी क्षेत्र संभावनाओं वाले हैं।

आने वाले समय में बहुपयोगी होने की वजह से मक्के की मांग भी बढ़ेगी। इस बढ़ी मांग का अधिक्तम लाभ प्रदेश के किसानों को हो इसके लिए सरकार मक्के की खेती के प्रति किसानों को लगातार जागरूक कर रही है। उनको खेती के उन्नत तौर तरीकों की जानकारी देने के साथ सीड रिप्लेसमेंट (बीज प्रतिस्थापन) की दर को भी बढ़ा रही है।

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **अमित अग्रवाल प्रोपराइटर सुमित प्लास्टिक ट्रेडर्स, सुमित कुमार अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, अरविंद कुमार अग्रवाल और रचित कुमार अग्रवाल** को **07.05.2024** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HLAPBRL00205327** की राशि रू.**56,46,212.07 (रूपये छप्पन लाख छियालीस हजार दो सौ बारह और सात पैसे मात्र)** और **06.05.2024** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **21.08.2024**. को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.**56,46,212.07 (रूपये छप्पन लाख छियालीस हजार दो सौ बारह और सात पैसे मात्र) 06.05.2024** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

पुरानी संपत्ति के मकान का नं. 134 के सभी भाग और खंड, नई संपत्ति नं.108, माप 123.37 स्क्वे..मीटर्स (पूर्व में 50 फीट, पश्चिम में 47.6 फीट, उत्तर में 27 फीट और दक्षिण में 27.6 फीट), जुल्फिकार गंज में स्थित, बरेली - 243001, उत्तर प्रदेश और जिसकी सीमा निम्नानुसार है:-

पूर्व : सेठ गिरधारी लाल की संपत्ति | पश्चिम : सेठ गिरधारी लाल की संपत्ति
उत्तर : सड़क | दक्षिण : सेठ गिरधारी लाल की संपत्ति

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

दिनांक : **21.08.2024**
स्थान : **बरेली**

राज्य और केन्द्र की योजनाओं का लाभ समय पर लाभार्थियों को मिले

राज्यपाल की अध्यक्षता में राजभवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, की अध्यक्षता में गुरुवार को राजभवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान, जनपद अयोध्या में आंगनबाड़ी केंद्रों की नवीन स्वीकृति विषयक कार्यवाही की अद्यतन स्थिति, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित महिला एवं बाल विकास विभाग की समस्त योजनाओं समीक्षा की गई। जिसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों को कायाकल्पित करने हेतु विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली धनराशि तथा उसके उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गयी।

राज्यपाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। राज्यपाल ने किशोरियों के लिए पोषणयुक्त आहार की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आंगनबाड़ी केंद्रों का निरंतर सरप्राइज विजिट करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकार की योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वित हो रही हैं। राज्यपाल ने विभाग को नियमित रूप से मंत्रियों के साथ बैठकें करने का निर्देश भी दिये, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर चर्चा की जा सके और उनका समाधान निकाला जा सके। उन्होंने जिलों में सीडीपीओ, सुपरवाइजर और कार्यकत्रियों की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी समाज और मानव विकास का मुख्य केंद्र हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का समुचित विकास हो। जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे, दूसरों को निर्देश नहीं दे सकते। हमें अपनी ड्यूटी के साथ-साथ समाज कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। संस्थागत डिलीवरी पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अभी भी कुछ प्रतिशत डिलीवरी अस्पताल में नहीं हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस समस्या के कारणों का विश्लेषण करें और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में गोद भराई कार्यक्रम के दौरान सगर्भा माताओं के सामने देशभक्ति, शहीदों की कहानी या धार्मिक कथाओं का वर्णन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के दौरान संगीत भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी संस्कार मिल सके। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति के समय उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कहते हुए राज्यपाल ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी में सभी गतिविधियां कैलेंडर के अनुसार और नियमित रूप से संचालित की जाएं। राज्यपाल ने जनपद अयोध्या में नए आंगनबाड़ी केंद्रों के शीघ्र निर्माण और उन्हें समय पर आवश्यक किट प्रदान करने पर भी जोर दिया। उन्होंने विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूल, मंदिर, पंचायत घर, खेलकूद का मैदान और बाजार का भ्रमण कराते रहना चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। बैठक में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल के सुझावों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग नियमित बैठकें करेगा और आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास, पोषणयुक्त आहार की उपलब्धता, और बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देगा। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले।

श्रवण साहू हत्याकांड

अकील अंसारी समेत आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

- सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों पर ठोका लाखों रुपए का जुर्माना

लखनऊ। विधि संवाददाता

राजधानी के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड मामले में गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने अकील अंसारी समेत आठ आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष जज राहुल प्रकाश ने आरोपी सत्यम पटेल व अमन सिंह पर अलग अलग दो लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है। इन्हें हत्या, हत्या की साजिश, सबूत मिटाने व इसकी साजिश रचने का दोषी करार दिया है। जबकि आरोपी अकील अंसारी, विवेक वर्मा, बाबू खान, फैसल, अजय पटेल व रोहित मिश्रा को हत्या व सबूत मिटाने की साजिश का दोषी माना है। उन्होंने इन सभी पर अलग अलग एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

यह है मामला

एक फरवरी, 2017 को राजधानी के सआदतगंज इलाके में श्रवण साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात की रिपोर्ट उनके पुत्र सुनीत साहू ने दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक उसके पिता बड़ा चौराहा दाल मंडी में अपनी तेल की दुकान पर बैठे थे। रात साढ़े आठ बजे मोटरसाइकिल सवार दो लड़के दुकान पर आए। उन्होंने आते ही जान से मारने की नियत से पिताजी पर कई फायर किए। वो लहूलुहान होकर गिर पड़े। उसके दोनो चाचा और अन्य लोगों के चिल्लाने पर हमलावर भाग गए। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग दुकान बंद कर भागने लगे। इतने में पुलिस आई। पिताजी को ट्रामा सेंटर ले गई। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

श्रवण साहू अपने पुत्र आयुष की हत्या के अहम गवाह थे

वर्ष 2013 में 16 अक्तूबर को श्रवण साहू के पुत्र आयुष साहू की हत्या कर दी गई थी। श्रवण साहू अपने पुत्र की हत्या के इस मामले में अहम गवाह थे और जोर शोर से उसके मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। आयूष की हत्या में अकील अंसारी नामजद था। श्रवण साहू हत्याकांड मामले में भी उसका नाम सामने आया। लेकिन वह पहले से जेल में था। पुलिस ने उसके खिलाफ श्रवण साहू की हत्या की साजिश रचने तथा सबूत मिटाने की साजिश का आरोप पाया। बाद में पुलिस ने इस चर्चित हत्याकांड मामले का पर्दाफाश करते हुए अन्य अभियुक्त अमन सिंह, सत्यम पटेल, अजय पटेल, विवेक वर्मा व रोहित मिश्रा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 16 फरवरी, 2017 को पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रिवाल्वर व खोखा भी बरामद किया।

हाईकोर्ट ने हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी

20 मार्च, 2017 को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में पुलिसवालों की मिलीभगत सामने आने पर इस हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। नौ मई, 2017 को सीबीआई ने अपनी जांच के बाद इन्हीं अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 व 120 बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। बाद में विवेचना के दौरान अभियुक्त फैसल उर्फ बबलू व बाबू खां का भी नाम सामने आने पर इनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया।

69000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने निदेशालय पर किया प्रदर्शन, संवैधानिक संरक्षण की मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

69000 शिक्षक भर्ती के चयनित सामान्य वर्ग के सैकड़ों शिक्षकों ने नौकरी बचाने के लिए गुरुवार को निशातगंज स्थित शिक्षा निदशालय में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि चार साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों को न छेड़ा जाए। सरकार उन्हें नौकरी में सुरक्षित बने रखने का फॉर्मूला बताए। यदि शिक्षक इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने से पहले सभी पक्षों को अच्छे से देख ले और नौकरी पा चुके किसी एक भी शिक्षक का अहित न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए।

69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत नौकरी पा चुके शिक्षक एक दिन की छुट्टी लेकर आज निदेशालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इन शिक्षकों का कहना था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं। उनका प्रदर्शन अपनी नौकरी बचाने के लिए है। प्रदर्शन में शामिल शिक्षक डॉक्टर धीरज चांदनी ने कहा कि यहां जितने भी शिक्षक आए हैं, वह सरकार से संवैधानिक संरक्षण की मांग कर रहे है। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जो नई मेरिट जारी करने की बात कही है। उस पर रोक लगाने की मांग शामिल है।

उन्होंने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती में 19000 की धांधली की सूची किसने बनाया।

नौकरी पा चुके शिक्षकों ने पूछा पीड़ित कौन

नौकरी पा चुके शिक्षकों ने प्रदर्शन के दौरान अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आरक्षण के मुद्दे पर ही सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया को सही बताते हुए कहा कि 69000 भर्ती प्रक्रिया में आखिर पीड़ित कौन है? प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के हाथ में जो पोस्ट थे,उसमें लिखा था कि 69000 शिक्षक भर्ती में अनारक्षित वर्ग की 34589 सीटें है। जिस पर सामान नियुक्ति 20310, अन्य पिछड़ा वर्ग 13007, अनुसूचित वर्ग 1753 और अनुसूचित जनजाति के 24 अभ्यर्थी नियुक्ति उपाय है। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल सामान्य अभ्यर्थियों की जनसंख्या 29फीसद, पिछड़ा वर्ग की 45फीसद व एससी-एसटी वर्ग के 26फीसद है। इस तरह से 71फीसद सीटों पर आरक्षित वर्ग को नियुक्ति मिला है, फिर ऐसे में आरक्षण घोटाला कैसे हुआ?

दोनों गुटों ने आमने-सामने किया प्रदर्शन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6800 अभ्यर्थी बीते तीन दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं गुरुवार को नौकरी पा चुके शिक्षकों का अच्छा भी प्रदर्शन करने पहुंच गए। ऐसे में बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर का माहौल काफी तनाव पूर्ण हो गया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने जहां योगी आदित्यनाथ का पोस्टर हाथ में लेकर कम से संरक्षण के गुहार लगा रहे थे तो वही 6800 अभ्यर्थी आरक्षण के मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपना दल एस नेता व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित अपने समाज के नेताओं की पोस्टर लगाकर नारेबाजी कर रहे थे। दोनों गुटों के एक साथ प्रदर्शन करने की सूचना पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते शकुंतला में लगेंगी ऑनलाइन कक्षाएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के शुक्रवार से शुरू होने के चलते परीक्षा केन्द्र बने शिक्षण संस्थान 23,24,25 व 30 व 31 अगस्त को बंद रहेंगे। ऐसे में डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय प्रशासन नें छुट्टियों के दौरान सभी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सम सेमेस्टर की मौखिक परीक्षा के लिए अलग स्थान का चयन किया गया है।

पुलिस भर्ती को लेकर पुनर्वास विश्वविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। परीक्षा के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसलिए विश्वविद्यालय ने 31 अगस्त तक शैक्षिक गतिविधियों के लिए छुट्टी कर दी गई है। इस संबंध में कुलसचिव ने आदेश भी जारी कर दिया है। कुलसचिव रोहित सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय अधिकतर कक्षाएं एकेडमिक ब्लॉक ए-1 और ए-2 में होती हैं। लिहाजा इन ब्लॉक्स में होने वाली कक्षाएं 31 अगस्त तक ऑनलाइन होंगी। किसी को ऑनलाइन कक्षा करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह अपने विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर सकता है। पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. यशवंत वीरदोय ने बताया कि एकेडमिक ब्लॉक ए-1 और ए-2 में सम सेमेस्टर की मौखिक परीक्षाएं भी होनी थीं। इन परीक्षाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अब यह परीक्षाएं कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र में कराई जाएंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास स्थित अटल ऑडोटोरियम की लॉबी के दोनों ओर शैक्षणिक ब्लॉक ए-1 और ए-2 के परीक्षार्थियों और परीक्षा में लगे स्टाफ के लिए बैग, मोबाइल व अन्य सामान रखने की व्यवस्था की गई है।

महिला स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा को लेकर केजीएमयू में टास्क फोर्स का गठन

- विभागों को विश्राम कक्ष सहित शौचालय के सुदृढ़ीकरण के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोलकाता में रेजीडेंट डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद देश भर के डॉक्टरों में गुस्से को देखते हुए महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही विभागों को महिला विश्राम कक्ष और शौचालयों को सुदृढ़ कराने के निर्देश दिये गये हैं।

विवि के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह के मुताबिक कलकत्ता में रेजीडेन्ट डाक्टर की हत्या के बाद, केजीएमयू द्वारा हर विभाग में महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु समीक्षा की जा रही थी। साथ ही प्रत्येक विभाग में इनके लिये विश्राम कक्ष व शौचालय की व्यवस्था करने, तथा पूर्व में बने विश्राम कक्ष व शौचालयों को सुदृढ़ करने हेतु आडिट किया जा रहा था, जो बुधवार को पूरा हो गया। आज कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विभाग में इनके लिये विश्राम कक्ष व शौचालय की व्यवस्था करने, तथा पूर्व में बने विश्राम कक्ष व शौचालयों को सुदृढ़ करने का कार्य तत्काल प्रभाव/ शुक्रवार से प्रारम्भ कर दिया जाय।

बैठक में मुख्य चिकत्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। जो चिकित्सा विश्वविद्यालय की महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं हेतु प्रयास करेगी तथा प्रत्येक विभाग में इनके लिये विश्राम कक्ष व शौचालय की व्यवस्था करने, तथा पूर्व में बने विश्राम कक्ष व शौचालयों को सुदृढ़ करने के कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन सुनिश्चित करेगी। इस टास्क फोर्स में अधिकतर महिला चिकित्सकों को शामिल किया गया है।

स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने घेरा डिप्टी सीएम का आवास

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर तैनात कर्मचारियों ने गुरुवार को स्थायी नौकरी की मांग को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के आवास का घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड महामारी में उन लोगों ने जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की। अब उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। कहीं समायोजित भी नहीं किया जा रहा है।

स्थायी नियुक्ति की मांग के समर्थन में संविदा स्वास्थ्य कमर्चारी गुरुवार सुबह करीब आठ बजे डिप्टी सीएम के आवास के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। संविदा कर्मचारियों के साथ ही एनएचएम के 17 हजार संविदा भर्ती वेटिंग को लेकर भी अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे और घेराव किया। डिप्टी सीएम के आवास के बाहर जाने के बाद ही इन कर्मचारियों को करीब पौने 12 बजे पुलिस बसों में भरकर ईको गार्डेन पार्क ले जाया गया। आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों ने बताया कि नौकरी से निकाले जाने के बाद वह लोग यहां करीब 15 बार आ चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। कर्मचारियों ने बताया कि नौकरी जाने से वह लोग बेरोजगार हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

शोध मेधा, छात्र कल्याण और कर्मयोगी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तिथि बढ़ी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुरुवार को शोध मेधा, छात्र कल्याण और कर्मयोगी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी पांच सितम्बर तक इन तीनों ही छात्रवृति के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीएसडब्ल्यू प्रो. वीके शर्मा ने बताया कि शोध मेधा, छात्र कल्याण और कर्मयोगी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। कई विद्यार्थी किन्हीं कारणों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके थे,उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की थी। लिहाजा तीनों ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब पांच सितम्बर तक छात्रों को ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी डीएसडब्ल्यू ऑफिस में जमा करना होगा।

केजीएमयू ट्रामा सेंटर के सीएमएस बने डा. प्रेम राज

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस डॉ. संदीप तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। डॉ. संदीप तिवारी ने इस्तीफा देने का कारण व्यक्तिगत बताया है। वह ट्रॉमा सर्जरी विभाग के अध्यक्ष हैं। इस पद पर वह बने रहेंगे। डॉ. संदीप के इस्तीफे के बाद कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने डॉ. प्रेमराज सिंह को नया सीएमएस नियुक्त किया। इससे पूर्व डॉ. सिंह ट्रामा सेंटर के अतिरिक्त सीएमएस के पद पर तैनात थे। बता दें कि एक दिन पहले मीडिया सेल के इंचार्ज डॉ. संतोष कुमार को हटाकर सर्जरी विभाग के डॉ. केके सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी।

मलेरिया विभाग में तैनात इंस्पेक्टर को हटाने के निर्देश

लखनऊ। नगर विकास मंत्री सहित अन्य विधायकों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मलेरिया विभाग में तैनात एक इंस्पेक्टर को उप्र शासन के उप सचिव अवनींद्र कुमार शुक्ल ने हटाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शिकायती पत्र का हवाला देते हुए तत्काल आरोपित को मुख्यालय से हटाकर दूसरे जनपद ट्रांसफर करने और जांच करने को कहा है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि बिना पद के लंबे समय से राज्य मलेरिया मुख्यालय में इंस्पेक्टर समीउल्ला खान तैनात हैं। गलत तरीके से वेतन आहरित किया जा रहा है। इनके खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार समेत तमाम आरोप सिद्ध हो चुके हैं। पूर्व डीजी हेल्थ डॉ. दीपा त्यागी ने भी मलेरिया इंस्पेक्टर को हटाने के लिए शासन को पत्र लिखा था। वहीं अपर निदेशक मलेरिया डॉ. सईद अहमद का कहना है कि अभी मुझे शासन के पत्र की जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की पूर्व संध्या पर बीबीएयू में कार्यक्रम

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में गुरुवार को गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय की ओर से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस-2024 की पूर्व संध्या पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए पोस्टर मेकिंग, प्रश्नोत्तरी एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन समिति में चेयरपर्सन एवं पुस्तकालय अध्यक्ष डॉ. सुनील गोरिया, कम्प्यूटर साइंस विभाग की डॉ. शालिनी चन्द्रा, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की डॉ. राजश्री एवं व्यावसायिक सहायक अमित कुमार वर्मा उपस्थित रहें। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने विचारों को पोस्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के दौरान अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न तथ्यों से जुड़े प्रश्न पूछे गये। इसके अतिरिक्त निबंध प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने भारत में अंतरिक्ष शोध में इसरो का योगदान विषय पर अपने विचारों को व्यक्त किया।

दवा सेवन कर फाइलेरिया उन्मूलन में करें सहयोग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सर्वजन दवा सेवन अभियान शुरू हुए पांच दिन बीत चुके हैं और इन पांच दिनों में 2.84 करोड़ लोगों ने फ़ाइलेरियारोधी दवा का सेवन किया है। इसके तहत लक्षित आबादी को सप्ताह में चार दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर-घर जाकर फ़ाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जा रही है।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी, फ़ाइलेरिया डा.ए.के.चौधरी ने बताया कि 10 अगस्त से दो सितम्बर तक चलने वाले एमडीए/आईडीए अभियान के दौरान 7.69 करोड़ लोगों को फ़ाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष अभी तक कुल 2.84 करोड़ लोगों को फ़ाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जा चुकी है। कानपुर देहात, कौशाम्बी और औरैया में अच्छी-खासी संख्या में लोगों ने दवा का सेवन किया। कानपुर में 44 फीसद, कौशाम्बी में 41 और औरैया में 40 फीसद लोगों ने अब तक फ़ाइलेरियारोधी दवा का सेवन किया है। बता दें कि कुछ लोग दवा को लेकर भ्रम में हैं कि वह दवा क्यों खाएं जब उनको कोई रोग नहीं है । उनको यह जानना जरुरी है कि फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है और संक्रमण होने के पांच से 15 साल बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं। तब तक लसिका तंत्र खराब हो जाता है और न चाहते हुये भी जीवन उसी स्थिति में जीने को मजबूर होते हैं। जबकि यदि साल में एक बार और लगातार पांच साल तक फ़ाइलेरियारोधी दवा का सेवन कर लेते हैं तो इस लाइलाज बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभियान तभी सफल होगा जब कम से कम 90 फीसद आबादी फाइलेरियारोधी दवा का सेवन करे।

संस्थान में लाभप्रद जानकारी व बेहतर शैक्षणिक वातावरण देना हमारी प्राथमिकता: डॉ. जीके गोस्वामी

- यूपीएसआईएफएस के नवारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय 'नवारंभ 2024-25' कार्यक्रम के दूसरे दिन के विशेष व्याख्यान सत्र में आमंत्रित विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों ने नवागंतुक छात्रों को उनके विषयों से संबंधित लाभप्रद जानकारियां साझा किया। इस अवसर पर संस्थापक निदेशक डॉ' जीके गोस्वामी गोस्वामी ने बताया कि 'नवारंभ 2024-25' कार्यक्रम के जरिए नवागंतुक छात्र-छात्राओं को संस्थान में उनके विषयों से संबंधित लाभप्रद जानकारी एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण देना हमारी प्राथमिकता है ताकि नवागंतुक छात्र अपने लक्ष्य को सफलता से हासिल कर सके।

इस अवसर पर निदेशक डॉ. गोस्वामी ने संस्थान में आये समस्त वक्तागण अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम मे अपर निदेशक राजीव मलहोत्रा, उपनिदेशक चिरन्जीव मुखर्जी, प्रशासनिक अधिकारी अतुल यादव, सहायक रजिस्ट्रार डॉ. अजिता, डॉ. सीएम सिंह, डॉ. विवेक, जन संपर्क अधिकारी संतोष तिवारी, प्रतिसार निरीक्षक बृजेश सिंह सहित संस्थान के शैक्षणिक संवर्ग के संकाय डॉ सौरभ सिंह, डॉ. अरूण खत्री, डा. सपना, डॉ. अजीत कुमार, डॉ. आशीष राज, डॉ. सपना शर्मा डॉ. पोरवी, डॉ. रोशन ,डॉ. अभिषेक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान अतिथि प्रवक्ता डॉ. एसके जैन निदेशक फोरेंसिक विज्ञान विभाग दिल्ली ने छात्रों को बताया कि फारेन्सिक विषयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर व्यक्ति की आवाज में अनोखापन होता है अगर कोई अपराधी आवाज बदल कर अपनी पहचान छिपाना चाहता है तो अब वायस इस्पेक्टोग्राफी टेक्नोलोजी के माध्यम से उसकी पहचान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में सुक्ष्म मात्रा मे ही साक्ष्य मिलते है लेकिन अब फोरेंसिक साइंस के माध्यम से उन केसों को भी सुलझाया जा सकता है।

इस अवसर पर अतिथि वक्ता डॉ. जी खान अपर निदेशक राज्य चिकित्सा विधि प्रकोष्ठ ने छात्रों को जुरिप्रुडेन्स मेडिको लीगल एन्ड जनरल टाक्सिकोलोजी से संबंधित विषयों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जुरिप्रुडेन्स मेडिको लीगल एन्ड जनरल टाक्सिकोलोजी का फोरेंसिक साइंस में क्या महत्व है को भी बताया। उन्होंने कहा कि बायलाजिकल साक्ष्य संकलन अपराध के अनुसंधान में अति महत्वपूर्ण है । अतिथि वक्ता डॉ. शिवपूजन एडवाईजर वायोटेक पार्क लखनऊ ने छात्रों बताया कि फारेन्सिक साइन्स में उद्यमिता की बहुत बड़ी संभावनायें हैं और नई तकनीकी को कैसे उपयोग में लायें जो फारेंसिक साइन्स को और अधिक बढावा दे सकता है। अतिथि वक्ता डॉ अरुण मोहन शेरी निदेशक ट्रिपल आईटी लखनऊ ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी की प्रकरणों में हम तकनीकी का कैसे इस्तेमाल करेंद्य उन्होंने कम्युनिकेशन को आसान भाषा में समझाया। अतिथि वक्ता डॉ उपेंद्र गिरी ने रियल लाइफ में टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करें इस विषय पर प्रकाश डाला साथ ही श्री रोहित नेगी ने साइबर सिक्योरिटी के विषयों को छात्रों से अपने अनुभव साझा किया।

अतिथि वक्ता डॉ अमित कुमार निदेशक बायोएक्सिस डीएनए रिसर्च सेंटर हैदराबाद ने बताया कि फोरेंसिक डीएनए तकनीक ने भारतीय न्याय व्यवस्था में एक नई क्रांति ला दी है। इस तकनीक के माध्यम से अपराधों की जांच और सुलझाने में अत्यधिक सटीकता और तेजी आई है। उन्होंने ने कहा कि डीएनए तकनीक की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मानक और परीक्षण बेहद जरूरी हैं। अतिथि वक्ता डॉ अरविंद चतुर्वेदी आईपीएस ने इस अवसर पर वाइल्डलाइफ एनिमल पर छात्र-छात्राओं को विशेष जानकारी प्रदान की।

महिला संबंधी अपराधों पर शत प्रतिशत लगाएं अंकुश: योगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ सहारनपुर

सहारनपुर की मंडलीय समीक्षा में बोले सीएम, जनता से सरकारी योजनाओं का फीड बैक लेकर सीएम कार्यालय को कराएं उपलब्ध

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सहारनपुर में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री गुरुवार को पूर्वाह्न पुलिस लाइन पहुंचे। यहां हेलीपैड पर उनका स्वागत जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। सीएम योगी ने सबसे पहले पुलिस लाइन में मंत्री, विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जनता और प्रशासन के साथ आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये। इसके बाद सीएम सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

बैठक में सीएम ने जनप्रनिधियों से सरकार की ओर से लागू योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने जनता और प्रशासन के साथ आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान उन्हे कोई समस्या आती है तो वह इसकी जानकारी दें। उसका समाधान कराया जाएगा। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से जनता के बीच अधिक से अधिक समय बिताने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वह जनता से सरकार की योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं के विषय में फीड बैक प्राप्त करें। उन्होंने इस फीड बैक को मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं सीएम के साथ साझा की। इस पर सीएम ने उसके निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में जल्द ही प्रभारी मंत्री की नियुक्ति की जाएगी, जो उनकी समस्याओं को सुनने के साथ उसका समाधान करेंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वह अगली बार सहारनपुर में रात्रि विश्राम भी करेंगे और जनता से संवाद भी करेंगे। समीक्षा बैठक में मंत्री बृजेश सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, जशवंत सैनी, विधायक राजीव गुंबर, देवेंद्र निम, मुकेश चौधरी और किरत चौधरी आदि उपस्थित थे।

सीएम योगी ने सर्किट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिये। साथ ही विकास कार्य को ससमय गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नगर निगम की सुविधाओं को बेहतर करने और जनता से फीड बैक लेने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने राजस्व वादों का निस्तारण, मुकदमा, पैमाइश की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष व 5 वर्ष से अधिक लम्बित मुकदमों का निस्तारण समयबद्धता के साथ मेरिट के आधार पर किया जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही है, अन्यथा की स्थिति में संबंधित की जवाबदेही तय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जनता की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। साथ ही अधिकारी जनसुनवाई के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें और गंभीरता से जनता की समस्या का निस्तारण करें। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। पीड़ित की तरफ से एफआईआर दर्ज करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए निर्देशित किया कि भीड़ वाले स्थानों पर वर्दी में तथा बिना वर्दी में पुलिस की तैनाती की जाए। उन्होंने निरंतर पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आगामी त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं, इसको लेकर पहले से योजना तैयार कर ली जाए। महिला पुलिस बीट अधिकारी और सिपाही नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में भ्रमण करें।

सभी विद्यार्थियों को विधायिका की संरचना व कार्य प्रणाली को करीब से जानना चाहिए: महाना

अयोध्या से आए छात्र-छात्राओं के बड़े दल ने किया विधानसभा का भ्रमण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधानसभा के आकर्षक ढांचे, आधुनिक, भव्य स्वरूप और उन्नत सुविधाओं ने इसे देशभर में एक मिसाल बना दिया है। यही कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, विद्यार्थी हों, या फिर सामान्य नागरिक, इसका भ्रमण करने आ रहे हैं। जहां विधानसभा के इतिहास, निर्माण, और कार्यप्रणाली के बारे में जानने के लिए लोग आ रहे हैं, वहीं विधानसभा एक पर्यटन स्थल के रूप में भी उभर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को अयोध्या के प्रतिष्ठित एल.एस.डी.पी. पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं के एक बड़े दल ने विधानसभा देखने के बाद कहा कि इतनी खूबसूरत और आकर्षक विधानसभा के बारे में कभी सोचा नही था, न तो हमे विधानसभा के गौरवमयी इतिहास के बारे में पता था और न ही यहां की इतनी बड़ी लाइब्रेरी के बारे में।

विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने छात्र-छात्राओं को सदन की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि जब सदन की कार्यवाही चलती है तो इसके सदस्य उस दौरान शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य विकास समेत अन्य मुद्दों को उठाते है। इसके बाद संबन्धित कमेटियां अपनी संस्तुति शासन के पास भेजती है। फिर इनका क्रियान्वयन कर का जनसमयाओं का निदान किया जाता है। सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष अपनी बात और विपक्ष अपनी बात कहता है लेकिन दोनों पक्ष जनहित की ही बात करते है। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा को सुंदर बनाने के पीछे यही कारण है कि आम जनता इसके बारे में जाने और उसे समझने का काम करे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि, सभी विद्यार्थियों को विधायिका की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली को करीब से जानना चाहिए। ये आने वाले समय में उन्हें मदद करेगी। विधायिका, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विधायिका की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने से उन्हे आगे इसका लाभ मिलेगा। महाना ने छात्र-छात्राओं को बताया कि जीवन की एक गलती आपकी सारी अच्छाइयों को खत्म कर सकती है। इसलिए सोच समझकर जीवन में अपने कदम आगे बढ़ाए। मोबाइल पर सेल्फी खराब आने पर उसे डिलीट कर फिर से नई फोटों को खींचा जा सकता है लेकिन व्यक्तिगत जीवन की गलती को डिलीट नही किया जा सकता हैं। उन्होंने कहा कि आज की आवश्यकता बेटियों को सशक्त बनाने की है, हांलाकि वह इस दिशा में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी और सशक्त होने की जरूरत है। बेटियों का सशक्तिकरण ही हमारे समाज को मजबूत बनाएगा। विद्यालय के प्रबंधक अनिल पाठक और प्रधानाचार्य आदित्य पाठक ने विधानसभा भ्रमण की अनुमति देने के लिए मोमेंटो व अंग वस्त्र देकर विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इस दौरान बालिकाओं ने विधानसभा अध्यक्ष को राखी भी बाँधी। विधानसभा भ्रमण के दौरान बच्चे काफी खुश और सेल्फी लेते हुए दिखे।इस दौरान उपप्रधानाचार्य आर. बी सिंह,आदित्य शर्मा, सलोनी सिंह, अंजली शुक्ला, रंजीत शर्मा, प्रवीण गिरी, कृष्णा तिवारी सहित अन्य अध्यापक उपस्थित रहे।

प्रदेश को जीरो पावर्टी वाला राज्य बनाने का लक्ष्य

घुमंतू समुदाय को सरकारी सुविधाओं से जोड़ रही सरकार

कलंदरखेड़ा में झुग्गी बनाकर रहने वाले घुमंतू समुदाय के परिवारों को मिलेंगी सभी सरकारी सुविधाएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश को देश का जीरो पावर्टी वाला राज्य बनाने के लिए सभी वंचित एवं गरीब तबके को तेजी के साथ सरकारी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसमें घुमंतू समुदाय भी शामिल है, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घूम-घूमकर जीवन यापन करते हैं। इसी क्रम में सरकार ने लखनऊ के कलंदरखेड़ा में झुग्गी बनाकर निवास करने वाले घुमंतू समुदाय के परिवारों को जल्द ही बिजली, पानी, आवास आदि मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से घुमंतू समुदाय को प्रधानमंत्री आवास, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

सरकार की इस मुहिम के तहत, प्रदेश के गरीब एवं वंचित तबके को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी मिलकर उन्हें सभी आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार के निर्णय से घुमंतू समुदाय के नागरिक काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि सभी सरकारी सुविधाएं प्राप्त होने से उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने अधिकारियों के साथ कलंदरखेड़ा बस्ती का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को आश्वस्त किया कि सरकार सभी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ जल्द प्रदान करेगी, ताकि सभी परिवार बेहतर जीवन यापन कर सकें। साथ ही प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जीरो पावर्टी के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। असीम अरुण ने कुछ दिनों पहले इस बस्ती का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को कैंप लगाकर यहां रहने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया था। इस अवसर पर कलंदरखेडा में देश के कई राज्यों से आए घुमंतू जाति के नागरिकों ने मंत्री असीम अरुण से मुलाकात भी की थी और समुदाय की बेहतरी के लिए घुमंतू आयोग बनाने की मांग की थी। इस मौके पर असीम अरुण ने बताया कि यहां समाज कल्याण सहित दूसरे कई विभाग के अधिकारी कैंप लगाकर पिछले कई दिनों से सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए नागरिकों को चिन्हित किया जा रहा है। दो सप्ताह पूर्व निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने असीम अरुण को बताया था कि यहां 200 परिवार करीब 90 वर्षों से झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। इन परिवारों के पास न तो पीने का साफ पानी उपलब्ध है और न ही बिजली। नगर निगम नागरिकों को टैंकर से साफ पेयजल उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही, बिजली की पहुंच के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। मालूम हो कि रेनके आयोग (2008) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 1,500 घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू जनजातियां और 198 विमुक्त जनजातियां हैं, जिनमें तकरीबन 15 करोड़ लोग शामिल हैं। देश के कई हिस्सों में ये जनजातियां अब भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

हाईकोर्ट ने संजय सिंह के सजा के आदेश पर लगाई रोक

लखनऊ (विसं)। वर्ष 2001 में सुल्तानपुर जिले में सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर की एक अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई तीन माह की सजा पर रोक लगा दी है। पीठ ने कहा है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध जमावड़ा और सदोष अवरोध का अपराध गठित करने का तथ्य नहीं हैं। पीठ ने इसके साथ ही संजय सिंह की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब कर लिया है। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने यह आदेश संजय सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। इनकी ओर से वरिष्ठ वकील सतीश चन्द्र मिश्रा ने बहस की। उनका कहना था कि वर्ष 2001 में निचली अदालत द्वारा संजय सिंह को दोषसिद्ध करार देते हुए तीन माह की सजा सुनाई। जिसके विरुद्ध उन्होंने अपील दाखिल की थी। सत्र अदालत द्वारा उनकी अपील खारिज कर दी गई। कहा गया कि अभियोजन की ओर से पेश गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है। यह भी कहा गया कि अभियोजन के एक गवाह ने याचिकाकर्ता को पहचानने से इंकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान इस याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया।

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक व कई अन्य कांग्रेस में शामिल

लखनऊ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नीतियों एवं उसकी विचारधारा से प्रेरित होकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष निषाद पार्टी एवं युवा कश्यप सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम कश्यप, मण्डल सचिव निषाद पार्टी सोनाराम कश्यप, जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर हरबिलेन्द्र सरदार कश्यप, समाजसेवी सलेख कश्यप ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के समक्ष कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर राय ने सभी लोगों के गले में तिरंगा पट्टिका पहनाकर पार्टी का सदस्यता कार्ड देकर पार्टी में विधिवत रूप से पार्टी में शामिल कराया। इसी क्रम में आज पूर्व सैनिक विभाग के वाइस चेयरमैन सुभाष मिश्र एवं दीपक भट्ट के संयुक्त नेतृत्व में जनपद प्रतापगढ़, बेरली, मऊ, रामपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से आये विनीत कुमार, अजय पाठक, रिहान वली खां, मो. उबैद खान, प्रदीप कुमार, फरहान, अंसार हुसैन, साबिर अली नियाजी, नाज़िम हुसैन, जुबैर खान, जय चन्द्र शंखवार, विजय कुमार पाल, राजकुमार यादव, हिर मोहन श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार, राम पूजन पटेल, अमरेश कुमार गौतम, फूल चन्द्र यादव, राज कुमार पाल, विवेक कुमार, राम अभिलाष, आदि ने भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कर्मचारी यूनियन का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

लखनऊ। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कर्मचारी यूनियन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री राकेश सचान उपस्थित रहे। उनके द्वारा नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में बोर्ड के संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी सिद्धार्थ यादव और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। यह शपथ ग्रहण समारोह बोर्ड कर्मचारी यूनियन के 15 जुलाई 2024 को सम्पन्न हुए चुनावों के उपरांत आयोजित किया गया। इस चुनाव में कमलेश कुमार वर्मा को अध्यक्ष, हरिगेंद मौर्य को महामंत्री, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव और राजेन्द्र कुमार कश्यप को उपाध्यक्ष, राजकुमार को मंत्री, हरिकरन सिंह को संगठन मंत्री, लक्ष्मी नारायण तिवारी को कोषाध्यक्ष और सुधर सिंह को प्रचार मंत्री चुना गया था।

सिंगल विंडो प्लेटफार्म ने यूपी में निवेशकों की राह बनाई आसान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

निवेश मित्र पोर्टल ने 15.40 लाख से अधिक आवेदनों को सफलता पूर्वक किया निस्तारित

उत्तर प्रदेश को देश को 'इकोनॉमिक पावर हाउस' बनाने में जुटी योगी सरकार ने तकनीक को अपना प्रमुख हथियार बनाया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल निभा रहा है। इस पोर्टल ने उत्तर प्रदेश में निवेश के इच्छुक निवेशकों एवं उद्यमियों की भागदौड़ को समाप्त कर दिया है। इसी का परिणाम है कि निवेश मित्र पोर्टल ने एनओसी/लाइसेंस के 15.40 लाख से अधिक आवेदनों को सफलतापूर्वक निस्तारित किया है।

सीएम योगी का कहना है कि आज का समय उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि किसी प्रदेश में उद्योग के लिए आवश्यक बेहतरीन कानून व्यवस्था, पर्याप्त लैंड बैंक, 96 लाख एमएसएमई इकाइयां और सस्ता श्रम आज देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। ये बड़े निवेश के बैकबोन हैं। वहीं जब हम इसमें तकनीक को जोड़ते हैं तो प्रदेश में निवेश के इच्छुक निवेशकों की राह और आसान हो जाती है। निवेशकों को एनओसी/लाइसेंस के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगती है। इसी का परिणाम है कि 8 लाख से अधिक उद्यमियों ने निवेश मित्र पोर्टल के विषय में संतुष्टि का फीडबैक दिया है। इस पोर्टल पर अब तक 10 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। योगी सरकार का यह सिंगल विंडो सिस्टम पर 42 से अधिक विभागों की 491 से अधिक लाइसेंस संबंधी सेवाएं उपलब्ध हैं। विगत 6 वर्षों में इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्यमियों की तरफ से एनओसी/लाइसेंस के लिए 15.90 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं, जिसमें से पोर्टल द्वारा 97 प्रतिशत आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल आज देश का सबसे अधिक सेवा देने वाला सिंगल विंडो का प्लेटफार्म बन गया है। इसके माध्यम से एमओयू मॉनिटरिंग और इंसेंटिव वितरण की प्रकिया भी सरल हुई है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश, देश में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट बन गया है।

2016 तक ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में जो उत्तर प्रदेश देश में 16वें स्थान पर था, आज दूसरे स्थान पर है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को सहूलियत प्रदान करने और उनकी समस्याओं के ससमय निस्तारण के लिए कटिबद्ध है। इसके माध्यम से निवेशकों की जिज्ञासाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है।

भारत बंद की सफलता दलित एकजुटता प्रतीक: फतेह बहादुर

अलग-अलग होने के बाद भी एससी/एसटी के आधिकारों की लड़ाई में एक साथ आए सामाजिक संगठन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सामाजिक संस्था बहुजन भारत के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस कुंवर फतेह बहादुर ने भारत बंद की सफलता पर सभी संगठनों को बधाई देते हुए कहा कि दलितों में एक देशव्यापी आंबेडकरवादी चेतना से लैस, जुझारु, साहसी और निडर अगुवा वर्ग विकसित हो गया है। यह अगुवा वर्ग मुख्य रूप से नौजवानों से बना है। जिसे कमोबेश अपने दोस्त-दुश्मन की पहचान है। ऐसे अगुवा लोगों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। दलित समुदाय अपने मुद्दों पर संघर्ष के लिए किसी एक पार्टी और व्यक्ति का मोहताज नहीं रहा गया है। उसके बीच एक सामूहिक नेतृत्व विकसित हो रहा है। जो राजनीतिक पटल पर भले ही उतना मुखर नहीं दिखता हो, लेकिन वैचारिक-सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत मुखर है। संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि भले ही दलित समाज में लाखों संगठन हों, आपस में उनके कुछ मतभेद भी हों, लेकिन जब सवाल दलितों के सामूहिक हितों का आता है, तो सब एकजुट हो जाते हैं। एक स्वर में बोलते हैं। दलितों को देशव्यापी स्तर एक सूत्र में बांधने वाला भले ही कोई एक संगठन या मंच न हो, लेकिन वैचारिक तौर पर (आंबेडकरवादी वैचारिकी) सब एक कमोबेश एक सूत्र में बंधे हुए हैं।

कुंवर फतेह बहादुर ने कहा कि आर्थिक तौर आज भी दलित समाज भले ही भारत का सबसे कमजोर तबका हो, लेकिन सामाजिक-वैचारिक तौर पर भारत का सबसे सशक्त सामाजिक समूह है। दलितों के भीतर अपनी स्थिति को लेकर गहरा असंतोष और तीव्र आक्रोश है, जिसकी अभिव्यक्ति समय-समय पर होती रहती है। इस भारत बंद में भी दिख रही है। भले ही यह भारत बंद किसी एक संगठन के दिशा निर्देश में नहीं हो रहा है लेकिन इसका असर कमोबेश पूरी तरह संगठित और अनुशासित होना यह बता रहा है कि दलित समाज अपनी भीतरी लोकतांत्रिक-संवैधानिक चेतना के चलते, स्वयं को लोकतांत्रिक तरीके से अभिव्यक्ति करने में सक्षम और सफल रहा है और भारत बंद को अधिकांश दलित-आदिवासी और पिछड़ों का, मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों का समर्थन इस बात का सबूत है कि ये पार्टियां दलितों के मुख्य सरोकारों से खुद को अब अलग-थलग नहीं रख सकती हैं। नहीं तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

वन्यजीवों को बचाने के लिए राजधानी के 250 विद्यार्थी जनजागरूकता फैलाएंगे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पर्यटन विभाग ने ईको टूरिज्म के माध्यम से उप्र की जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए छात्र-छात्राओं को जागरूक करने की एक अनोखी पहल की है। इस क्रम में लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 बच्चों द्वारा दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व समेत अन्य महत्वपूर्ण ईको पर्यटन स्थलों पर आधारित आर्ट एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता कराई जा रही है। यह छात्र आर्ट एण्ड क्राफ्ट के माध्यम से बतायेंगे कि कैसे वन्य जीवों को संरक्षित रखा जा सकता है। इसके तहत ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 विद्यार्थियों को 25 अगस्त, 2024 को आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जायेगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए अच्छी शुरुआत है। विद्यार्थी आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से बताएंगे कि कैसे वन्य जीवों को बचाया जाए और प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। उप्र विविधताओं से भरा राज्य है। पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है। यहां 16 हजार 582 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र के साथ अनेक अति सुंदर परिदृश्य, नदियां, सुंदर झरने हैं। लुप्तप्राय पक्षियों और वन्य जीवों की उपलब्धता है। जयवीर सिंह ने बताया कि उप्र पर्यटन विभाग का प्रयास है कि, देश-दुनिया से जो भी पर्यटक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वे आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों के साथ नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लें। प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिताएं। यहां के सुंदरतम स्थल अवश्य ही पर्यटकों/आगंतुकों के तन-मन को आनंद प्रदान करेगी।

रेजीडेंट डॉक्टर्स ने आंदोलन लिया वापस, विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधेगे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में मेडिकल छात्रा के साथ घटित घटना के विरोध में पिछले दस दिनों से चला आ रहा जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन गुरुवार को समाप्त हो गया। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टरों ने केन्द्रीय संरक्षण कानून के संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं होने पर ड्यूटी के दौरान काला फीता बांध कर विरोध दर्ज करायेंगे। कोलकाता में हुई घटना की जांच सीबीआई कर रही है और कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। ऐसे में आज केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि संरक्षण कानून बनाने की दिशा में अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं होने से वे काला फीता बांध कर ड्यूटी करेंगे।

केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को मिलेगी सूखे से निजात

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

ढाई लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित बनाने में जुटी प्रदेश सरकार

दशकों तक उपेक्षा का दंश झेल चुके बुंदेलखंड को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और यहां समृद्धि की राह प्रशस्त करने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र को सूखा मुक्त करने के अपने संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में केन-बेतवा लिंक परियोजना के जरिए अब सरकार बुंदेलखंड में ढाई लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित करने की कवायद में जुट गई है। इस परियोजना को मूर्त रूप देने के बाद जहां महोबा, झांसी और ललितपुर में हजारों हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित की जा सकेगी, वहीं बांदा में करीब दो लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाया जा सकेगा। योगी सरकार इसके अलावा बांदा और पैलानी में केन नदी पर दो नये बैराज भी बना रही है। इतना ही नहीं 100 साल से अधिक पुराने बरियापुर पिकअप वियर और पारीक्षा वियर तथा 300 साल से भी पुराने बरुआ सागर बांध के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के प्रयास भी तेज हो गए हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से आगे बढ़ रही है। 221 किमी लंबी केन बेतवा लिंक परियोजना में उत्तर प्रदेश में 21 किमी के लिंक चैनल का निर्माण होना है, जिसके लिए 271 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है। इस बहुउद्देशीय परियोजना को 2030 तक पूरा किया जाना है। वर्तमान में केन नहर प्रणाली द्वारा बांदा में 87 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित है। योगी सरकार इसे बढ़ाकर बांदा में ही करीब दो लाख हेक्टेयर करने की तैयारी में है। इसके अलावा महोबा में 37 हजार हेक्टेयर से अधिक, झांसी में 17 हजार हेक्टेयर से अधिक और ललितपुर में 3 हजार हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त भूमि को सिंचित बनाने का लक्ष्य है। वहीं बांदा में 1.66 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य भी योगी सरकार कराने जा रही है, जिस पर 1191.51 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2024 में शुरू करके मार्च 2028 तक पूरा करना है।

ऐसे ही महोबा में 510 करोड़ रुपए की लागत से 15 बांध और बड़े तालाबों के जीर्णोद्धार और केन बेतवा लिंक नहर से इनके भराव का प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहा है। ये प्रोजेक्ट जून 2025 से शुरू होगा, जिसे मार्च 2028 तक पूरा करना है। वहीं केन नदी पर दो नये बैराज बांदा और पैलानी में बनाये जाएंगे। करीब दो हजार करोड़ की लागत वाला यह प्रोजेक्ट अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा, जिसे जून 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। इसके साथ ही योगी सरकार बुंदेलखंड के बरियापुर पिकअप वियर, पारीक्षा वियर और बरुआ सागर बांद का भी जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कराने जा रही है। बरियापुर वियर का निर्माण 1906 में हुआ था, जबकि पारीक्षा वियर को 1910 में बनाया गया था। वहीं झांसी में बरुआ सागर बांध का निर्माण सन 1700 में हुआ था। अब सरकार इन तीनों का जीर्णोद्धार और पुनर्निमाण कराने जा रही है। इसके लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को डीपीआर बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके ई-टेंडर का कार्य फरवरी 2025 से शुरू होगा, जबकि अप्रैल 2025 से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इन तीनों प्रोजेक्ट को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर जताया विरोध

के पी कॉलेज से सुभाष चौराहे तक हिन्दू संगठनों ने निकाली विशाल आक्रोश रैली

संवाददाता। प्रयागराज

बांग्लादेश में हिंदुओं पर सामूहिक रूप से की जा रही लक्षित हिंसा एवं दमन चक्र से क्षुब्ध हजारों हिन्दुओं ने आज सड़क पर निकल कर हिंदू रक्षा समिति के तत्वावधान में आक्रोश रैली निकाली। वक्ताओं ने हिंसा तत्काल रोकने एवं हिंदुओं को पूर्ण सुरक्षा देने की जोरदार मांग की। सुभाष चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका तथा हिंदू रक्षा के जोरदार नारे लगाए। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष कवींद्र प्रताप सिंह ने भारत सरकार से मांग की है की कूटनीतिक उपाय के अलावा हिंदुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर सेना का उपयोग करें।

जबकि कुछ संतों ने मांग की है कि सीमाएं खोल दी जाएं संत एवं हिंदू समाज मिलकर अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करेंगे। बूंदाबांदी के बीच केपी ग्राउंड से गुरुवार को आक्रोश रैली की शुरुआत हुई। विहिप के काशी प्रांत अध्यक्ष के पी सिंह उपाध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल विहिप के संगठन मंत्री नितिन आदि की अगुवाई में हजारों हिंदू हाथों में तिरंगा एवं केसरिया ध्वज लिए बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान के जोरदार नारों के साथ एमजी रोड से सिविल लाइन की ओर आगे बढ़े। हाथों में वी वांट जस्टिस हिंदुओं को भी जीने का अधिकार है आदि नारे लिखी तख्तियों को हाथों में पकड़े हिंदुओं का यह समूह मेडिकल चौराहे से सी ए वी कॉलेज के सामने से हनुमान मंदिर चौराहे पर पहुंचे।

चौराहे पर मूर्ति के समक्ष आतंकवाद का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शिक्षक व्यापारी छात्र तथा महिलाएं शामिल रहीं। चौराहे पर क्षुब्ध युवकों ने हिंदू का अपमान हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर तथा हिंदू एकता जिंदाबाद वंदे मातरम जय श्री राम के जोरदार नारे रैली में शामिल अपने आक्रोश का प्रगटीकरण किया। सुभाष चौराहे पर संपन्न हुई विशाल जनसभा में विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के अध्यक्ष कवींद्र प्रताप सिंह ने संपूर्ण हिंदू समाज का आह्वान किया कि वह जेहादी तत्वों के खिलाफ आगे आएं। अन्यथा हिंदुस्तान में भी शांति के साथ हिंदुओं का रहना दूभर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह जुल्म ढाए जा रहे हैं। उसे हम अब मौन होकर नहीं सहेंगे। उसके खिलाफ हिंदुओं का संघर्ष जारी रहेगा। सभी हिंदू भाई भाई है कोई भी ताकत हमें जाति पंथ मत में नहीं बांट सकती।

मंच से उन्होंने हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है का उद्घोष किया। इस पर सभी ने तालियां बजाकर अपना समर्थन जताया। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि हिंदुओं को कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत के कुछ राजनीतिक दलों की चुप्पी की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे दलों को लगता है सांप सूंघ गया है।

भारत में बांग्लादेश की घटना को दोहराए जाने की आशंका जताने वाले नेताओं को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोग शांति के पुजारी हैं लेकिन कोई हमारी शांति व्यवस्था में खलल डालेगा तो हम माकूल जवाब देंगे। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार को रोकने के लिए कूटनीतिक उपाय के साथ जरूरत पड़ने पर सेना का उपयोग करें तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से हस्तक्षेप करने का आग्रह करें।

राजस्व वसूली लक्ष्य पूरा न करने वालों की तय होगी जिम्मेदारीः जिलाधिकारी

संवाददाता। सोनभद्र

जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यक्रमों व कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान वसूली के लक्ष्य को पूरा करने, तहसील स्तरों पर बकायेदारों पर वसूली की कार्यवाही करने, आर0सी0 का नियमित मिलान करने के साथ ही सरकारी जमीनों को सुरक्षित करते हुए जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि लक्ष्य को पूरा न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जायेगी।

राजस्व वसूली व प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही व राजस्व वसूली में शिथिलता बरती जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर अधिकारी को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दियें। इस दौरान जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रवर्तन की कार्यवाही में खानापूर्ति का कार्य न करें, जिम्मेदारी के साथ प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये और रोस्टर के अनुसार अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जाये। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध मदिरा के बिक्री पर प्रतिबन्ध और दुकानों पर छापेमारी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये और लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने कहा कि तहसीलों का काम समयबद्ध और बेहतर तरीके से करने के लिए कड़ाई के साथ उप जिलाधिकारी व तहसीलदार राजस्व कार्मिकों से दायित्वबोध के साथ पेश आयें और जरूरत पड़ने पर उचित कदम भी उठायें। उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाये, जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाये, किसी भी हाल में जनता के साथ अन्याय न होने पायें।

भूमि सम्बन्धित विवादों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित की जाये, नगर पालिका व नगर पंचायत अपने कार्य क्षेत्रों में सुधार लायें, नगर क्षेत्रों में विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही अतिक्रमण मुक्त पर ध्यान रखें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0रा0 सहदेव कुमार मिश्र अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुभाष चन्द्र यादव, उप जिलाधिकारी घोरावल राजेश सिंह, उप जिलाधिकारी दुद्धी सुरेश राय एसडीएम सदर आदि मौजूद रहे।

ओबरा की खदानों को लेकर एनजीटी सख्त, रिपोर्ट तलब

सोनभद्र। हैवी ब्लास्टिंग से घरों की दरकती दीवारों, शिक्षण संस्थाओं पर मडराते खतरा और फराटिक लेवल की गहरी खदानों पर एनजीटी ने ऋतिशा गोड की याचिका पर मेसर्स राधे राधे समेत चार खदानों को नोटिस जारी किया है। उक्त जानकारी देते हुए अधिवक्ता अभिषेक चौबे नें बताया कि 2019 के एक मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के आबादी से निश्चित दूरी के बाद ही ब्लास्टिंग करने की अनुमति देता है परंतु बिल्ली मारकुंडी में इसका खुला उल्लंघन हो रहा है खदानें इतनी गहरी है कि खदानो मे वाटर लेवल के नीचे तक पानी निकाल कर खनन हो रहा है जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है।

इस मामजले में याची ऋतिशा ने बताया कि मेसर्स राधे-राधे इंटरप्राइजेज मेसर्स कृष्णा माइनिग साई बाबा स्टोन कामख्या स्टोन की खदान पूर्ण रूप से मानक के विपरीत चल रही है और भूमिगत जल स्रोत से भी नीचे जा कर लगातार भारी मशीनों से पानी निकाल कर निष्प्रयोजन बहाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में वाटर लेवल नीचे जा रहा है एक दिन ऐसा होगा कि लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। उन्होंने बताया कि खदानें आवासीय, सार्वजनिक स्थानों के बेहद नजदीक है जिसमें हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है घरों के दीवारें टूट रही हैं आईटीआई, डिग्री कॉलेज जहां बच्चे पढ़ते हैं कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

प्राकृतिक जल स्रोत के नाले जो सोन नदी की सहायक थी उसे अब बिल्कुल नष्ट ही कर दिया गया है। बगैर नदी को बचाएं जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है इसलिए पर्यावरण संतुलन और जीवन सुरक्षा के लिए यह संघर्ष जरूरी है अगली सुनवाई में और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किये जाएंगे।

बांग्लादेश की घटना से आहत हिन्दू रक्षा समिति ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

संवाददाता। गाजीपुर

हिन्दुओं के महा जन आक्रोश मार्च हिन्दु समाज के लिए बांग्लादेश सहित पुरे विश्व में हिन्दुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उददेश्य से गुरूवार को राजकीय होम्योपैथक कालेज गुरूबाग रौजा से रैली निकाली गयी, जो ओवरब्रिज विशेष्वगंज होते हुए महुआबाग, ओपियम फैक्ट्री होते हुए कचहरी स्थित सरयू पाण्डेय पार्क मे आकर सभा में तब्दील हो गयी। जिसमें व्यक्ता के रूप में सच्चिदानन्द राय, अधिवक्ता रणजीत सिंह, गायत्री शक्तिपीठ के सुरेन्द्र नाथ सिंह, आदित्य प्रकाश आर्य समाज, दिनेश चन्द्र पाण्डेय विश्व हिन्दु परिषद ने कहा कि बांग्लादेश में हर जिले में यह वीभत्स कुकृत्य होने की सूचना है कटटरपंथियो के निशाने पर शमशान तक नही बचे हैं। मंदिरों को भारी क्षति पहुचाई गयी है। निरंतर अंतराल पर होने वाले ऐसे दंगों का ही परिणाम है कि बांग्लादेश में हिन्दु जो विभाजन के समय 32 प्रतिशत से घटकर अब 8 प्रतिशत से भी कम बचे हैं और वे भी लगातार जिहादी उत्पीड़न के शिकार हैं।

देश की सरकार से हर सम्भव कदम उठाने की मांग करती है। वर्तमान में बांग्लादेश राजनैतिक षड़यत्र और अराजकता की दौर से गुजर रहा है जिसमें वहां रहने वाले निर्दोष अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर धर्माधता के कारण अमानवीय अत्याचार किये जा रहे है। हिन्दुओ की सम्पत्ति को लूटा जा रहा है हिन्दु महिलाओं पर घिनौने अत्याचार किये जाने रहे है। उनकी आबरू लूटकर हत्या की जा रही है, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिन्दुओं के घरो व दुकानो को आग के हवाल किया जा रहा है। वहा के शासन प्रशासन द्वारा हिन्दुओ की कोई सुरक्षा प्रदान नही की जा रही है। वहां की कानून व्यवस्था बिल्कुल निष्प्रभावी व शून्य हो गयी है।

ऐसे में हिन्दु वहां एक लावारिस कौम की तरह अपने जीवन भीख मुस्लिम जेहादियों से मांग रहे हैं। बंगलादेश मे इस समय हिन्दुओ की स्थिति बेजान लाश की तरह हो गयी है और उनकी सुरक्षा के लिए विश्व की कोई सरकार किसी भी प्रकार का कोई कदम नही उठा रही है। ऐसी परिस्थिति में भारत का हिन्दु समाज मुख दर्शक बना नही रहेगा। अपने हिन्दु भाई बहनों की सुरक्षा के लिए हम सभी हर सम्भव प्रयास करेंगे। बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वहा शान्ति एवं सौहार्द कायम रखने हेतु भारत सरकार व अन्य सरकारों से अपेक्षा है। हिन्दु हमेशा शान्ति प्रिय रहा है हिन्दु विश्व में जहा भी अल्पसंख्यक हैं अपने मेहनत के दम पर वहां महत्वपूर्ण योगदान करते है और हमारे हिन्दू समुदाय को अपने भाईयो की सुरक्षा के लिए सजग व सर्तक रहना होगा।

आज गाजीपुर के सभी हिन्दु संगठन जिसमें व्यापारिक, सामाजिक व धार्मिक संगठनो द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिन्दुओ प्रति अत्याचार के विरूद्ध जनाक्रोष मार्च किया गया। आज हम भारत सरकार को इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते है कि बांग्लादेश के साथ साथ विश्व के हिन्दू समुदाय की सहायता व सुरक्षा के लिए जो आवश्यक कदम हो अतिशीघ्र उठाकर प्रभावी कार्यवाही करे। जिससे हिन्दु समाज की सुरक्षा हो सके। महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य को सम्बोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सदर प्रखर उत्तम को सरयू पाण्डेय पार्क में दिया गया।

महिला मंडल ने किया चार्जबल टॉर्च का वितरण

सोनभद्र। दिशिता महिला मंडल रेणुसागर सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहा है इसी कड़ी में दिशिता महिला मंडल द्वारा सामाजिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कुलडोमरी ग्राम पंचायत के ग्राम बियहवा में कार्यक्रम का आयोजन कर 101 ग्रामीणों का चयन करके उन्हे चार्जबल टॉर्च वितरित किया गया। इस अवसर पर दिशिता महिला मंडल की अध्यक्षा इन्दू सिंह ग्राम बियहवा में अपनी टीम के साथ उपस्थित होकर ग्रामीणों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यो से ही जरूरतमन्दो का सहयोग किया जा सकता है भविष्य में भी अलग-अलग योजनाओं का क्रियान्यवयन कर ग्रामीणो को सहयोग किया जायेगा।

दोना, पत्तल व कुल्हड़ को महाकुंभ में देंगे बढ़ावा: एडीएम

●पालिथीन के दोने, पत्तल, गिलास और अन्य उत्पादों पर लगेगा प्रतिबंध

संवाददाता। प्रयागराज

तीर्थराज प्रयागराज के संगम की धरती पर जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ को प्रदेश की योगी सरकार और महाकुम्भ के मेलाधिकारी विजय किरन आनंद ने प्लास्टिक फ्री घोषित किया है। कुंभ मेले में प्लास्टिक और थर्माकोल का प्रयोग बंद कर दोना पत्तल और मिट्टी के बने बर्तनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्लास्टिक के गिलास और थर्माकोल की प्लेटों के बजाय दोने पत्तल और कुल्हड़ को बढ़ावा देने के लिए माघ मेले और महाकुंभ में सबसे बड़ा भंडारा चलने वाली संस्था लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति आश्रम के गुरुदेव और शिव सेना की प्रदेश सचिव रूचि अभिषेक तिवारी आगे आई हैं। मेला प्रशासन ने भी संस्था की इस मुहिम को मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले को योगी सरकार प्लास्टिक फ्री और ग्रीन कुंभ के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है।

प्लास्टिक फ्री घोषित करने के लिए मेला क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ऐसे में महाकुंभ मेले में पॉलिथीन के साथ ही साथ थर्माकोल की प्लेटों और प्लास्टिक के गिलास के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए मेला प्रशासन ने दोना पत्तल और मिट्टी के बर्तन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ओम नमः शिवाय के गुरुदेव महाकुंभ में दो दर्जन प्रमुख स्थानों पर दिन रात विशाल भंडारा चलने वाली सबसे संस्था लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति आश्रम आगे आई है। इसके लिए यमुनापार के मेजा इलाके में दोना पत्तल बनाने वाले मुसहर और कुम्हार समाज के लोगों से संपर्क किया गया है। उनसे ज्यादा से ज्यादा दोना पत्तल और कुल्हड़ बनाने की अपील की गई है।

मेजा के जेवनिया क्षेत्र की पूर्व प्रधान और शिव सेना की प्रदेश सचिव रुचि अभिषेक तिवारी के प्रयासों से मुसहर और कुम्हार समाज के लोगों को दोने पत्तल और मिट्टी के बर्तनों से महाकुंभ में रोजगार देने की पहल की गई है। महाकुंभ में दोना पत्तल और मिट्टी के बर्तन उपलब्ध कराने वाले मुसहर और कुम्हारों को बाबा ओम नमः शिवाय ने माला पहनाकर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। ओम नमः शिवाय के गुरुदेव ने कहा कि महाकुंभ मेले में लगभग दर्जन भर स्थानों पर भंडारा चलता है। जहां पर वह दोना पत्तल में और कुल्हड़ में श्रद्धालुओं को भोजन कराएंगे। उन्होंने कहा है कि मुसहर और कुम्हार लोग जितना भी दोना पत्तल बनाएंगे उसे वह खरीदेंगे। मेले में दोना पत्तल और कुल्हड़ का प्रयोग करने से जहां मेला प्रदूषण मुक्त होगा। वहीं समाज के वंचित लोगों को रोजगार मिलने से उनकी आर्थिक उन्नति भी होगी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य स्वामी कौशल्या नंद गिरी टीना मां ने इस मुहिम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि किन्नर अखाड़ा भी अपने शिविर में दोने पत्तल और कुल्हड़ के प्रयोग को बढ़ावा देगा। महाकुम्भ के दौरान प्लास्टिक के दोना पत्तल और प्लास्टिक के गिलास का प्रयोग किन्नर अखाड़ा में नहीं किया जाएगा। महाकुम्भ के अपर मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद का कहना है कि सरकार ने मेले को प्लास्टिक फ्री घोषित किया है। इस दिशा में मेला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा है कि ओम नमः शिवाय के पूज्य गुरुदेव की ओर से वनवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेले में दोना पत्तल और कुल्हड़ को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल कॉलेज सभागार में पूर्व में एक कार्यशाला भी आयोजित हो चुकी है।

22 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

संवाददाता। सोनभद्र

उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के आवाहन पर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट एवं तहसील में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

जिलाध्यक्ष राजीव कुमार शुक्ला ने कहा कि 22 सूत्रीय मांगों में कलेक्ट्रेट कार्यालय को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कार्मिकों का वेतन उच्चिकृत करने, कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2011 पूर्वत लागू करने, लेखा का कार्य संपादित करने वाले पटल सहायकों को लेखा संवर्ग का वेतनमान दिए जाने, नवसृजित जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नवसृजित तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किए जाने, भूलेख लिपिक का पद पूर्व की भांति कलेक्ट्रेट में वापस किए जाने, सामयिक सहायक वालिस वाकी नसीबों को रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन किए जाने आदि प्रकरणों में विभाग अध्यक्ष व अध्यक्ष परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संस्तुति हो जाने के बाद भी शासनादेश निर्गत न करने से कर्मचारियों में कुंठा व्याप्त है। शासन द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पदोन्नति का शासनादेश तों निर्गत किया जाता है।

किंतु सेवा नियमावली की व्यवस्था के तहत प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति हेतु अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित किए जाने लिपिक संपर्क कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति किए जाने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने जैसी तमाम मांगे अनावश्यक रूप से लंबित है शासन का सबका साथ सबका विकास का नारा कर्मचारियों के प्रति खोखला साबित हो रहा है।

प्रशासनिक अधिकारी रामलाल अमरनाथ, शिव मूरत भीमराव, ओमकार यादव ने कहा कि यदि 17 सितंबर तक मांगे पूरी नहीं होगी तो 18 सितंबर को लखनऊ में पूरे प्रदेश के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। धरने में सुरेश पाठक, श्री राम गिरी, उमानाथ पांडे, भगवान सिंह, रमेश कुमार श्रीवास्तव, अमूल्य वर्मा, अतुल मालवीय, विमल श्रीवास्तव, अशफाक अहमद समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया।

बाइक सवार बदमाशों ने स्टेशन मास्टर को गोली मार किया घायल

मुग़लसराय, चन्दौली। मुगलसराय कोतवाली के औद्योगिक नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत हमीदपुर गांव के समीप बाइक सवार बदमाशों ने स्टेशन मास्टर को गोली मार दी । घटना के वक्त वह अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे । इस दौरान गोली स्टेशन मास्टर के कमर में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर गए । घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पीड़ित से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस गिरफ्तारी के लिए जगह - जगह दबिश दे रही है ।

मिली जानकारी के अनुसार जीवनथपुर में स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात 58 वर्षीय वीरेंद्र वर्मा नारायणपुर बाजार में रहते हैं। हर रोज की भांति बुधवार की रात ड्यूटी समाप्ति कर वापस घर लौट रहे थे । जैसे ही वह हमीदपुर गांव के पास पहुंचे की पीछे से आगे आकर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी । इस दौरान गोली उनके कमर में लगी । जिससे वह वहीं मौके पर गिर गए । घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी । सूचना के बाद एडिशनल एसपी विनय प्रकाश सिंह , सीओ पीडीडीयू नगर आशुतोष , मुगलसराय कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए । घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।

कोतवाल विजय बहादुर सिंह ने इस बाबत पूछे जाने पर जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि स्टेशन मास्टर का नारायणपुर के ही रहने वाले राजेश नाम के अवैध वेंडर से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान उसने वीरेंद्र वर्मा को धमकी दी थी । पीड़ित की तहरीर पर राजेश व अन्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच की जा रही है।

करंट लगने से मरने वाले किशोर के घर पहुंच मंत्री स्वतंत्र देव ने दी आर्थिक सहायता

अंबेडकर नगर। बेवाना थानाक्षेत्र के नौगवां गांव में किशोर की करंट की चपेट में आने से मौत की सूचना मिलने पर मंत्री जल शक्ति विभाग स्वतंत्र देव सिंह,मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग,प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिलाधिकारी अविनाश सिंह , पुलिस अधीक्षक डॉ.कौस्तुभ, भाजपा जिला अध्यक्ष त्यंबक तिवारी मृतक के घर पहुंच कर मृतक को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री गण व जिलाधिकारी द्वारा प्रशासन की तरफ से परिजनों को 5 लाख का आर्थिक सहायता के साथ ही आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री आवास, राशन कार्ड, तालाब का पट्टा और एक बीघा का कृषि भूमि का पट्टा आवंटन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मृतक के परिजनों की मुख्य मांगे थी कि पांच लोगों को जिनके खिलाफ परिजन ने तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी, उन पांच लोगों को कल ही रात गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भरोसा दिलाया गया कि जिला प्रशासन मृतक के परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक धर्मराज निषाद, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा व मिथिलेश त्रिपाठी के साथ ही संबंधित उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी गण व अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

लोको पायलट के आवास से नगदी सहित लाखों के स्वर्णाभूषण चोरी

मुग़लसराय, चन्दौली। अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोको कालोनी में एक बंद पड़े रेल आवास को चोरों ने निशाना बनाया है। गुरुवार को घर पहुंचने पर रेलकर्मी को घटना के बाबत जानकारी हुई। पीड़ित रेलकर्मी के अनुसार क्वार्टर की पीछे की दीवार तोड़कर घुसे चोरों ने आलमारी का ताला तोड़कर लगभग 12 लाख रुपए के जेवरात और आठ हजार रुपए नगदी पार हाथ साफ किया है । घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले कन्हैया लाल रक्षाबंधन पर्व पर लोको कालोनी स्थित रेलवे क्वार्टर 416 सीडी में ताला बंद कर परिवार के साथ घर गए हुए थे। गुरुवार को दिन में लगभग 11 बजे जब लोको कालोनी स्थित क्वार्टर पहुंचे तो कमरे में बिखरा हुआ सामान देखकर उनके होश उड़ गए । उन्होंने बताया कि घर में लगा एसी चल रहा था , वहीं आलमारी में रखा। समान गायब था। पीड़ित ने बताया कि आलमारी में रखे लगभग 12 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और आठ हजार रुपए नगदी समेत अन्य समान गायब थे । उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दीं । मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है । वहीं मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत कस्बा स्थित लाल बहादुर शास्त्री क्रय विक्रय केंद्र में चोरों ने बुधवार की रात चार गुमटियों के ताले चटका दिए।

इस दौरान चोर सिर्फ योगेश की गुमटी में चोरी कर पाए। पीड़ित ने बताया कि उसकी गुमटी से लगभग दस हजार रुपए मूल्य का समान और दो हजार रुपए नगदी पर हाथ कर दिया। इस घटना के बाद से दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त है । लोगो। ने बताया कि पहले कूड़ा बाजार पर तैनात पुलिसकर्मी एलबीएस कटरे में रात में गस्त करते रहते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होता है , जिससे चोरों के हौसले बुलंद है। पीड़ित ने कूड़ा बाजार पुलिस चौकी पर तहरीर दी है।

देवी जयंती पर कजली और सोहर गीतों के साथ शास्त्रीय गीतों से झूमा विंध्य धाम

विंध्याचल। मीरजापुर मां विंध्यवासिनी देवी जयंती के अवसर पर बुधवार को शाम 7 बजे से अखिला भारती सांस्कृतिक समारोह मां विंध्यवासिनी आराधना केंद्र के तत्वाधान में मां विंध्यवासिनी देवी जी का भव्य व दिव्य श्रृंगार पूजन तथा विशाल भंडारे तथा प्रसाद वितरण के साथ कोलकाता और वाराणसी के फूलों से मां का श्रृंगार और मंदिर की सजावट किया गया। विंध्य कॉरिडोर परिसर को रंग बिरंगी झालरों से भव्यता के साथ सजाया गया था तथा देवी जागरण में रात भर लोकप्रिय गायकों और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले मां विंध्यवासिनी देवी जी का भव्य और दिव्य विधि विधान पूर्वक मां की श्रृंगार किया गया इसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम के बाद भंडारा और रात भर देवी जागरण का कार्यक्रम होता रहा। अमरेश शुक्ला प्रयागराज ने हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू , फिर इसी को सोहर के रूप में गाया तब सभी भक्त इनके साथ गाने लगे, इसी के बाद उन्होंने निमिया की डरिया मैय्या, झुलेली झुलनवा, हे वरदानी, दया करो मां अष्टभुजा महारानी, खप्पर वाली, काली गुफा अति मन भावन आदि गीत के माध्यम से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सबको झुमाते रहें। वहीं मध्य प्रदेश की लोकप्रिय गायिका कल्याणी ने प्यारा भजन तोहरे शरणिया में आई, हे माई विंध्यवासिनी महिमा तोहार जग से अपार बा, सजल दरबार बा, कजली गीत में कृष्ण जन्म लिहे जेल की कोठरिया आदि गीत प्रस्तुत की। बक्सर बिहार के लोकप्रिय गायक विष्णु ओझा, बालक अबोध समझकर गलती भुलाई जा, आदि अपने सभी गीतों से भक्ति की रसधार बहाते रहे।

लेटरल इंट्री
वापसी की घोषणा

सरकार ने नौकरशाही में 'लेटरल इंट्री' की वापसी की घोषणा कर दी। सरकार ने सिविल सेवाओं में लेटरल इंट्री की पहल वापस लेने का निर्णय किया है। यह निर्णय उसके कुछ राजनीतिक सहयोगियों की आपत्तियों के कारण हुआ। विपक्षी दलों ने इसे एससी, एसटी व ओबीसी के अधिकारों का हनन कहा था। हालांकि, इस वापसी से सरकार की नौकरशाही में निजी क्षेत्र से नई प्रतिभा को प्रवेश दिलाने की इच्छा को थोड़ा धक्का लग सकता है। इसका उद्देश्य प्रशासन में विशेष कौशल तथा दृष्टिकोण शामिल करना था। एक अवधारणा के रूप में 'लेटरल इंट्री' की शुरुआत सिविल सेवाओं में आवश्यक समकालीन प्रशासन तथा परंपरागत विशेषज्ञता के बीच खाई पाटने के लिए की गई थी। वित्त, तकनीक तथा सामाजिक विज्ञानों जैसे अनेक क्षेत्रों से पेशेवरों को वरिष्ठ स्तरों पर नौकरशाही में प्रवेश की अनुमति दे कर सरकार सार्वजनिक प्रशासन की प्रभावशीलता और क्षमता बढ़ाना चाहती थी। इस पहल को ऐसी व्यवस्था में नए विचारों और खोजों को प्रवेश कराने की इच्छा के रूप में देखा जा रहा था जिसकी आलोचना अक्सर सुस्त, जड़ तथा समकालीन यथार्थ से कटे रहने के कारण होती है। लेकिन इसे विपक्ष तथा कुछ भाजपा सहयोगियों द्वारा पसंद नहीं किया गया।

आलोचकों का तर्क है कि लेटरल इंट्री से भारतीय सिविल सेवाओं के मूल सिद्धान्तों को नुकसान पहुंच सकता है जिसमें ऐतिहासिक रूप से तटस्थता, निरंतरता तथा देश के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से समझना शामिल है। हालांकि, लेटरल इंट्री के माध्यम से भर्तियां कांग्रेस सरकारों में भी होती रही हैं और उनमें आरक्षण का भी

कोई प्राविधान नहीं था, पर संभवत: इस बार इनकी संख्या अधिक थी। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने 2005 में लेटरल इंट्री की सिफारिश की थी। इस संस्तुति के पहले भी प्रोफेसर व अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्त सचिव बनाया गया था तथा बाद में 'आधार' अवधारणा के जनक नंदन नीलकेणी को नौकरशाही में स्थान मिला था। इसके साथ ही कांग्रेस सरकारों में लेटरल इंट्री के माध्यम से अनेक भर्तियां की गई थीं। कांग्रेस शासनकाल में लेटरल इंट्री का कोई विरोध नहीं हुआ, जबकि अब राहुल गांधी व विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' इसका विरोध कर रहा था। यह राजनीतिक व चुनावी लाभ के लिए सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने के प्रयास के सिवा और कुछ नहीं है। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने याद दिलाया है कि कांग्रेस शासनकाल में लेटरल इंट्री से भर्तियां मनमाने व अपारदर्शी ढंग से होती थीं, जबकि इस बार सरकार ने इसके लिए खुला विज्ञापन जारी किया था। भाजपा नेताओं ने यह भी याद दिलाया है कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार में श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति नौकरशाही के निर्णय निर्देशित करती थी, लेकिन इस पर कभी सवाल नहीं उठे। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि मोदी सरकार ने आरक्षित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना भी शामिल है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 'लेटरल इंट्री' पर निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर वापस लिया गया है जो इसमें एससी, एसटी व ओबीसी को समुचित आरक्षण देना चाहते हैं। इस प्रकार भाजपा ने सही समय पर सही कदम उठा कर विपक्ष के हाथों से एक हथियार छीन लिया है जिसके बहाने वह देश की जनता को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने का सपना देख रही थी।

कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव

वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 की वापसी तथा जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने के बाद इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कश्मीर में चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 की वापसी तथा जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने के बाद इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक प्रकार से यह चुनाव जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में विधानसभा चुनाव 90 विधायक चुनने के लिए होंगे। ये चुनाव अगस्त, 2019 में राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा उसे दो संघशासित क्षेत्रों में बांटने के बाद पहली बार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नए चुनाव कराने में विलंब को लेकर काफी समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन हाल में सर्वोच्च न्यायालय का दिशानिर्देश महत्वपूर्ण रहा जिसके चलते अब राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस निर्देश ने चुनाव का समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि कश्मीर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का बिंदु रहा है। भारत और पाकिस्तान, दोनों पूरे कश्मीर पर अपना दावा करते रहे हैं, हालांकि दोनों देशों का इसके एक-एक हिस्से पर शासन रहा है। पाकिस्तान ने लंबे समय से कश्मीर मुद्दे के 'अंतरराष्ट्रीयकरण' का प्रयास किया है। कश्मीर मुद्दा लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी उठाया जाता रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के अलावा अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा बार-बार उठाया है, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। 2019 में राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा राज्य को दो भागों में बांटने पर भी विवाद रहा है। राज्य को विभाजित करने के निर्णय से जम्मू कश्मीर का अपना झंडा, अपराध संहिता तथा संवैधानिक प्रक्रियायें समाप्त हो गईं। इसके कारण कश्मीरियों को सरकारी नौकरियों के अवसर भी घटे क्योंकि अब कश्मीर के बाहर के लोग भी इनमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा राज्य को दो भागों में बांटने के बाद चुनौतियों के बावजूद राज्य में अनेक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिए हैं, भले ही कुछ लोगों पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहलों ने राज्य में विकास को गति दी है। जम्मू कश्मीर में खाड़ी देशों द्वारा निवेश करने में दिलचस्पी बढ़ी है जिससे जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। इससे राज्य के निवासियों में आशा की किरण पैदा हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार, राज्य में आतंकवादी व अलगाववादी प्रवृत्तियां कमजोर पड़ने के कारण हताहतों की संख्या में भारी कमी आई है।

सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या जहां 2019 में 80 थी, वह 2023 में घट कर 33 रह गई। इसी प्रकार सिविलियन मौतों की संख्या भी 2019 में 44 से घट कर 2023 में 12 रह गई। राज्य में इसके पहले 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। राज्य में बदलते परिवेश के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बहुत बढ़ा और इस सकारात्मक परिघटना ने विधानसभा चुनाव का रास्ता खोल दिया। कश्मीर में हालिया संसदीय चुनाव में 58.46 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जो 2019 में आम चुनाव से 30 प्रतिशत अधिक था। सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा राज्य के दो भागों में विभाजन के बाद 'परिसीमन' भी पूरा किया। 2022 में परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 87 से बढ़ कर 114 हो गई है, जिसमें पाक-अधिकृत कश्मीर-पीओके की 24 सीटें भी शामिल हैं।

सीटों में इस वृद्धि के कारण शक्ति संतुलन बदला है और यह आगामी चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। भाजपा का दावा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने तथा कश्मीर में इसके बाद लागू की गई उसकी नीतियों के कारण क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए हालिया लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विजय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस-एनसी व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी-पीडीपी भी पुनर्जीवित हुई हैं। इस चुनाव में उनकी सदस्य संख्या बढ़ी है तथा वे लंबे समय से लंबित मुद्दों को सामने लाने में सफल हुई हैं। हालांकि, कांग्रेस को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली और एनसी अपने द्वारा लड़ी तीन सीटों में से दो पर विजय प्राप्त करने में सफल रही, पर तीसरी सीट पर भी उसने मजबूत चुनौती पेश की थी।

क्षेत्र में आतंकवाद के इतिहास तथा चुनावों में धांधली के आरोपों के बावजूद हाल में हुए चुनाव मोटेतौर से स्वच्छ एव निष्पक्ष माने जाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव केन्द्र सरकार के प्रयासों की परीक्षा होगी जो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारतीय संघ के साथ जोड़ना चाहती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अनुच्छेद 370 की वापसी के साथ शुरू हुई है जो इस राज्य को विशेष दर्जा देती थी। यह निर्वाचन आयोग की भी परीक्षा होगी कि वह बिना किसी हिंसा के चुनाव कराने में सफल हो। राजनीतिक पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं जिनमें अभियान की रणनीतियां बनाना, गठबंधन के प्रयास तथा उम्मीदवारों का चयन शामिल हैं। चुनाव की योजना बनाने के लिए पीपुल्स कान्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कान्फ्रेंस अपनी बैठकें कर चुकी हैं।

राजनीतिक पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की व्यापक रूप से तैयारियां शुरू कर दी हैं जिसमें अभियान की रणनीति बनाने के साथ ही संभावित गठबंधनों पर गौर करना व विभिन्न विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देना शामिल हैं। पीपुल्स कान्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तथा नेशनल कान्फ्रेंस लगातार पार्टी के स्तर पर बैठकें कर चुनाव की रणनीति और योजना बना रहीं हैं। यदि विधानसभा चुनाव निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के अनुसार होते हैं तो घाटी में नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं में ध्रुवीकरण तथा अलगाववादी विमर्श भी देखने को मिला था। आशंका है कि विधानसभा चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही इन परिघटनाओं को बल मिल सकता है। पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी और अन्य ने चुनावी बयानबाजी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग की चुनाव कराने की घोषणा का समर्थन करने वाली अन्य पार्टियों ने भी चुनावी प्रचार शुरू करने की पहल कर दी है। इनमें कांग्रेस, भाजपा, माकपा तथा पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी-डीपीएपी भी शामिल हैं।

2014 में जम्मू कश्मीर चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री घोषित करने के पहले राज्य में 49 दिन तक राज्यपाल शासन लागू करना पड़ा था। 2018 में भाजपा ने सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने का निर्णय किया जिसके चलते राज्य में एक बार फिर राज्यपाल शासन लागू करना पड़ा। इसके बाद नवंबर, 2018 में विधानसभा भंग कर दी गई और दिसंबर, 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद से राज्य में राज्यपाल शासन चल रहा है। सरकार को यह तय करना है कि वह कश्मीर घाटी में अलगाववाद की कुछ घटनाओं से निपटने के लिए हस्तक्षेप करना चाहती है अथवा वह चुनाव के पहले राज्य में कोई पुनर्गठन योजना लागू करेगी। हालिया संसदीय चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था। इसके अंतर्गत नेशनल कान्फ्रेंस ने कश्मीर में तीन सीटों पर चुनाव लड़ा जबकि कांग्रेस ने जम्मू और उधमपुर में चुनाव लड़ा।

'इंडिया' गठबंधन की साझीदार होने के बावजूद पीडीपी को इस गठजोड़ में शमिल नहीं किया गया और उसने नेशनल कान्फ्रेंस के खिलाफ कश्मीर में तीन सीटों पर चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस और एनसी साथ चुनाव लड़ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला के अनुसार, पीडीपी से गठबंधन कठिन होगा क्योंकि संसदीय चुनाव में वे एक-दूसरे के खिलाफ थे। यदि क्षेत्रीय पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करना चाहें तो उनको एकजुट होकर 'इंडिया' से गठजोड़ करना चाहिए। कश्मीर विधानसभा चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है जिनसे एक दशक बाद राज्य में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा।

विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम

डिजिटल लर्निंग के साथ-साथ शिक्षा और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का यह बजट आवंटन एक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने में मदद करेगा।

रीतू श्रीवास्तव
(लेखिका शिक्षाविद हैं)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2024-25 के बजट को 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन, अनुसंधान और नवाचार को पहले की तरह प्राथमिकता देते हुए, सविकसित भारत के लिए बजट भारत की साख को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा उठाए गए ये व्यापक और ठोस उपाय हैं जो सभी हितधारकों-छात्रों, शिक्षाविदों और उद्योग के लिए फायदेमंद होंगे। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए बजट आवंटन 30 प्रतिशत बढ़ाकर 1.48 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें स्कूलों में 265 मिलियन छात्र, उच्च शिक्षा में 43 मिलियन और कौशल संस्थानों में 10 मिलियन से अधिक शिक्षार्थी नामांकित हैं। 2024-25 के लिए 73,498 करोड़ रुपये का बजट आवंटन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए अब तक का सबसे अधिक है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति जैसे स्वायत्त निकायों को भी अब तक का सबसे अधिक आवंटन मिला है। समग्र शिक्षा, पोषण और पीएम-श्री जैसी प्रमुख योजनाओं को 3,250 करोड़ रुपये मिले हैं। बजट में कौशल और प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, भारत की शीर्ष कंपनियों द्वारा एक करोड़ युवाओं के लिए कौशल विकास और इंटर्नशिप के अवसर, और पूरे क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है। सरकार ने 25000 छात्रों को सालाना 1.5 लाख से 7.5 लाख तक की 'मॉडल कौशल ऋण योजना' शुरू की है और उच्च घरेलू शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर साल एक

लाख छात्रों को 3ज्ञ की वार्षिक ब्याज छूट के साथ 10 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया है। इस कदम से निश्चित रूप से घरेलू संस्थानों में नामांकन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही छात्रों पर वित्तीय बोझ भी कम होगा। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कौशल विकास क्षेत्र के लिए कई पहलों की रूपरेखा भी बताई।

इनमें उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन शामिल है। सरकार द्वारा 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर एक स्वागत योग्य कदम है, इससे युवाओं को जुड़ाव मिलेगा और रोजगार और व्यावहारिक कौशल में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) योजना में 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस बजट में उच्च शिक्षा विभाग के बजट आवंटन में कुल 3525.15 करोड़ रुपये (7.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर और आईआईएससी को भारी आवंटन मिला है, जो पिछले बजट की तुलना में काफी अधिक है। उच्च शिक्षा में डिजिटल ई-लर्निंग, शोध एवं नवाचार, शिक्षक प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र और कुछ विशिष्ट संस्थानों जैसे क्षेत्रों को अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। डिजिटल ई-लर्निंग के तहत सरकार वर्चुअल लर्निंग की क्षमता का दोहन करने और पोर्टेबिलिटी और लचीले अध्ययन विकल्पों को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ जोड़ने की योजना बना रही है।

'आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन' योजना में 2024-25 में 480 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह 2023-24 के आवंटन से 80 करोड़ रुपये अधिक है। शोध एवं नवाचार के लिए बढ़ा हुआ बजट विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग पर केंद्रित है। स्कूल स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक नए शैक्षणिक ढांचे की आवश्यकता है, इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण खंड को इसका उचित हिस्सा मिला है। 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में 3 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना' योजना को बजट में 255 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) जिसे पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के नाम से जाना जाता था, के लिए बजट 1814.94 करोड़ रुपये रखा गया है। उत्कृष्ट संस्थानों के लिए 1800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 'बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार ईएपी (मेरिटे)' योजना में 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह पिछले साल के बजट से 100ज्ञ अधिक है।

एनईपी 2020 का कहना है कि नीति का उद्देश्य भारत में 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करना होना चाहिए जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच हो। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार ने शिक्षा के लिए एक महत्वाकांक्षी पैकेज तैयार किया है ताकि यह विकासोन्मुख, समावेशी और प्रगतिशील हो। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका कार्यान्वयन है। शिक्षा मंत्री द्वारा बताए गए अनुसार शिक्षा के लिए बजट की विशेषताएँ 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनने की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

आप की बात

हिंदुओं पर अत्याचार

इस्कॉन प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक्स पर लिखा है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के वजूद में आ जाने के बावजूद हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। दास ने दावा किया कि बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं पर हर दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य बांग्लादेश में काम कर रहे सभी 25 लाख हिंदुओं को उनकी नौकरियों से हटाना है। यह सब कुछ नई सरकार के सपोर्ट और एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। यह सब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत तथा उनके गृह मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से हिंदुओं से माफी मांगने के बाद हो रहा है। स्पष्ट है कि यह बांग्लादेश में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने और अंतत: देश छोड़ कर जाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से राजनयिक स्तर पर सीधे बात कर इन प्रवृत्तियों पर रोक लगाने का आग्रह करना चाहिए। इसके लिए भारत को आवश्यकता होने पर बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव डालने, भारत में उसकी परिसंपत्तियां जब्त करने, उसके साथ व्यापार व अन्य संबंध तोड़ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में व अन्य मंचों पर मुद्दा उठाने पर विचार करना पड़ सकता है।

-सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

आरक्षण: जटिल समस्या

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में उप-विभाजन को लेकर दिए फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान एक प्रकार से अपनों का अपनों के उत्थान के विरुद्ध अभियान है। आखिर भारत बंद का आह्वान करने वाली ये कैसी लीडरशिप है जो कहती है कि गरीब, पिछड़े और अक्षम वहीं रहें और जो ऊपर उठ गए हैं या सक्षम बन गए हैं उन्हें ही पीढ़ी दर पीढ़ी शीर्ष पर चढ़ाते जाएं। ऐसे में कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भला क्या करे? बरसों से चल रही स्वार्थ की राजनीति ने आरक्षण नीति को इतना उलझाकर रख दिया है कि उसे सुधारना तो दूर उसमें गरीब व अक्षम लोगों के हित में फैसले लेना भी असंभव सा हो गया है। ऐसे में राजनेता, कानूनविद और समाजसेवी तीनों को मिलकर आरक्षण जैसी जटिल समस्या का दीर्घकालीन समाधान ढूंढें ताकि हर छोटी-छोटी बात पर लोग सड़क पर न आने पाएं। बाबा साहब की फोटो लेकर आंदोलन के नाम पर हिंसक उपद्रव करने वालों को स्वयं अंबेडकर के शब्द याद रखने चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत में संविधान लागू होने के बाद अब आंदोलन, धरना, हड़ताल, आदि असंवैधानिक गतिविधियों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। क्या आरक्षण समर्थक समाज में संवाद का कोई रास्ता खोजेंगे?

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि राज्य सरकारें एससी-एसटी, यानी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्ग बना सकती हैं। इसके विरोध में समूचा विपक्ष खड़ा हो गया। सरकार ने भी राजनीतिक मजबूरियों के कारण इसे परोक्ष रूप से यथावत रखने का आश्वासन दे दिया है। गंभीरता से गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई विसंगति नहीं है और यह संविधान की भावना के अनुकूल सर्वाधिक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। मगर वोटों की राजनीति और भीडतंत्र ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए भारत बंद का आह्वान कर दिया। क्या आजादी के बाद से आरक्षण का लाभ ले चुकी एससी-एसटी की क्रीमी लेयर यह नहीं चाहती कि उनके अन्य गरीब बंधु-बांधवों को भी उन्हीं की तरह आगे आने का मौका मिले? ऐसे में आरक्षण की सीमा बढ़ाने व जातीय गणना कराने की मांग करने वाले नेताओं की नीयत पर भी सवाल उठता है कि क्या वे देश में एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा कर अपने निहित राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के लिए देश को कमजोर करना चाहते हैं? यह स्थिति निश्चित रूप से चिन्ताजनक है।

- विभूति बुपक्या, खाचरोद

एक राष्ट्र एक चुनाव

प्रधानमंत्री मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव के नारे से विपक्षी दलों के नेता भी सहमत होने लगे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे का समर्थन करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया है और इस पर अपनी सहमति दी है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के लिए एक राष्ट्र चुनाव का नारा लागू करने की बात दोहराते हुए सभी दलों से इस पर सहमति देने की बात कही थी। हालांकि, शरद पवार ने चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनाव घोषणा को देखते हुए प्रधानमंत्री का मजाक भी उड़ाया। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा सभी राजनीतिक दलों की सहमति और अनेक संविधान संशोधनों के बाद लागू हो सकती है। अत: शरद पवार के व्यंग्य या मजाक का कोई तुक नहीं है। देश की वर्तमान विभाजित राजनीति तथा भाजपा-विरोधी दलों के अधिकांश नेताओं की येन-केन-प्रकारेण सत्ता तक पहुंचने की लालसा के कारण फिलहाल ऐसी अवधारणा के फलीभूत होने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अच्छे विचारों को बार-बार दुहराना भी लाभदायक है।

- मनमोहन राजावत, शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

कार्यदाई संस्थाएं गुणवत्ता का दें विशेष ध्यान: डीएम

● निर्माणाधीन परियोजनाओं की डीएम ने की समीक्षा

संवाददाता। अमेठी

जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ जनपद में 50 लाख के ऊपर लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं को लेकर समीक्षा किया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए इसे कार्यदायी संस्थाएं पूरी गंभीरता से लें। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि प्राप्त हो गई है उन परियोजनाओं का कार्य निश्चित समयावधि के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाएं पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने तथा गुणवत्तापूर्ण एवं समय के अंदर कार्य पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा मानक विहीन व अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता जांच के बाद ही निर्माण कार्य में प्रयुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को पूर्ण कराने में बजट की आवश्यकता हो उसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे जिससे कि कार्य में बाधा न उत्पन्न हो व निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं उनको संबंधित विभाग को हैंड ओवर कर दिया जाए।

डीएम-एसपी ने की कानून व्यवस्था व अभियोजन कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक

अमेठी। आज कलेक्ट्रेट सभागार गौरीगंज में जिलाधिकारी निशा अनंत व पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह द्वारा जनपद के अधिकारीगण के साथ कानून व्यवस्था व अभियोजन कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अभियोजन कार्यों के स्पीडी ट्रायल, संबंधित मामलों, सामान्य वाद तथा राजस्व से संबंधित वादों की समीक्षा की गई तथा गत माह में दायर मामलों, मामलो में हुए निर्णय, डिस्पोज्ड मामले सहित पुराने मामलों की पेंडेंसी एवं डिस्पोजल तथा न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मामलो को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराने के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक हरेन्द्र कुमार, जिला अभियोजन अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारीगण, जनपद के थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

पशु चिकित्सालय की भूमि पर अवैध निर्माण

तिलोई, अमेठी। राजकीय पशु चिकित्सालय इन्हौना की भूमि पर एक वर्ष पूर्व पशुपालन विभाग से सेवा निवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वार अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को भेजी है। जानकारी के मुताबिक लगभग 38 वर्ष पूर्व वर्ष 1984 में इन्हौंना में शुक्लबाजार मार्ग के किनारे ग्राम पंचायत की भूमि पर पशु चिकित्सालय का निर्माण हुआ था। परंतु चहार दिवारी का निर्माण नहीं हुआ था। पशु चिकित्सालय के साथ ही चिकित्सक आवास और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवास का निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया था। अस्पताल में मूलरूप से तिलोई विकास क्षेत्र निवासी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विजय बहादुर विभाग के सरकारी आवास में निवास कर रहे थे और एक वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त हो गए पशुपालन विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते सेवा निवृत्त कर्मी ने आवास का कब्जा नहीं छोड़ा। और अब उसी परिसर में अपना निजी आवास निर्माण करा रहा है।

सीएम डैशबोर्ड व विकास कार्यों को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

संवाददाता। श्रावस्ती, भिनगा

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग लाने वाले विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगायी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी सीएम डैशबोर्ड पर अपने विभाग की रैंकिंग में आपेक्षित सुधार लाएं और टीम भावना के साथ कार्य कर विकास कार्यक्रमों में तेजी लाकर जनपद की रैंकिंग बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभायें। इस दौरान यदि किसी भी विभागीय अधिकारी की प्रगति में शिथिलता पायी गई तो निश्चित ही कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि माह जुलाई में जनपद श्रावस्ती को विकास कार्यो एवं राजस्व के सम्बन्ध में 33 वीं रैंक है माह जुलाई में जनपद श्रावस्ती को कुल 75 कार्यक्रमों में से 45 कार्यक्रमों में ए. व ए श्रेणी 05 कार्यक्रमों में बी श्रेणी 03 कार्यक्रमो में सी श्रेणी, 05 कार्यक्रमो में डी श्रेणी 07 कार्यक्रमों में ई श्रेणी एवं 10 कार्यक्रमों में 6 प्राप्त हुआ है। अतिरिक्त ऊर्जा, उद्यान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दुग्ध विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पिछडा वर्ग कल्याण, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास, सहकारिता, सिचाई एवं जल संसाधन विभागो के कार्यक्रमो में ए्ए् श्रेणी तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यक्रमों में ए/ ए. प्राप्त हुआ है। ऊर्जा, कृषि, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, पचांयतीराज, पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन, माध्यमिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता, सूक्ष्म लधु एवं मध्यम उद्यम, समाज कल्याण, लोक शिकायत विभागों के कार्यक्रमो में श्रेणी यथा– बी, सी, डी व ई श्रेणी प्राप्त हुये हैं जिससे जनपद की रैंकिंग प्रभावित हुई है, इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य में तेजी लाकर अपनी देख–रेख में शत–प्रतिशत डाटा फीडिंग कराने हेतु निर्देशित किया।

पुलिस भर्ती परीक्षा आज प्रशासन ने कीं तैयारियां

संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन सभागार में आगामी 23/ 24/25/30 व 31, अगस्त, 2024 को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के दृष्टिगत समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद के अन्तर्गत 09 केन्द्रों पर दो पालियों में परीक्षा समय क्रमशः प्रथम पाली प्रातः 10.00बजे से 1200 बजे तक व द्वितीय पाली अपरान्ह 15.00बजे से सायं 17.00 बजे तक कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें कुल 2616 परीक्षार्थी शामिल होगें। उक्त परीक्षा को सकुशल सम्पन्न करानें / शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधि0 / कर्मचारीगण के साथ गोष्ठी की गई व शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। गोष्ठी के दौरान क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अजीत चौहान व क्षेत्राधिकारी धनघटा अजय सिंह सहित समस्त अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

डीएम को अल्पसंख्यक समाज ने दिया ज्ञापन

संतकबीरनगर। विधानसभा चिल्लूपार 328 गोरखपुर की फेस बुक आईडी से मजहबे इस्लाम और नबी पाक स.अ.व. के खिलाफनाज़ेबा बाते लिखी थी और कार्टून भी बनाया था। जिसके विरोध में बुधवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सैय्यद फिरोज अशरफएवं ग्राम प्रधान आटा कला एकलाख अहमद के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लोगो ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उसके विरूद्व कार्रवाई किये जाने की मांग की है। अधिकारियों ने अल्पसंख्यक समाज को अस्वस्थ किया है कि सम्बन्धित के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाय। अल्पसंख्यक समाज ने कहा है कि पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक बयान व कार्टून की शक्ल ने प्रदर्शित किया है जो कि संविधान के मूल विचारधारा के विपरीत असामाजिक कृत्य है।

तालाब व बंजर भूमि से प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा

डलमऊ, रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार की अवैध अतिक्रमणकरियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तहसीलदार डलमऊ उमेश चंद्र द्वारा मौके पर पहुंच कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण करियों से मुक्त कराते हुए सभी अतिक्रमण करियों के हौसले पस्त कर दिया साथ ही सरकारी जमीन पर कुंडली मार कर बैठे अवैध अतिक्रमण करियों पर आगे भी कड़ी कार्यवाही होने के संकेत दिया.मामला कैली गांव मजरे लोदीपुर उतरांवा का है जहां पर गाटा संख्या 2420 तालाब और 2573 बंजर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करलिया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सरकारी भूमियों को अवैध अतिक्रमण करियों से मुक्त कराने संबंधी निर्देश पर सख्ती के साथ अनुपालन के क्रम में बुधवार को तहसीलदार उमेश चंद्र द्वारा मौके पर पहुंच कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण करियों से मुक्त कराया.इस कार्यवाही के दौरान तहसीलदार उमेश चंद्र के साथ राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र प्रजापति, लेखपाल राजेश गुप्ता सहित पुलिस बल की उपस्थित रहा। पूर्व में पारित सकुर्लर में तहसीलदारों को गैर कानूनी कब्जे हटाने के लिए अधिकृत किया गया। सरकार की भूमि पर अतिक्रमण या कब्जा करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर वार्षिक लगान का 50 गुना तक जुर्माना लगेगा।

डीएम-एसपी व विधायक ने सीताद्वार मन्दिर एवं झील का लिया जायज़ा

श्रावस्ती, इकौना। विधायक इकौना रामफेरन पाण्डेय डीएम अजय कुमार द्विवेदी एवं एसपी घनश्याम चौरसिया ने विकास खण्ड इकौना के सीताद्वार मन्दिर में पहुंचकर दर्शन–पूजन किया। इस दौरान उन्होने सीताद्वार मन्दिर एवं झील पर पूर्व में कराये गये साफ–सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कार्य का भी जायजा लिया। विधायक ने डीएम को अवगत कराते हुए बताया कि सीताद्वार मन्दिर एवं झील मनोरम स्थल है। यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जन सहयोग द्वारा झील की साफ–सफाई एंव विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य प्रारम्भ कराया गया था, किन्तु कुछ कारणवश सौन्दर्यीकरण कार्य को बन्द कर दिया गया था। जिसे पुनः प्रारम्भ कराने की आवश्यकता है।

रेलवे बोर्ड के सदस्य ने आरेडिका एवं फोर्ज्ड व्हील प्लांट का किया दौरा

लालगंज, रायबरेली। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना एवं फोर्ज्ड व्हील प्लाण्ट का रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य (उत्पादन इकाई) संजय कुमार पंकज ने दौरा किया। श्री पंकज ने कोच एवं फोर्ज्ड व्हीलों के उत्पादन के संबंध में आरेडिका के महाप्रबंधक श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा तथा उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान दीन दयालु कोचों के उत्पादन को गति देने के लिए आरेडिका के उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया क्योंकि रेलवे का ध्येय सामान्य कोचों में यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का है। अपर सदस्य ने फोर्ज्ड व्हीलों के उत्पादन को 35 हजार से बढाकर 50 हजार एवं आगे 70 हजार फोर्ज्ड व्हील वार्षिक करने हेतु प्लांट की अवसंरचना का विकास के संबंध में उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किया एवं बताया कि आने वाले समय में फोर्ज्ड व्हीलों की मांग बढेगी इसलिए उत्पादन बढाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने का सुझाव दिया। रेलवे बोर्ड का सहयोग आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। आरेडिका के व्हील निर्माण से फोर्ज्ड व्हीलों के विदेशी आयात से भी राहत मिल रही है। अपर सदस्य ने कारखाना परिसर का दौरा किया एवं आरेडिका में प्रथम निर्माणाधीन टीआरएस टीआरएससी कोचों का निरीक्षण किया।

डीएम ने रैंकिंग में सुधार लाने के लिए दिए निर्देश

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत विकास कार्यों, राजस्व संबंधी कार्यक्रमो/ योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सेवाओं, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति जाना रहा। उन्होंने बारी–बारी से सभी विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि कार्य को समय से और गुणवत्तापरक पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड में जिन विभागों की रैंकिंग ठीक नहीं है उन विभागीय अधिकारियों को कड़ी फ्टकार लगाई। निर्देश दिया कि जो भी विभागीय अधिकारी अपने कार्यों में उदासीनता दिखा रहे हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कराई जायेगी।

जिलाधिकारी ने की स्वास्थ्य समिति बैठक की अध्यक्षता

अयोध्या। जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी। जिलाधिकारी ने बैठक में राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि नवजात शिशु (0 वर्ष) से 5 वर्ष तक सभी बच्चों का समय से टीकाकरण किया जाय साथ ही यू–विन के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर सेशन क्रिएशन शत प्रतिशत किया जाय तथा बाल विकास पुष्टाहार व शिक्षा विभाग से समन्वय कर नियमित टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे सभी पात्र बच्चों का सही से हेड काउंट सर्वे करा कर उनका शत प्रतिशत टीकाकरण से आच्छादित किया जाय।

जिलाधिकारी ने क्षय रोग मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुये टी0बी0 टास्क फोर्स तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टास्क फोर्स का गठन करते हुए 9 सितम्बर 2024 से 19 सितम्बर 2024 (10 दिन) एक्टिव केस फाइंडिंग प्रोग्राम्स चलाया जाए, जिसमें टी0बी0 के एक्टिव मरीजों के खोज की जाएगी। क्षय रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत जनपद को क्षय रोग से मुक्त करने के अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। जनपद को क्षय रोग से मुक्त करने के लिए और भी सघन प्रयास करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।

जिलाधिकारी ने तीन दिवसीय प्रदर्शनी का किया शुभारम्भ

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज, ऑडिटोरियम के परिसर में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा आयोजित राणा बेनी माधव बक्श सिंह के जीवन एवं जनपद के महत्वपूर्ण स्थलों व प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर आधारित तीन दिवसीय प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारम्भ कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि राणा बेनी माधव बक्श सिंह के जीवन व जनपद के महत्वपूर्ण स्थलों एवं प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण नीतियों, निर्णयों, उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा 22 से 24 अगस्त तक फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के परिसर में तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी सुबह 09 बजे से सायं 06 बजे तक आमजन मानस के लिए खुली रहेगी। जिसमें आम जनमानस आकर जानकारी प्राप्त कर सकते है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभपरक व जन कल्याणकारी योजनाओं संबंधित जानकारी लोगों को मिलती है।

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाला मौन जुलूस

संवाददाता। उरई, जालौन

गुरुवार को हिंदू रक्षा समिति, कानपुर प्रान्त के निर्देशन में बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे शारीरिक, आर्थिक व धार्मिक शोषण तथा अत्याचारों के विरोध में टाउन हॉल उरई से जिलाधिकारी कार्यालय तक मौन जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मौन जुलुस के दौरान उमस भरी गर्मी के चलते बारिश होनी शुरू हो गयी लेकिन कार्यकर्ता बरसते पानी में पैदल चलते रहे। मौत जुलूस में मातृ शक्ति ने भी सहभागिता की।

प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि विगत दिवसों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार पत्रों व सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों व उनके पवित्र पूजा स्थलों पर लगातार हमले हो रहे है। उत्पीडन, शोषण व मानवीय अत्याचारों से समस्त बांग्लादेशी हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक व्यथित व पीड़ित है। बांग्लादेश में अराजकता तथा निष्प्रभावी कानून व्यवस्था के कारण अतिवादी जिहादी तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंदुओं का आर्थिक तथा शारीरिक शोषण किया जा रहा है। हिंदुओं को लक्ष्य मानकर उसके धार्मिक तथा व्यवसायिक स्थलों पर लूट व तोड़फोड़ की जा रही है, ऐसी घटनाएं बांग्लादेश में प्राय: होती रहती थी परंतु ध्वस्त सरकारी व्यवस्था के चलते ऐसी घटनाओं ने वीभत्स रूप ले लिया है।

कट्टरपंथी जिहादियों द्वारा बहन, बेटियों तथा छोटे बच्चों पर भी किए जा रहे कृत्यों के चित्र आदि देखकर संपूर्ण देश का हिंदू आक्रोशित है। हिंदू रक्षक समिति तथा अन्य हिंदू संगठन बांग्लादेश में व्याप्त इन अमानवीय अत्याचारों व दुर्व्यवस्था से पीड़ित हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यक के परिवारों व उनके व्यावसायिक, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तथा संरक्षण की मांग करते है।

मॉनिटरिंग टीम जिले में वृक्षारोपण की जमीनी हकीकत परखेगी

संवाददाता। उरई, जालौन

पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्य किए जाने की मंशा से प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए वृहद वृक्षारोपण अभियान की सत्यता को परखने के लिए अब यहां जनपद में दो मॉनिटरिंग टीम में अपने–अपने कार्यों को अंजाम देने में जुटी हुई है बताया जाता है कि यह मॉनिटरिंग कार्य दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा उसके बाद प्रदेश और केंद्र को भी वस्तु स्थिति की रिपोर्ट भेजी जाएगी।

बताते चलें कि वर्ष 2024 में प्रदेश सरकार ने वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्य को किए जाने के निर्देश दिए थे जिनके पालन में यहां जनपद के वन विभाग में उक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण कार्य कराया अन्य विभागों की सहभागिता सुनिश्चित कर विगत माह समुचित जनपद में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया जिला अधिकारी सहित समुचे प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं स्कूली बच्चे और यहां तक की आम नागरिकों ने भी इस वृहद वृक्षारोपण अभियान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।

बहरहाल अब इस वृक्षारोपण अभियान की वस्तु स्थिति को परखने के लिए थर्ड पार्टी सर्वे और मॉनिटरिंग टीमें के जनपद में आई हुई है विभागीय सूत्र बतलाते हैं कि यह मॉनिटरिंग कार्य दिसंबर माह तक पूरा करने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन और एनजीटी को भेजी जाएगी।

वृहद वृक्षारोपण अभियान को लेकर वन अधिकारी जनपद जालौन प्रदीप कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया इस बार वृहद वृक्षारोपण के दौरान बारिश की परिस्थितियों काफी अनुकूल रही हैं जिसके चलते वह अपने लक्ष्य को तो हासिल कर ही सके हैं साथ ही वीजारोपण के माध्यम से किया गया कार्य में उन्हें अच्छे परिणाम मिले हैं रोहित बी लगभग 6 इंच के पौधों में तब्दील हो गए हैं तो वहीं सीधे आरोपित किए गए पौधों की स्थिति भी बेहतर रही है।

डीएफ्ओ प्रदीप कुमार ने यह भी जानकारी दी कि जिले में कुल आठ रेंज जिनका रकवा लगभग 25 हजार हैक्टेयर से ज्यादा हैं जिनमें 70 फीसदी लक्ष्य भूमि पर वीजा रोपण के माध्यम से तथा 30 फीसदी भूमि में सीधे पौधे रोपित कराए गए हैं।

एसडीएम ने खेतों में जलभराव की समस्या का मौके पर पहुंचकर किया निदान

कोंच, जालौन। तहसील क्षेत्र के ग्राम करहियापुर एवं बदऊआं में जलभराव के चलते सैंकड़ों बीघा कृषि भूमि में बोई गयी धान की फसल नष्ट हो जाने से परेशान करीब आधा सैकड़ा से अधिक की संख्या में उक्त दोनों गांवों के परेशान किसानों ने गत दिनों पूर्व एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की गुहार लगायी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जलभराव की समस्या का निस्तारण करा दिया। समस्या निस्तारित होने से ग्रामीण प्रसन्न नजर आ रहे हैं। गुरुवार को एसडीएम ज्योति सिंह और तहसीलदार वीरेंद्र वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर जलभराव की स्थिति देखी। जल निकासी के लिए प्रयुक्त बंबी में जमा खरपतवार को जेसीबी की मदद से साफ कराकर जलभराव की समस्या खत्म करा दी।

पानी में बही सड़क, एट-कोंच रोड पर आवागमन बंद

कोंच, जालौन। एट-कोंच रोड पर पिछले 9 दिनों से आवागमन इसलिए ठप्प पड़ा है कि गांव सतोह के पास पानी के अत्यधिक बहाव के कारण रोड कट गई। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने जिलाधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग व सिंचाई विभाग को रिपोर्ट बना कर भेजी थी। व्यवस्था सुचारु होने तक के लिए इस रोड पर आवागमन बंद कर दिया गया और वाहनों के लिए बैरागढ़ होकर रूट बनाया गया जो लंबी दूरी के साथ जोखिम भरा भी है। दूसरी सड़क तहसील मुख्यालय को सीमावर्ती मध्यप्रदेश से जोड़ने वाली सलैया-दबोह रोड है जो पिछले करीब 12 दिन से ठप्प पड़ी है। इसकी वजह पहूज नदी के पास पानी के तेज बहाव से सड़क में आई कटान है। 12 अगस्त को ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ज्योति सिंह ने सलैया-दबोह मार्ग का पहूज नदी के पुल के 100 मीटर आगे तेज बहाव से कटी सड़क का निरीक्षण किया था।

कालपी में नवीन इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की कवायद शुरू, अधिकारियों ने किया निरीक्षण

संवाददाता। कालपी, जालौन

कालपी में नया इंडस्ट्री एरिया बनाने हेतु गुरुवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त प्रभात यादव एवं कामेश्वर तथा ग्राम प्रधान किरतपुर पवनदीप निषाद तथा हस्त निर्मित कागज उद्योग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार तिवारी के साथ ग्राम सभा किरतपुर में सरकारी राजस्व की 6 हेक्टेयर भूमि का उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करने के बाद उद्योग विभाग के अधिकारियों ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वहां तक रोड भी जिला प्रशासन द्वारा बनना आवश्यक है।

इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान पवनदीप निषाद ने कहा कि ग्राम सभा किरतपुर की प्रस्तावित भूमि कागज उद्योग के विकास के लिए समर्पित है। ग्राम प्रधान ने यह भी बताया की खेत के पास तक बने लिंक रोड कोअतिशीघ्र पक्का बनवाने का प्रयास किया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि कालपी के उद्योगों के विकास के लिए बड़ी इंडस्ट्री एरिया की आवश्यकता है। कालपी में उद्योग स्थापित हो सकते हैं। लेकिन उपयुक्त भूमि न होने के कारण काफी लोग उद्योग लगाने से वंचित हो रहे हैं।

उपरोक्त समस्या को हाथ कागज निर्माता संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार तिवारी जब उद्योग बंधु में यह बात रखी तो जिलाधिकारी जालौन में तत्काल भूमि का सर्वे कराने तथा प्रस्ताव भेजने के निर्देश उप जिलाधिकारी कालपी को दे दिए थे सब कुछ ठीक रहा तो अतिशीघ्र। वहां पर इंडस्ट्री एरिया का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। उपायुक्त जिला उद्योग के प्रभात यादव ने बताया की नई इंडस्ट्री एरिया में सभी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

इसके लिए शासन स्तर से धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है केवल भूमि का चयन की औपचारिकताएं पूरी होना है। इस अवसर पर हाथ कागज उद्योग के वरिष्ठ उद्यमी विनीत गुप्ता, पंकज पांडे, सोनू गुप्ता भी उपस्थित थे। ग्राम प्रधान पवनदीप निषाद ने बताया कि उपरोक्त भूमि चाहीपुर मौजा में है।

पीएम आवास योजना शहरी के पात्रता की जांच में न करें लापरवाही: जिलाधिकारी

● पात्रों को योजना का अवश्य दिलाएं लाभ, कार्य पर सतत रखें निगरानी

पीएम आवास योजना शहरी की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेतीं डीएम सी. इन्दुमती।

फतेहपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में डीएम सी. इंदुमती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने सभी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतो के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थियों की पात्रता की जांच एवं जीओ टैगिंग समय से नियमानुसार पारदर्शिता के साथ सर्वेयर करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहे।

डीएम ने सभी अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वेयर द्वारा की गई जांच की रैंडम जांच करे और उनके कार्य पर सतत निगरानी बनाए रखें। पात्रों को योजना का लाभ अवश्य दिलाएं। एडीएम (न्यायिक) एवं परियोजना निदेशक डूडा को निर्देशित किया कि नपाप एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों/सभासदों के साथ बैठक करा लें और उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाए कि नियमानुसार कार्यवाही कर पात्रों को ही लाभ दिया जाए किसी भी सूरत में अपात्रों को लाभ नहीं दिया जाए। पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के जो आवास निर्माण के कार्य अपूर्ण है उसको समय से पूरा कराएं। द्वितीय, तृतीय किस्तों के भुगतान के लिए नियमानुसार कार्यवाही पूरी कर धनराशि मुहैया कराई जाए। ताकि आवास पूर्ण हो सके और जनपद की रैंकिंग सही रहे। पीएम आवास योजना शहरी में नामित समिति के सदस्य स्क्रूटनी के पश्चात ही पत्रावली प्रस्तुत करें। एडीएम न्यायिक, प्रभारी परियोजना निदेशक डूडा अभिनीत कुमार, अधिशाषी अधिकारियों सहित संबंधित उपस्थित रहे।

कोलकाता मे महिला डाक्टर के साथ हुई बर्बरता के विरोध में वकीलो ने कैडिल मार्च निकाला

कानपुर देहात। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर बेटी के साथ हुई बर्बरता के विरोध में गुरुवार को जनपद न्यायालय के वकीलों ने एकीकृत बार एसोसिएशन के तत्वावधान में घटना का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट करते हुए कैंडल मार्च निकालाएऔर जनपद न्यायालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर के पास इकट्ठा हो श्रद्धांजलि सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर एकीकृत बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम कटियार एवं महामंत्री संजय सिंह सिसोदिया ने कहा कि हम अधिवक्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम पश्चिम बंगाल की घटना का जोरदार विरोध करें और चिकित्सा व्यवसाय रत डाक्टरो अधिवक्ताओं की सुरक्षा की व्यवस्था की मांग सरकार से करें।कानपुर देहात बार एसोसिएशन के संस्थापक महामंत्री वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार से संगठित मांग की जाए कि सरकार केंद्रीय कानून लाये और अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करे। जितेन्द्र चौहान ने कहा कि अब समय की मांग है कि सरकार तत्काल मेडिकल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे।

इस अवसर पर सरोज दीक्षित नरेश सिंह अश्वनी कुमार बाजपेई कमल सिंह यादव पूर्व महामंत्री महेन्द्र मोहन श्रीवास्तव पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ कटियार पूर्व मंत्री ज्योति सिंह जिला शैलेन्द्र कुमार तिवारी अरविन्द कुशवाह अमर सिंह भदौरिया राजीव दीक्षित विजय लक्ष्मी सैनी के के पाण्डे विनोद चौहान रईस अहमद जय सिंह यादव अशोक सचान विकास गुप्ता विराट बाजपेई अभय प्रताप सिंह योगेंद्र प्रताप सिंह चौहान प्रमुख रहे।

महर्षि विद्या मंदिर में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री ने बांटे पुरस्कार

● गीत गोविंद प्रकाशन व ममता फाउंडेशन की प्रतियोगिताओं का हुआ समापन

महर्षि विद्या मंदिर में पुरस्कार वितरित करतीं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति।

फतेहपुर। गीत गोविंद प्रकाशन ने ममता फाउंडेशन की विभिन्न विद्यालयों में कराई गई प्रतियोगिता के समापन के पश्चात गुरूवार को शहर के महर्षि विद्या मंदिर, प्लेवे इंग्लिश स्कूल व आरएस एक्सेल इंग्लिश एकेडमी में पुरस्कार वितरण किया गया।

महर्षि विद्या मंदिर के पुरस्कार वितरण में विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, विशेष अतिथि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सावन गुप्ता एवं अनुभव शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उन्हे प्रमाण पत्र एवं मेडल से सम्मानित किया। महर्षि विद्या मंदिर में कनिष्ठ में प्रथम शिवांश शुक्ला, द्वितीय कुमार अंश, निशांत सानू तृतीय व वरिष्ठ में महिमा गुप्ता प्रथम, तूलिका द्विवेदी द्वितीय, दीक्षा गुप्ता तृतीय, रुद्रकांत दुबे चतुर्थ, अदिति सिंह ने पंचम स्थान प्राप्त किया।

प्लेवे इंग्लिश स्कूल में प्रथम रहीमा अली, द्वितीय अनन्या, तृतीय सोनल कसुधन, चतुर्थ रिचा सिंह एवं मयंक प्रताप सिंह पंचम स्थान प्राप्त हुआ। इसी तरह आरएस एक्सेल इंग्लिश एकेडमी सिविल लाइंस में कनिष्ठ में प्रथम वानी तिवारी, द्वितीय आशू पटेल, तृतीय आर्मिश सैफी, मरियम शोभी चतुर्थ एवं पंचम स्थान में अरव मेहरा रहे। वरिष्ठ स्तर में प्रथम प्रियांश कुमार गुप्ता, द्वितीय दृष्टि सिंह, तृतीय इशिका अग्रहरि, चतुर्थ अमृता श्रीवास्तव एवं कृतिका तिवारी पंचम में प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में राजेश मिश्रा गीत गोविंद प्रकाशन से हार्दिक अग्रहरि, लैक्मे से मीनाक्षी गुप्ता एवं नीतू शर्मा उपस्थित रहे।

विद्युत विभाग के चेकिंग अभियान से लोगों में मचा हड़कम्प

चेकिंग अभियान की जानकारी देते एसडीओ व विजिलेंस टीम।

● काटे पैंतीस कनेक्शन वसूले साढ़े तीन लाख रुपये

गुरसहायगंज (कन्नौज)। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विद्युत उपखण्ड अधिकारी ने उपनिरीक्षक व अवर अभियंता सहित विजिलेंस टीम के साथ ग्राम रजलामऊ में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया। ग्रामीणों में हड़कम्प मच गया। विद्युत विभाग द्वारा करीब तीन दर्जन कनेक्सन काटे और आधा दर्जन पर कार्रवाई करते हुये लाखों रुपयो की राजस्व बसूली की है। गुरूवार को क्षेत्र के ग्राम रजलामऊ में उपखण्ड अधिकारी बृजेश कुमार सिरोही नें उप निरीक्षक टीपी सिंह, अवर अभियंता विकास कुमार एवं विजिलेंस टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाते हुये पैंतीस लोगों के केबल विच्छेदन किये और विद्युत चोरी करते रंगे हाथ पकडे गये छह लोगो पर मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही साढे तीन लाख रुपयों की राजस्व वसूली की।

डीएम व एसीपी ने परीक्षा केन्द्रों का सघन किया निरीक्षण

बाँदा। जिलाधिकारी नगेन्द्र प्रताप एवं अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र के साथ उप्र पुलिस भर्ती परीक्षा को जनपद में सकुशलढंग से नकल विहीन आयोजित कराये जाने हेतु जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्तए 2024 को जनपद बाँदा में चयनित 10 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा को नकलविहीनी, शान्तिपूर्ण व सुचितापूर्ण तरीके से सकुशल सम्पन्न कराये जाने की तैयारियों के सम्बन्ध में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि बांदा, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बाँदा, राजकीय इण्टर कॉलेज तिन्दवारा बाँदा, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज बाँदा एवं अन्य परीक्षा केन्द्रों का गहनता से निरीक्षण करते हुए पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की गयी तैयारियों का निरीक्षण किया।

उन्होंने परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, फर्नीचर, लाइट, पेयजल व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

परीक्षा के समय सभी ड्यूटी में लगे अधिकारीए कक्ष निरीक्षक, कर्मचारी अपने.अपने परिचय पत्र के साथ ही ड्यूटी पर रहेंगेए कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नही करेगा। उन्होंने प्रधानाचार्य को निर्देश दिए की प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी अवश्य लगे हो और निरन्तर संचालित रहेंए इसका कन्ट्रोल रूम भी बनाया जाए। परीक्षा केन्द्र के बाहर एक कक्ष निर्धारित कर सभी का मोबाइल फोन व सामग्री जमा करने हेतु व्यवस्था की जाए। उन्होंने परीक्षा केंद्र में आवश्यक फर्नीचर एवं समय से सीटिंग प्लान सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण तैयारी के साथ समय से आज सायं काल तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि इस कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने पाए। सभी परीक्षा केन्द्रों में बायोमैट्रिक उपस्थित भी की जायेगी।

उन्होंने निर्देशित किया कि सभी परीक्षार्थियों की गहनता से चेकिंग परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश से पूर्व अवश्य की जाए तथा कोई भी कर्मचारी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक घड़ी, डिवाइस, कैलकुलेटर आदि सामग्री लेकर नही जायेगा। परीक्षा केन्द्र के आस.पास कोई फोटोकॉपी की दुकान नही होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा के दौरान निर्बाद्ध विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी परीक्षा केदो में आवश्यक पुलिस व्यवस्था एवं सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई हैए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमिताभ यादव, क्षेत्राधिकारी पुलिस, सम्बन्धित कालेजों के प्रधानाचार्य तथा अन्य अध्यापक गण उपस्थित रहे।

क्विक न्यूज

सब्ज़ी लेने जा रहे युवकों की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर

संडीला (हरदोई)। बाइक से सब्ज़ी लेने के लिए जा रहे दो युवकों को अनियंत्रित गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। ग्राम भवानीपुर थाना कछौना निवासी सुधीर पुत्र विशुनदयाल तथा भवानीपुर निवासी गंगाराम पुत्र राम सिंह सब्ज़ी लेने के लिए अपनी कछौना चौराहे पर जा रहे थे। हरदोई की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे दोनों ही लोग सड़क पर उछलकर दूर जा गिरे। ट्रक मोटरसाइकिल को काफ़ी दूर तक खींचता हुआ ले गया। दोनों युवकों को इस दुर्घटना में गंभीर चोटें लगीं। दोनों को उठाकर पहले सीएचसी कछौना ले जाया गया जहां से दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। ट्रक चालक ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने ट्रक को रोक लिया तथा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

प्रेमिका से बिछड़ने पर खाया जहर, हुई मौत

फर्रूखाबाद। एक साथ जहर खाने वाले दोस्त दीपांशु उर्फसूरज की मौत हो जाने पर परिवार में मातम छा गया। दीपांशु उर्फ सूरज कोतवाली मोहम्मदाबाद के मोहल्ला किदवई नगर निवासी राजपाल शर्मा का 19 वर्षीय पुत्र था। दीपांशु के घर के सामने प्रमोद पाल का घर है प्रमोद पाल का 19 वर्षीय आकाश पाल व दीपांशु में दोस्ती थी। दोनों आज सुबह करीब 7.30 बजे घर से निकले थे। कही बाहर जाकर दोनो दोस्तों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों के बेहोश पड़े होने की जानकारी मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन को दीपांशु व आकाश को लोहिया अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान दीपांशु की मौत हो गयी। गंभीर रूप से बीमार आकाश का उपचार किया जा रहा है। दोनो दोस्त दिल्ली में अलग अलग नौकरी करते है। दीपांशु की मौत पर मां कुंती देवी आदि महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दीपांशु बीते सप्ताह दिल्ली से घर आया था, आते समय दीपांशु दिल्ली से किसी युवती को भगा लाया था। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया और दीपांशु को पकड़ कर ले गई थी। प्रेमिका के बिछड़ जाने से आहत दीपांशु ने जहर खाकर जान दी है। लेकिन उसके दोस्त के द्वारा जहर खाना अभी रहस्य बना हुआ है।

ग्रह कलह से तनाव में आकर विवाहिता ने डाई पीकर दी जान

फर्रूखाबाद। गृह कलह से तनाव में आयी विवाहिता नें डाई पी ली। जिससे उसकी मौत हो गयी। घटना के बाद ससुरालीजन फरार हो गये। पुलिस नें मामले की तहकीकात की। थाना राजेपुर के ग्राम पुरनपुर जिठौली निवासी 24 वर्षीय उपासना पत्नी अजीत सिंह का एक माह से ससुराल में विवाद चल रहा था। मिली जानकारी में मुताबिक उपासना नें गृहकलह के चलते घर में रखी डाई को पी लिया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार सोलंकी नें मौके पर आकर जाँच की। ग्राम सराह निवासी रामकृपाल की पुत्री उपासना का विवाह 11 जुलाई 2019 अजीत सिंह के साथ हुआ था। उपासना के आत्महत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार बताये गये। घटना के बाद उपासना के पति अजीत सिंह नें साले गोलू सिंह को जानकारी दी। जिसके बाद मृतका के स्वजन मौके पर आ गये। ससुराल पक्ष के मृतका के पति सहित सभी फरार हो गये। थानाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह सोलंकी नें बताया की शव का पोस्टमार्टम कराया जायेगा। विधिक कार्यवाही भी होगी।

महिला से चेन छीन कर फरार हुए बाइक सवार

फतेहपुर। घर से निकलकर भाई के घर जा रही एक महिला के साथ चेन स्नेचिंग की घटना हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े घटना को अंजाम दिया और मौके से भाग निकले। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सदर कोतवाली के फूलबाग कालोनी निवासी कमलेश सिंह पत्नी प्रेम सिंह गुरूवार दोपहर में अपने घर से निकलकर कुछ दूर रहने वाले अपने बड़े भाई के घर जाने के लिए निकली थीं। जैसे ही वह कुछ ही दूर निकली थीं कि तभी एक युवक उनके पास आया और गले से सोने की चेन छीनने का प्रयास करने लगा। चेन न छीन पाने से युवक ने कटर से चेन काट ली और आगे की ओर भागा। जहां एक बाइक में एक युवक हेलमेट लगाकर खड़ा था। बाइक में बैठकर बदमाश मौके से भाग निकला। शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर जांच पड़ताल शुरू कर दी।

पेपर लीक होने से बच्चों का भविष्य होता बर्बादः नरेश उत्तम

अमौली, फतेहपुर। केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पहले से ही लीक हो जाता है और इसका खुलासा होने से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होने जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की आवाज उठाई थी इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। यह बात गुरूवार को अमौली कस्बा स्थित राम सजीवन चंदा देवी महाविद्यालय में सपा के आयोजित छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कही।

छेड़खानी करने वाले को तीन वर्ष की कैद

हमीरपुर। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी के पिता ने थाना जरिया 19 मार्च 2016 को तहरीर दी थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 16 मार्च 2016 को समय करीब सात बजे सुबह अपने दरवाजे के सामने सफाई कर रही थी। तभी पड़ोस का जीतू पुत्र इंद्रजीत लोधी आया और इशारा करने के बाद बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। जिस पर उसने शोर मचाया तो वह जाति सूचक शब्दों से गालीगलौज करने लगा। शोर सुनकर किशोरी की भाभी आ गई तो जान की धमकी देता हुआ भाग गया। जिस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एससी एसटीए छेड़खानी व पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित जीतू के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष का कठोर कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदंड की लगाया है। वहीं अर्थदंड जमा न करने पर आरोपित को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बरौर के निलंबित प्रिंसपल प्रकरण में प्र.प. ने की प्रबंध समिति से वार्ता

आपस में विचार विमर्श करते पदाधिकारीगण

पुखरायां। कानपुर देहात। प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारियों ने गुरुवार को भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के पटेल विद्या पीठ इंटर कॉलेज का दौरा किया। परिषद के पदाधिकारियों ने प्रबंध समिति के सदस्यों से निलंबित प्रधानाचार्य अवधेश कुमार की बहाली करने की सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। प्रधानाचार्य परिषद के संरक्षक रविशंकर त्रिपाठी ने बताया कि प्रबंधक सत्येंद्र कुमार एवं सदस्य अमरनाथ के साथ हुई वार्ता के बाद निलंबित प्रधानाचार्य अवधेश कुमार ने गुरुवार को कार्यभार संभाल लिया है। प्रबंधक सत्येंद्र कुमार और प्रधानाचार्य अवधेश कुमार ने मिल जुलकर विद्यालय की व्यवस्था देखने को सहमत हुए। प्रबंधक सत्येंद्र कुमार ने प्रधानाचार्य अवधेश कुमार पर आराजकता करने का आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश प्रभारी कुलदीप दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. इन्द्र भूषण सिंह, डॉ. योगेश मिश्र, मुनि नाथ सचान, रमाकांत सचान, विनोद द्विवेदी एवं प्रधानार्चा वासुदेव तिवारी भी मौजूद रहे।

जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समितिः डीएम ने ली मासिक समीक्षा बैठक, दिए निर्देश

लखीमपुर खीरी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की मासिक समीक्षा बैठक लीए संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने निर्देश दिया कि विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान शिक्षा की गुणवत्ताए मिड.डे.मील सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लें तथा यह सुनिश्चित कराएं कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले। सभी बीईओ पंजीकृत छात्रों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ.साथ इस बात को भी सुनिश्चित करें कि सभी छात्र प्रापर ड्रेस, जूताए मोज़ा व स्वेटर पहन कर विद्यालयों में आयें।

डीएम ने बीएसए को निर्देशित किया कि शिक्षकों द्वारा शिक्षक संदर्शिका व शिक्षक डायरी का अनिवार्यता से दैनिक प्रयोग किया जाए। न्यून अधिगम स्तर वाले छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कराए। समस्त शिक्षक.शिक्षिकाएं शिक्षक सन्दर्शिका के अनुरूप ही शिक्षण कार्य करें, जिससे छात्रों को निपुण बनाने में सहजता और शीघ्रता हो। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने प्रत्येक माह के अंतिम बुधवार को सभी परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक .शिक्षक बैठक आयोजित की जाए। निर्देश दिए कि इन बैठकों में सुपरवाइजरी अफ्सरो की ड्यूटी भी लगाई जाए। इन बैठकों में अच्छी उपस्थिति वाले बच्चों के अभिवावको को सम्मानित किया जाए। कम अटेंडेंस वाले अभिभावकों की काउंसलिंग भी की जाए। 03 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने पर शिक्षक संबंधित बच्चों के घर पर विजिट करें।

डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में माह के प्रथम दिन विद्यालय में नामांकित छात्रों में से उसे माह में जन्मे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाए। जन्मदिन वाले बच्चे के हाथो से अन्य साथी बच्चों को टाफ्फिा का वितरण कराया जाए।

साजिश रचकर पुत्र की हत्या किए जाने का आरोप

एसपी कार्यालय में ग्रामीणों संग खड़े मृतक के परिजन।

फतेहपुर। एक माह पूर्व ललौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला पूर्वी कृष्णा नगर बहुआ में श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर भंडारा व कीर्तन के दौरान वाद यंत्र बजाते समय करंट की चपेट में आने से हुई युवक की मौत के मामले में परिजनों ने साजिश रचकर उनके पुत्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया तत्पश्चात एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से मुकदमा पंजीकृत करवाए जाने की गुहार लगाई है।

गाजीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लिलरा गांव निवासी रामस्वरूप पुत्र देवीदीन ग्रामीणों संग गुरूवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। जहां उन्होने प्रदर्शन करते हुए एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा। जिसमें बताया कि उनका पुत्र विनय कुमार आरगन वाद यंत्र बजाने का कलाकार था। ललौली थाना क्षेत्र के लदिगवां गांव निवासी दीपू कुशवाहा भी आरगन वाद यंत्र बजाता है। 22 जुलाई को श्रावण मास के प्रथम सोमवार को जय भोले भंडारी कमेटी बहुआ के अध्यक्ष व संचालक मनीष शिवहरे पुत्र कामता शिवहरे ने ललौली थाने के मोहल्ला पूर्वी कृष्णा नगर बहुआ में भंडारे व कीर्तन का आयोजन किया था। जिसमें उनका पुत्र विनय कुमार वाद यंत्र बजाने गया था। वाद यंत्र बजाने वाला दीपू कुशवाहा उनके पुत्र से खुन्नस रखता था। दीपू कुशवाहा का बहनोई राम बाबू कुशवाहा निवासी कोरारी थाना ललौली लाइट व टेंट का काम करता है। भंडारे में रामबाबू कुशवाहा का टेंट व लाइट जनरेटर आदि लगा हुआ था। उनके पुत्र को आरगन वाद यंत्र बजाने के लिए दीपू व रामबाबू कुशवाहा की साजिश से अतुल यादव पुत्र ननकाई निवासी बावन थाना गाजीपुर घर से बुलाकर ले गए। स्टेज पर बैठाकर आरगन बजा रहा था तभी बिजली का कटा हुआ तार साजिशन डाल दिया। जिससे करंट की चपेट में आकर उनके पुत्र की मौत हो गई। सूचना ललौली थाने में भी दी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और थाने से भगा दिया। वह लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

टीएसआई ने काटे चालीस वाहनों के चालान, मचा हड़कम्प

वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाईजर मशीन से चेकिंग करते टीएसआई।

● स्कूली वाहनों को चेक कर बताये यातायात के नियम

गुरसहायगंज (कन्नौज)। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी यातायात डा. प्रियंका बाजपेई एवं यातायात प्रभारी आआफाक खॉन के पर्यवेक्षण में टीएसआई अरशद अली द्वारा हाईवे के किनारे खतरनाक ढंग से खड़े ट्रकों के चालान किए गए। गुरूवार को टीएसआई अरशद अली द्वारा हाईवे के किनारे ढाबों के आसपास खड़े ट्रकों सहित रॉन्ग साइड में चलने वाले वाहनों के चालान किये जा रहे हैं। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों एवं स्कूली वाहनों को भी यातायात पुलिस लगातार चेक कर रही है और चालकों को जागरुक भी किया जा रहा है। टीएसआई द्वारा करीब चालीस वाहनों के चालान काटे गए। उधर नगर में टीएसआई द्वारा 01 मोटर साइकिल व 02 श्री व्हीलर को सीज कर कोतवाली में खडा कराया गया। टीएसआई द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम किया जाएगा क्योंकि रात्रि के समय वाहनों का दिखाई पड़ना बेहद जरूरी है।

जिले के नौ परीक्षा केन्द्रों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा

● पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिले में तैयारी पूरी

●एक शिफ्ट में 2800 के लगभग परीक्षार्थी होंगे शामिल

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा 9 अलग-अलग केंद्रों पर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा देने का मौका मिले। प्रत्येक दिन एक शिफ्ट में लगभग 2800 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा। यह कदम परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बायोमेट्रिक जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना को खत्म किया जा सके।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए, जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास के सभी साइबर कैफे और फोटोकॉपी की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहेगा, जो केंद्रों पर निगरानी रखेगा और शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

आधार के सत्यापन को लेकर दो घंटे पहले पहुंचे

सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में अपने आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया है, उन्हें अनिवार्य रूप से दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा। अन्य अभ्यर्थियों को भी इसी तरह दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व किसी को भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

इन सामग्रियों पर रहेगा प्रतिबंध

परीक्षा केंद्र पर पाठ्य सामग्री, कागज के टुकड़े, ज्यामितीय-पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबिल, इलेक्ट्रानिक पेन, स्कैनर, डिजिटल पेन, मोबाइल, चाभी, कैमरा, घड़ी, ज्वेलरी, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैंड प्रतिबंध रहेगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को प्रसिद्ध जीव रसायन वैज्ञानिक और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंदराजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार की इस साल शुरुआत की है। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडपम में आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने 13 विज्ञान श्री पुरस्कार, 18 विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और एक विज्ञान टीम पुरस्कार भी प्रदान किए। चंद्रयान-3 मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार मिशन के परियोजना निदेशक पी वीरमुथुवेल ने प्राप्त किया। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया गया।

विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए वैज्ञानिकों में बेंगलुरू स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यमअ तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक आनंदरामकृष्णन सीअ भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान में रसायन विज्ञान समूह के निदेशक आवेश कुमार त्यागीअ लखनऊ स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर सैयद वजीह अहमद नकवी शामिल हैं। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के जीवविज्ञानी उमेश वार्ष्णेय, पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उदगांवकर, आईआईटी दिल्ली के एमेरिटस प्रोफेसर भीम सिंह, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक संजय बिहारी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आदिमूर्ति आदि, आईआईएम कोलकाता के राहुल मुखर्जी को भी विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किया गया।

इनके अलावा साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान के भौतिक विज्ञानी नबा कुमार मंडल और भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली के लक्ष्मणन मुथुस्वामी और प्रो. रोहित श्रीवास्तव

(प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष) को विज्ञान श्री से सम्मानित किया गया।

विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर विवेक पोलशेट्टीवार और आईआईएसईआर-भोपाल के प्रोफेसर विशाल राय, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के कृष्णमूर्ति एस एल और राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के स्वरूप कुमार परिदा को प्रदान किया गया। आईआईएसईआर-भोपाल की प्रोफेसर राधाकृष्णन महालक्ष्मी, सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर के अभिलाष आईआईटी-मद्रास के राधा कृष्णअ झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की पूर्बी सैकियाअ राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर के बप्पी पॉल विज्ञान युवा पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शामिल थे। इनके अलावा पुणे स्थित आईसीएमआर- राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की प्रज्ञा ध्रुव यादव, चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार साहूअ आईआईएससी, बेंगलुरु के महेश रमेश काकड़े विज्ञान युवा पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शामिल थे। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु की उर्वशी सिन्हा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम के दिगेंद्रनाथ स्वैन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद के प्रशांत कुमार और आईआईटी-मद्रास के प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल को भी विज्ञान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रशिक्षु पायलट व प्रशिक्षक का शव मिला, विमान की तलाश जारी

भाषा। जमशेदपुर

झारखंड के जमशेदपुर स्थित हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लापता हुए दो सीट वाले विमान में सवार प्रशिक्षु पायलट और प्रशिक्षण देने वाले पायलट का शव बृहस्पतिवार को चांडिल बांध में पाया गया जबकि विमान की तलाश जारी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एक निजी उड़ान प्रशिक्षण संस्थान अलकेमिस्ट एविएशन का विमान सेसना 152 मंगलवार सुबह सोनारी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था, जिसके बाद बांध के जलाशय सहित आस-पास के इलाकों में इसका पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर खोजबीन अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि विमान के चांडिल बांध के आस-पास दुर्घटनाग्रस्त होने का संदेह था।

अधिकारियों ने कहा कि आदित्यपुर निवासी प्रशिक्षु पायलट शुभ्रोदीप दत्ता का शव सुबह मिला, जबकि पटना निवासी पायलट कैप्टन जीत शत्रु आनंद का शव बाद में मिला। उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम से आई नौसेना की 19 सदस्यीय टीम लापता विमान की तलाश में लगातार जुटी है। अधिकारियों के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी), उड़ान प्रशिक्षण निदेशालय (डीएफटी) और उड़ान योग्यता निदेशालय (डीएडब्ल्यू) के साथ घटना की जांच शुरू कर दी है।

वीटी-टीएजे के रूप में पंजीकृत विमान का स्वामित्व और संचालन करने वाली अल्केमिस्ट एविएशन ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना के कारणों के बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। इसने कहा, विमान में 80 लीटर ईंधन था और यह साढ़े चार घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम था तथा उड़ान का समय एक घंटा निर्धारित था। बयान में कहा गया कि मंगलवार पूर्वाह्न करीब 11.10 बजे विमान का संपर्क जमशेदपुर हवाई नियंत्रण कक्ष (एटीसी) से टूट गया। अल्केमिस्ट एविएशन ने कहा कि विमान डीजीसीए द्वारा जारी उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र के साथ उड़ान योग्य स्थिति में था और इसमें मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा निर्मित इंजन लगाया गया था। बयान में कहा गया कि अमेरिकी कंपनी लाइकमिंग इंजन के इंजन से युक्त इस विमान का संचालन काल 30,000 घंटे का होता है, जिसमें से इसने केवल 16,000 घंटे पूरे किए थे। इसने कहा गया कि बांध में एक जोड़ी जूते तैरते पाए गए, जिसके बाद उन्हें बरामद करके पहचान की गई।

कंपनी ने कहा, इससे हमें यह आशंका हुई कि घटनास्थल बांध ही होगा। प्रारंभिक खोज टाटा स्टील के हेलीकॉप्टर और हमारे अपने विमान द्वारा की गई। इसके बाद मौसम खराब हो गया और खोजबीन अभियान जमीन पर वाहनों के जरिए चलाया गया तथा स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद स्थानीय सरकारी अधिकारियों को सूचित किया गया और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की मदद से बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। इसके बाद भारतीय नौसेना को मदद के लिए बुलाया गया और उसने एक सोनिक नेविगेशन एंड रेंजिंग (सोनार) उपकरण तैनात किया जो घटना की सटीक स्थिति को चिह्नित करने में सहायता करेगा।

एकनाथ खडसे ही भाजपा में वापसी के बारे में बता सकतेः मंत्री रक्षा खडसे

मुंबई। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने बृहस्पतिवार को कहा कि केवल उनके ससुर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पूर्व विधान पार्षद (एमएलसी) एकनाथ खडसे ही भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल होने की अपनी योजना का खुलासा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक रहे एकनाथ खडसे को 2016 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया। खडसे ने 2020 में पार्टी छोड़ दी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (अविभाजित) में शामिल हो गए। खडसे ने इस साल अप्रैल में राकांपा के विधान परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था और ऐसी अटकलें थीं कि वह फिर से भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन तब से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। अपने ससुर की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने संवाददाताओं से कहा, केवल नाथाभाऊ (एकनाथ खडसे इसी नाम से लोकप्रिय हैं) ही भाजपा में वापसी के समय के बारे में बता सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रमुख नेता एकनाथ खडसे को महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है और विधाई प्रक्रियाओं में उनकी कुशलता के लिए अक्सर उनकी सराहना की जाती है।

पायलट बाबा को दी गई भूसमाधि

भाषा। हरिद्वार

श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमनाथ गिरि उर्फ पायलट बाबा को बृहस्पतिवार को यहां उनके कनखल आश्रम में भूसमाधि दे दी गई। पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। पायलट बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां बड़ी संख्या संतों के अलावा देश-विदेश से उनके अनुयाई आए थे। पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने भी आश्रम पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान, साधु-संतों के सभी 13 अखाडों के पदाधिकारी, महामंडलेश्वर, श्रीमहंत, महंत, विभिन्न दलों के नेता, देश के बड़े उद्योगपति और कारोबारी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमहंत हरि गिरि महाराज की देखरेख में पायलट बाबा को अभिजीत मुहूर्त में पूर्वाह्न 11 बजकर 55 मिनट पर भूसमाधि दी गई। पायलट बाबा की शिष्या महामंडलेश्वर साध्वी चेतनानंद गिरि व साध्वी श्रद्धा गिरि ने उन्हें समाधि दी। पायलट बाबा की जापानी शिष्या योगमाता केको आइकवा भी इस दौरान मौजूद रहीं।

श्री महंत हरी गिरि महाराज ने पायलट बाबा को सिद्ध संत बताते हुए कहा कि वह समाज, देश व धर्म की सेवा के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने बताया कि संन्यासी बनने से पूर्व पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और उन्होंने 1962, 1965 व 1971 के युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने बताया कि बाद में युद्ध की विभीषिका से आहत पायलट बाबा ने 1974 में संन्यास ले लिया और विधिवत दीक्षा लेकर जूना अखाड़े में शामिल हो गए।

पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पायलट बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के रूप में उन्होंने जहां देश सेवा की मिसाल कायम की, वहीं एक सच्चे व सिद्ध संत के रूप में उन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का मार्गदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि पायलट बाबा ने जीवित रहते हुए कई बार जल समाधि, एयर टाइट ग्लास रूम में कई दिन तक योग साधना के बल पर दुनिया को सनातन और योग शक्ति से रूबरू कराया था।

अखाडा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने भी पायलट बाबा को उच्च कोटि का योगी बताते हुए कहा कि उनके देहावसान से सनातन की अपूरणीय क्षति हुई है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर पायलट बाबा मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में ब्रह्मलीन हो गए थे। उनके पार्थिव शरीर को बुधवार को यहां कनखल स्थित उनके आश्रम लाया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।

महाराष्ट्र सरकार बंबई उच्च न्यायालय की इमारत के लिए भूमि सात सितंबर तक उपलब्ध कराए : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह सात सितंबर तक एक आदेश जारी करके बंबई उच्च न्यायालय को नई इमारत के निर्माण के लिए बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भूमि उपलब्ध कराए। शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय की ऐतिहासिक इमारत और उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन शीर्षक वाले मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की भवन परियोजना को महत्वपूर्ण घोषित करने के लिए एक और आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया। इस निर्देश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण परियोजना प्रभावित नहीं हो। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की विशेष पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुंबई की एक इमारत के कुछ हिस्से का कब्जा सौंपने के संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के साथ समन्वय करने के लिए भी कहा ताकि वहां उच्च न्यायालय की कुछ सुविधाओं को स्थानांतरित किया जा सके। अदालती कार्यवाही की शुरुआत में पीठ ने मामले में अब तक हुई प्रगति के बारे में पूछा। महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कहा कि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और राज्य सरकार उच्च न्यायालय को जमीन का कब्जा सौंपने के लिए कदम उठा रही है।

कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमे की अनुमति पर फैसले के लिए राज्यपाल को सलाह देंगेः कर्नाटक मंत्रिमंडल

बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने जनता दल (सेक्युलर) नेता एवं केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी तथा खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी सहित भाजपा के तीन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध पर निर्णय के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सहायता और सलाह देने का बृहस्पतिवार को फैसला किया। कांग्रेस सरकार ने यह कदम मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाले में 16 अगस्त को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के एक सप्ताह के भीतर उठाया है। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, लंबित मामलों में जल्द से जल्द निर्णय लेने तथा न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिमंडल राज्यपाल को सहायता एवं सलाह दे सकता है। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने को अपनी मंजूरी दी है। पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, सलाह राज्यपाल को भेजी जाएगी। जिन चार लंबित मामलों में हमने सहायता और सलाह दी है, इनमें से दो मामलों (जनार्दन रेड्डी और कुमारस्वामी) में आरोप-पत्र दायर किए जा चुके हैं...। पाटिल से जब यह पूछा गया कि क्या राज्यपाल मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह को अस्वीकार कर सकते हैं, उन्होंने कहा, हमारे अनुसार, वह हमारी सलाह मानने को बाध्य हैंअ उनका विवेकाधिकार सीमित है। मुझे यकीन है कि वह अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल बहुत विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे। राज्यपाल ने 16 अगस्त को सिद्धरमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधि., 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत एस पी प्रदीप कुमार, टी जे अब्राहम और स्नेहमई कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। पाटिल ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी मांगने वाली कई अर्जी राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं, जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाएं भी शामिल हैं इनमें से कुछ मामलों में आरोप-पत्र भी दायर किए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि इन अर्जियों में से विशेष अर्जी पूर्व मंत्री शशिकला जोले के विरुद्ध हैं, जिनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने नौ दिसंबर, 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। (भाजपा के पूर्व मंत्री) मुरुगेश निरानी के खिलाफ इसी कानून की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए 26 फरवरी, 2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तीसरी अर्जी कुमारस्वामी मामले को लेकर है, जिनके खिलाफ 21 नवंबर 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अर्जी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत मंजूरी मांगी गई है। पाटिल ने कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है और राज्यपाल ने 29 जुलाई, 2024 को मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसपर इसने (एसआईटी ने) 16 अगस्त, 2024 को आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिया है। चौथा मामला रेड्डी से संबंधित है, जिनके खिलाफ 13 मई, 2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 और बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत मंजूरी मांगने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्यपाल द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब जांच एजेंसियों ने दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्वाई नहीं की गई है। जनता की नजर में राज्यपाल का कार्यालय गलत काम करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हमें लगा कि यह सहायता और सलाह देना उचित है। सिद्धरमैया के मामले में एक निजी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि इन चार मामलों में जांच हो चुकी है और दो मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

श्याम रजक ने राजद से इस्तीफा दिया

पटना। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने बृहस्पतिवार को राजद से इस्तीफा देते हुए धोखा दिए जाने का आरोप लगाया। रजक ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को संबोधित एक संक्षिप्त पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद के साथ-साथ दल की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहे हैं। रजक ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद को संबोधित अपने पत्र में लिखा है, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था।

कांग्रेस ने केरल सरकार से हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने को कहा

तिरुवनंतपुरम, कोच्चि। कांग्रेस ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर हेमा समिति की रिपोर्ट के संबंध में बृहस्पतिवार को केरल सरकार से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष के. सुधाकरन ने संवाददाताओं से कहा कि अगर 2026 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुधाकरन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि समिति की जिस रिपोर्ट में महिलाओं और यहां तक कि नाबालिग लड़कियों के साथ विभिन्न अत्याचारों के संबंध में गंभीर जानकारी दी गई है उसे वर्षों तक रोक कर रखा गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को इतने लंबे समय तक लटकाए रखने का निर्णय उचित नहीं ठहराया जा सकता।

सुधाकरन ने कहा, कांग्रेस हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्वाई की मांग करती है। विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने दावा किया कि न्यायमूर्ति हेमा ने राज्य सरकार से रिपोर्ट जारी न करने के लिए कभी नहीं कहा। सतीशन ने उनके द्वारा पहले भी लगाए गए आरोपों को दोहराया और सरकार पर शिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

सतीशन ने कोच्चि में संवाददाताओं से कहा, हेमा समिति ने सरकार से रिपोर्ट जारी न करने को कभी नहीं कहा, बल्कि उसने इसे जारी कर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने पीड़ितों के नामों का खुलासा न करने का निर्देश दिया है और उसका निर्देश रिपोर्ट पर कार्वाई करने के खिलाफ नहीं है। सतीशन ने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रुख स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोई शिकायत देता है तो मामला दर्ज किया जा सकता है।

सतीशन ने कहा, प्रस्तावित सिनेमा सम्मेलन में आरोपी भी पीड़िताओं के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे। सिनेमा सम्मेलन नारीत्व का अपमान होगा। सतीशन ने राज्य सरकार द्वारा फिल्म उद्योग के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रस्तावित दो दिवसीय सिनेमा सम्मेलन का जिक्र करते हुए यह बात कही। विपक्षी कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस दावे को बुधवार को नकार दिया कि न्यायमूर्ति हेमा ने खुद उनसे मलयालम फिल्म उद्योग पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक न करने का अनुरोध किया था। यूडीएफ ने इसे सरासर झूठ और पाखंड बताया। राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि (हेमा) समिति ने बयान दर्ज करने और रिपोर्ट सौंपते समय सभी कानूनी पहलुओं पर गौर किया होगा।

बायजू मामले में सीओसी को बैठक न करने का अंतरिम आदेश देने से न्यायालय का इनकार

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने वित्तीय संकट से घिरी शिक्षा-प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही जारी रखने के लिए कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को कोई बैठक नहीं आयोजित करने का अंतरिम आदेश देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह 27 अगस्त को इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक होने वाले घटनाक्रमों को वह नकार सकती है अगर उसे यह लगता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले के खिलाफ अमेरिका की कर्जदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी की तरफ से दायर अपील में कोई दम नहीं है।

बायजू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक दिन पहले सीओसी का गठन कर दिया गया है और 98 प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी के पास है।

बायजू का संचालन करने वाली मूल कंपनी थिंक एंड लर्न को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें एड-टेक प्रमुख के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को अलग रखा गया था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ 158.9 करोड़ रुपए के बकाया निपटान को मंजूरी दी गई थी। इससे पहले दो अगस्त का अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला बायजू के लिए बड़ी राहत लेकर आया था क्योंकि इसने प्रभावी रूप से संस्थापक बायजू रवींद्रन को फिर से नियंत्रण में ला दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी के फैसले को प्रथम दृष्टया अनुचित करार देते हुए रोक लगा दी थी।

यह मामला बीसीसीआई के साथ एक प्रायोजन सौदे से संबंधित 158.9 करोड़ रुपए के भुगतान में बायजू की चूक से जुड़ा है। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को निर्देश दिया था कि वह बायजू से समझौते के बाद प्राप्त 158 करोड़ रुपए की राशि को अगले आदेश तक एक अलग एस्क्रो खाते में रखे। बायजू ने 2019 में बीसीसीआई के साथ टीम प्रायोजक समझौता किया था। कंपनी ने 2022 के मध्य तक अपने दायित्वों को पूरा किया, लेकिन 158.9 करोड़ रुपए के बाद के भुगतानों में चूक कर गई।

पेज 1 का शेष

एफआईआर...

तब तक सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने कहा कि घटना में पहली एफआईआर रात 11.45 बजे पीड़िता के दाह संस्कार के बाद ही दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा, शुरुआत में, अधिकारियों ने माता-पिता को बताया कि यह आत्महत्या थी, लेकिन बाद में इसे मौत की श्रेणी में रखा गया। पीठ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की भूमिका पर भी पश्चिम बंगाल सरकार से पूछताछ की, जो इस भयानक अपराध के बाद संदेह के घेरे में आ गए हैं। दोपहर के भोजन के बाद जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, अदालत ने पूछा कि घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में 14 घंटे की देरी का क्या कारण था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के संपर्क में कौन था? उन्होंने देरी क्यों की एफआईआर में उद्देश्य क्या था? पीठ ने टिप्पणी की, प्रक्रिया एक अलग मसला है, लेकिन मुद्दा अभी भी बना हुआ है। शव मिलने के लगभग 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करने का क्या कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आना चाहिए था और निर्देश देना चाहिए था। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा, जिस क्षण प्रिंसिपल इस्तीफा देता है, उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है। सुनवाई के दौरान, रिकॉर्ड देखने के बाद, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा, कुछ बहुत परेशान करने वाला है। अप्राकृतिक मौत के संबंध में जीडी प्रविष्टि सुबह 10.10 बजे दर्ज की गई है। इसलिए पुलिस स्टेशन है सूचित किया गया कि अप्राकृतिक मौत हुई है। इस सब के बावजूद, अपराध स्थल की सुरक्षा, जब्ती आदि रात के 11.30 बजे होती है? सिब्बल ने दावा किया कि यह गलत जानकारी थी और दावा किया कि सभी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई थी। शुरुआत में मेहता ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपराध के पांचवें दिन जांच शुरू की। हमने पांचवें दिन जांच शुरू की। इससे पहले, स्थानीय पुलिस ने जो कुछ भी एकत्र किया था वह हमें दे दिया गया था। जांच अपने आप में एक चुनौती थी क्योंकि अपराध स्थल बदल दिया गया था। (पीड़िता के) दाह संस्कार के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई थी रात 11.45 बजे। मेहता ने कहा, पहले, पीड़िता के माता-पिता को (अस्पताल के) उपाधीक्षक ने सूचित किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब वे अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है... सौभाग्य से, उसके सहकर्मी खुश थे मृतक ने वीडियोग्राफी के लिए जोर दिया। इससे पता चलता है कि उन्हें मामले को छिपाने का संदेह था। सिब्बल ने मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि हर चीज की वीडियोग्राफी की गई थी और दावा किया कि अपराध स्थल पर कुछ भी बदलाव नहीं किया गया था। उन्होंने दलील दी कि कोलकाता पुलिस ने प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया और सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट केवल मामला खराब करने का प्रयास करती है।

सुप्रीम कोर्ट...

करते हैं और उसके निर्देशों का पालन करने का आह्वान करते हैं। रोगी की देखभाल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों के संघ ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और उनकी मांगों को संबोधित करने में हुई प्रगति को देखते हुए, वे शुक्रवार आठ बजे सुबह से अपना काम फिर से शुरू करेंगे।

अलकायदा...

गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। पुलिस उपायुक्त (पब्लिक रिलेशन ऑफिस) सुमन नलवा ने कहा, संचालन की वर्तमान स्थिति के अनुसार, मॉड्यूल का नेतृत्व रांची (झारखंड) के एक डॉ. इश्तियाक द्वारा किया जा रहा था, और यह खिलाफत घोषित करने और देश के भीतर गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का इच्छुक था। अल कायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को चरमपंथी विचारधाराओं से प्रेरित किया गया था और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षित भी किया जा रहा था। मॉड्यूल के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर सिद्धांत और हथियार प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। छह लोगों को राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में लिया गया, जब वे हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे थे, और आठ लोगों को पूछताछ के लिए झारखंड और उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया गया। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के जंगलों सहित विभिन्न स्थानों पर हथियार चलाने सहित प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने कहा कि संदिग्धों को पकड़ने के लिए पहाड़ी के जंगलों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से तीन और लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल विभिन्न स्थानों पर पूछताछ चल रही है और ऑपरेशन जारी रहने के कारण मामले में अतिरिक्त गिरफ्तारियों की भी उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि हथियार, गोला-बारूद और साहित्य बरामद करने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। बयान में कहा गया, इसके अलावा, अब तक रांची में 15, राजस्थान में एक और अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में एक जगह पर छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि संदेह है कि मॉड्यूल आगामी त्योहारी सीजन के दौरान भारत के उत्तरी हिस्से में एक आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। ऑपरेशन की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अल कायदा मॉड्यूल पिछले कुछ महीनों से सक्रिय है और इसके सदस्य सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि स्पेशल सेल ने 15 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था और तब से, आतंकवाद विरोधी इकाई संदिग्धों का विवरण एकत्र कर रही थी।

जम्मू-कश्मीर....

दिया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर बोलते हुए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 'हमारे स्थानीय नेताओं' के फीडबैक के आधार पर गठबंधन बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा, हम पूरे विपक्ष को साथ रखना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस राज्य की वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू-कश्मीर में चुनाव सुनिश्चित नहीं कर सकती। एआईसीसी प्रमुख ने कहा, पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर दबाव में चुनाव की घोषणा की। मैं यह रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि भाजपा अब जम्मू-कश्मीर में लोगों की आवाज को दबा नहीं सकती है। कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू-कश्मीर के बारे में खड़गे ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले क्षेत्र के लोगों से जो वादा किया था, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है।

असम...

सरमा ने कहा कि असम सरकार मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए चल रहे शरद ऋतु सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। यहां कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि सरकार असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024 पेश करेगी। पिछले महीने, कैबिनेट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और 1935 के नियमों को खत्म करने के लिए निरसन विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जो विशिष्ट शर्तों के तहत कम उम्र में विवाह की अनुमति देता था। असम मंत्रिमंडल ने राज्य में बाल विवाह के सामाजिक खतरे को समाप्त करने के लिए 23 फरवरी को अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय को मंजूरी दे दी थी। विपक्षी दलों ने इस फैसले की निंदा की थी और इसे चुनावी वर्ष में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया 'मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण' बताया था।

दिल्ली में...

दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने आरोप लगाया कि चालकों को धमकाया जा रहा है। उनका संघ हड़ताल का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, कई चालक हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं। रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप के बाहर चालकों को धमकाया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि पुलिस इन जगहों के बाहर निगरानी बढ़ाए।

वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक

सदस्यों ने कई प्रावधानों पर उठाए सवाल

भाषा। नई दिल्ली

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने प्रस्तावित कानून के कई प्रावधानों पर विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों के बीच बृहस्पतिवार को पहली मैराथन बैठक की। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से एक प्रस्तुति दी गई। बैठक के दौरान कई बार तीखी बहस हुई लेकिन विभिन्न दलों के सदस्यों ने कई घंटे तक बैठकर विधेयक के प्रावधानों पर अपने विचार दर्ज कराए, सुझाव दिए और स्पष्टीकरण मांगा। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के ए. राजा के साथ कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने जिलाधिकारी को और अधिकार देने और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को रखने सहित कई प्रावधानों की आवश्यकता पर सवाल उठाए।

कुछ सदस्यों ने कहा कि मंत्रालय बैठक में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं दिखा। समिति के एक सदस्य ने बताया कि इसकी अगली बैठक 30 अगस्त को होगी। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि समिति विभिन्न मुस्लिम निकायों सहित सभी हितधारकों से बात करेगी। संसद ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को विवादास्पद विधेयक की जांच करने का काम सौंपा है। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विधेयक पर प्रस्तावित संशोधनों पर समिति को जानकारी देंगे। पाल ने बैठक से पहले कहा कि समिति विधेयक पर विस्तार से चर्चा करेगी और इससे जुड़ी चिंताओं पर भी विमर्श करेगी। उन्होंने कहा कि समिति विभिन्न हितधारकों की आवाज सुनेगी। उन्होंने कहा, हम सभी 44 संशोधनों पर चर्चा करेंगे और अगले सत्र तक एक अच्छा और व्यापक विधेयक लाएंगे। पाल ने कहा कि समिति विभिन्न पंथों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न मुस्लिम संगठनों को बुलाएगी ताकि उनके विचार सुने जा सकें। यह विधेयक भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार की पहली बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करना है। यह कई सुधारों का प्रस्ताव करता है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य वक्फ बोर्डों समेत एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना शामिल है। विधेयक का एक विवादास्पद प्रावधान, जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है कि क्या संपत्ति को वक्फ या सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विधेयक को आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और बहस के बाद संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। सरकार ने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित कानून मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखता है जबकि विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उठाया गया कदम और संविधान पर हमला बताया।

पर्सनल लॉ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा- नीतीश और नायडू ने हमें वक्फ विधेयक का विरोध करने का यकीन दिलाया

नई दिल्ली। (भाषा) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है जिसमें दोनों नेताओं ने यकीन दिलाया कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे। रहमानी ने कुछ शीर्ष मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की। नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) और नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की प्रमुख घटक हैं। रहमानी ने यह भी कहा कि केंद्र को यह विधेयक वापस लेना चाहिए और अगर यह विधेयक संसद में पारित करने के लिए पेश किया गया तो इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा तथा कानून के दायरे में रहते हुए प्रत्एक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस संवाददाता सम्मेलन में रहमानी के अतिरिक्त जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, जमात-ए-इस्लामी हिंद के अमीर सआदतुल्ला हुसैनी, मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्रमुख मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी, पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी और पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास मौजूद थे। यह पूछे जाने पर कि क्या जद(यू) और तेदेपा के नेताओं से भी मुलाकात हुई है और उनका क्या रुख है, तो रहमानी ने कहा, हम लोगों की मुलाकातें अलग-अलग विपक्षी दलों के नेताओं से हुई है। चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वह इस विधेयक का विरोध करेंगे। कल (बुधवार को) नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि वह इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव (राजद नेता) से मुलाकात हुई और उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि वह इसका विरोध करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वक्फ पर सरकार को हाथ नहीं रखने दिया जाएगा। उनका कहना था कि कई अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और राजग के सहयोगी दलों ने भी विधेयक का विरोध करने का विश्वास दिलाया है। नीतीश और नायडू से मुलाकात के विवरण के बारे में पूछे जाने पर रहमानी ने कहा, हम इस बारे में विस्तार से नहीं बता सकते। हम उनसे मिल चुके हैं। ए कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ए न्याय और अन्याय का मसला है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाजपा के सहयोगियों सहित सभी धर्मनिरपेक्ष दल न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मद्देनजर हमारा समर्थन करें। मुस्लिम संगठनों ने उस दिन संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया जिस दिन वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक हुई। जमीयत प्रमुख अरशद मदनी ने आरोप लगाया कि मसला सिर्फ वक्फ का नहीं, बल्कि मसला यह है कि हिंदुस्तान के संविधान में अल्पसंख्यकों को जो आजादी दी गई है, मौजूदा सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है।

लापता बच्चों और महिलाओं का पता लगाना सरकार का कर्तव्य : बंबई उच्च न्यायालय

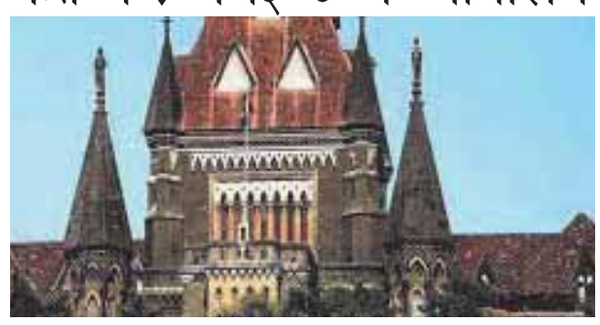

मुंबई। (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि लापता बच्चों और महिलाओं का पता लगाना सरकार का कर्तव्य है।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने मानव तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) से भी जवाब मांगा तथा इसे रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएससीडब्ल्यू) से सुझाव आमंत्रित किए। सांगली निवासी शाहजी जगताप की ओर से दायर जनहित याचिका में राज्य पुलिस को 2019 और 2021 के बीच महाराष्ट्र में लापता हुईं एक लाख से अधिक महिलाओं का पता लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में लापता महिलाओं और बच्चों के मामलों में राज्य के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही निष्क्रियता पर चिंता जताई गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता मंजरी पारसनीस ने बृहस्पतिवार को अदालत को सूचित किया कि जगताप की अपनी बेटी लापता है। अधिवक्ता ने बताया कि बेटी की तलाश के दौरान उनके मुवक्किल को 14 मार्च, 2023 को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े मिलेअ जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में लापता बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। मंत्रालय के मुताबिक, 2019, 2020 और 2021 में, लापता बच्चों की संख्या क्रमश: 4,562, 3,356 और 4,129 थी। इसी तरह, इन तीन वर्षों में महाराष्ट्र में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लापता होने के एक लाख से अधिक मामले सामने आए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों और महिलाओं के लापता होने के कई कारण हो सकते हैं। पीठ ने कहा, लेकिन उनका पता लगाना और उनकी सुरक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित आश्रय देना राज्य का कर्तव्य है। लापता बच्चों और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या का एक कारण संभवत: मानव तस्करी का खतरा है, जिसके लिए सभी सरकारी विभागों, पुलिस, रेलवे और अन्य विभागों के सभी अधिकारियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अक्टूबर की तारीख तय की है।

खाद्य सुरक्षा नियामक का दूध, दही से ए-वन, ए-टू के दावों को हटाने का आदेश

नई दिल्ली। (भाषा) खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने बृहस्पतिवार को ई-कॉमर्स सहित खाद्य कंपनियों को पैकेट से ए-वन और ए-टू प्रकार के दूध, दही समेत अन्य उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया। नियामक ने इस तरह के लेबल को भ्रामक बताया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि ए दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं हैं। अपने ताजा आदेश में, एफएसएसएआई ने कहा कि उसने इस मुद्दे की जांच की है और पाया है कि ए-वन और ए-टू का अंतर दूध में बीटा-केसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है। हालांकि, मौजूदा एफएसएसएआई नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देते हैं। खाद्य व्यवसाय परिचालकों का जिक्र करते हुए नियामक ने कहा, एफबीओ को अपने उत्पादों से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश दिया गया है। ई-कॉमर्स मंच को भी उत्पादों और वेबसाइट से इन दावों को तुरंत हटाने के लिए कहा गया। कंपनियों को पहले से मुद्रित लेबल समाप्त करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है, इसके अलावा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। ए-1 और ए-2 दूध में बीटा-कैसीन प्रोटीन की संरचना अलग-अलग होती है, जो गाय की नस्ल के आधार पर अलग-अलग होती है। नियामक ने इस निर्देश का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। आदेश का स्वागत करते हुए पराग मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने कहा कि एफएसएसएआई का आदेश सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने एक बयान में कहा, ए-1 और ए-2 विपणन मकसद से विकसित की गई श्रेणी है। ...यह जरूरी है कि हम भ्रामक दावों को खत्म करें जो उपभोक्ताओं को गलत जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ए-1 या ए-2 दूध उत्पाद श्रेणी कभी अस्तित्व में नहीं थी और वैश्विक स्तर पर भी यह प्रवृत्ति खत्म हो रही है और उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई का स्पष्टीकरण इस व्यापक समझ का समर्थन करता है।

बलात्कार के मामलों में 50 दिनों के भीतर सजा दिलाने वाले कानून की जरूरत: अभिषेक बनर्जी

कोलकाता। (भाषा) तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने यौन उत्पीड़न के मामलों में 50 दिनों के भीतर दोषसिद्धि अनिवार्य करने वाले कानून की वकालत करते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ही देश में ऐसे 900 से अधिक मामले हुए हैं।

बनर्जी ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार पर बलात्कार रोधी समग्र कानून बनाने के लिए दबाव डालें, जिससे इन मामलों में त्वरित सुनवाई हो और आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके। बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ पिछले 10 दिनों में जब लोग सड़कों पर प्रदर्शन और न्याय की मांग कर रहे हैं, उसी दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में बलात्कार की 900 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा, देश में हर दिन बलात्कार की 90 घटनाएं, प्रति घंटे ऐसी चार तथा प्रति 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना सामने आती है इसलिए इन मामलों में निर्णायक कार्वाई की जरूरत है। हमें ऐसे मजबूत कानूनों की जरूरत है जो 50 दिनों के भीतर सुनवाई और दोषसिद्धि कर सकें और उसके बाद कठोर सजा दे सकें, न कि केवल खोखले वादे करें। राज्य सरकारों को कार्वाई करनी चाहिए और केंद्र सरकार पर बलात्कार रोधी समग्र कानून बनाने के लिए दबाव डालना चाहिए जो त्वरित सुनवाई कर सके और सख्त सजा दे सके।

जनगणना प्रश्नावली में कॉलम जोड़कर ओबीसी का जातिवार आंकड़ा एकत्र करें

नई दिल्ली। (भाषा) कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की मांग एक बार फिर उठाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि जनगणना की प्रश्नावली में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) का जातिवार आंकड़ा एकत्र किया जा सकता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा होने से जाति जनगणना की व्यापक मांग पूरी होगी और सकारात्मक कार्य वाले कार्यक्रमों को और मजबूत आधार मिलेगा।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भारत में हर 10 साल में नियमित रूप से जनगणना होती रही है। पिछली जनगणना 2021 में होनी थी और 2021 की जनगणना न होने का मतलब है कि आर्थिक योजना और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 12 करोड़ से जूयादा भारतीयों को उनका कानूनी हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, अब ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार अगले कुछ महीनों में लंबे समय से लंबित और अस्वीकार्य रूप से विलंबित इस जनगणना को करवा सकती है। रमेश ने कहा, 1951 से हर जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी के बारे में जातिवार आंकड़ा एकत्र किया जाता रहा है। बिना किसी परेशानी के सिर्फ एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर जनगणना की प्रश्नावली में ओबीसी आबादी के बारे में भी जातिवार आंकड़ा एकत्र किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से जाति संबंधी जनगणना की व्यापक मांग पूरी होगी और सकारात्मक कार्य वाले कार्यक्रमों को और मजबूत आधार मिलेगा। रमेश ने कहा कि जनगणना संविधान की सातवीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है और यह केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है जिसका अर्थ है कि जनगणना कराना केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

गाय को बचाने के लिए बांध में कूदा किसान, एसडीईआरएफ के दो जवान डूबे

भिंड (मप्र)। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक गाय को बचाने के लिए बांध में कूदा किसान और बचाव अभियान के लिए तैनात राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) के दो जवानों की डूबने से मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दी।पुलिस अधीक्षक असित यादव ने बताया कि बुधवार शाम कुंवारी नदी पर बने बांध के स्लुइस गेट में एक गाय फंस गई, जिसके बाद उसका मालिक विजय सिंह और उनका चचेरा भाई दिनेश भदौरिया जलाशय में कूद गए। यादव ने पीटीआई-भाषा को बताया, यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर हुई। दिनेश सिंह तेज बहाव में बह गया। कचोंगरा गांव के निवासियों ने रस्सियों की मदद से विजय को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा, दिनेश को नदी के बीच में झाड़ियों में फंसा हुआ देखकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने उसे बचाने के लिए राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) की मदद मांगी। जीवन रक्षक जैकेट पहने एसडीईआरएफ की तीन सदस्यीय टीम नदी में उतरी, लेकिन उनकी नाव पलट गई, जिससे वे तेज बहाव में गिर गए।उन्होंने कहा कि एसडीईआरएफ के जवान प्रवीण कुशवाह और हरदास चौहान की जीवन रक्षक जैकेट तेज बहाव में फट गई, जबकि तीसरा जवान तैरकर सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। अधिकारी ने कहा कि 100 से अधिक जवानों को तैनात करने के बाद आज शाम कुशवाह और चौहान के शव बरामद किए गए। यादव ने एसडीईआरएफ के एक जवान से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि दिनेश और गाय को बुधवार को बचा लिया गया था। बुधवार रात को अंधेरे के कारण लापता दो जवानों को खोजने का अभियान रोक दिया गया था और बृहस्पतिवार सुबह इसे फिर से शुरू किया गया।

भोजपुर जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

आरा (बिहार)। बिहार के भोजपुर जिले में आरा-बक्सर राजमार्ग पर बृहस्पतिवार को एक जीप के डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। भोजपुर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह गजराजगंज थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर बीबीगंज पुल के पास उक्त वाहन डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान भूप नारायण पाठक (56), बिपुल पाठक (26), रेनू देवी (55), अर्पिता पाठक (25) और सिटी कुमार उर्फ हर्ष कुमार (3) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घायलों में खुशी कुमारी (22), मधु देवी (27) और बेली कुमारी (पांच) शामिल हैं। पुलिस ने घायलों को भोजपुर जिला मुख्यालय आरा स्थित सदर अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उनका इलाज जारी है। बयान के अनुसार इस हादसे में हताहत हुए लोग भोजपुर जिले के अजीमाबाद थानाक्षेत्र के कमरिया गांव के निवासी थे और फिलहाल पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र की अर्पण बैंक कॉलोनी में रह रहे थे।

शरद पवार ने एमपीएससी परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों का समर्थन किया

पुणे। (भाषा) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर पुणे में आंदोलन कर रहे उम्मीदवारों का समर्थन किया है। पवार ने चेतावनी भी दी है कि यदि राज्य सरकार इस मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो वह इस प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। एमपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 अगस्त को होगी। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी मंगलवार रात से ही परीक्षा की अलग तिथि तय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसी दिन एक बैंकिंग परीक्षा भी है।राकांपा (एसपी) के विधायक रोहित पवार भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के साथ बैठ गए। राकांपा (एसपी) के प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बुधवार रात एक पोस्ट में कहा, एमपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों के हितों पर विचार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है... हालांकि, ऐसा लगता है कि वह इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। यदि कल (बृहस्पतिवार) तक सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो मैं आंदोलन स्थल पर जाऊंगा और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन में शामिल हो जाऊंगा। प्रदर्शनकारियों की यह भी मांग है कि एमपीएससी परीक्षा के माध्यम से ही कृषि विभाग के 258 पदों पर नियुक्तियां की जाएं। एमपीएससी के एक अभ्यर्थी ने कहा कि वे चाहते हैं कि कृषि विभाग के 258 पदों को एमपीएससी परीक्षा के दायरे में लाया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्र ने कहा, चूंकि 25 अगस्त को निर्धारित एमपीएससी परीक्षा के साथ-साथ उसी दिन लिपिक पदों के लिए भारतीय बैंकिंग कार्मिक चयन (आईबीपीएस) परीक्षा भी है इसलिए एमपीएससी परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए क्योंकि कई छात्रों ने दोनों ही परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है।

अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री साहा से बात की बाढ़ स्थिति का जायजा लिया

नई दिल्ली। (भाषा) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से फोन पर बात करके राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के दलों के साथ-साथ नौकाएं और हेलीकॉप्टर भी राज्य में भेज रही है।उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया,"त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डा. माणिक साहा से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम के अलावा नौका और हेलीकॉप्टर भी भेज रहा है"। मुख्यमंत्री को हरसंभव सहायता का आश्वासन देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में त्रिपुरा में हमारे बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़ी है। रविवार से त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। भारी बारिश के कारण 32,000 से अधिक लोगों ने 330 राहत शिविरों में शरण ली है।

हमें अपना बुनियादी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता : प्रह्लाद जोशी

बेंगलुरु। (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत प्रतिभा, जनशक्ति और क्षमता से भरपूर है, इसलिए हमें आगे बढ़ने तथा देश में और अधिक विनिर्माण करने की आवश्यकता है।

जोशी यहां राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखने के लिए बेंगलुरू में थे।नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे जोशी ने कार्यक्रम में कहा, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना बहुत जरूरी है। हमें अपनी प्रणाली, अपना बुनियादी ढांचा विकसित करने की जरूरत है। इस दिशा में, मेरे गृह राज्य में पहली ईवी बैटरी परीक्षण सुविधा खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का प्रत्एक निर्णय आपस में जुड़ा हुआ है और यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है।जोशी ने कहा, उदाहरण के लिए, हमारी योजना 2030 तक भारतीय सड़कों पर 30 प्रतिशत ईवी वाहन लाने की है। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि ईवी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली नवीकरणीय हो, इसलिए हम बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। हम एक करोड़ घरों में नि:शुल्क सौर ऊर्जा इकाई लगाने पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमें नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच मिल सके। उन्होंने एनटीएच से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करके तथा ईवी परीक्षण जैसी अधिक सुविधाएं स्थापित करके अपनी परीक्षण क्षमता में विविधता लाने का भी आग्रह किया। एनटीएच विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन में अग्रणी रहा है। यह उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। एनटीएच को पहले ही भारत में सेंट्रल विस्टा और मेट्रो रेल जैसी कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाएं मिल चुकी हैं।

बैंक खाते और आय का ब्योरा नहीं देने पर गुजारा भत्ते के लिए महिला का दावा खारिज

इंदौर (मध्यप्रदेश)। इंदौर के कुटुम्ब न्यायालय ने 28 वर्षीय महिला द्वारा अपने पति से गुजारा भत्ता हासिल करने का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उसने अपने बैंक खाते और आय का स्पष्ट ब्योरा अदालत में पेश नहीं किया। बी. कॉम. की उपाधि प्राप्त महिला ने ट्रैवल एजेंट पति से अपने और दम्पति की तीन वर्षीय बेटी के भरण-पोषण के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की रकम की मांग के साथ अदालत में दावा दायर किया था। कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एन पी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के एक फैसले की रोशनी में यह दावा खारिज कर दिया। अदालत ने प्रकरण के तथ्यों पर गौर के बाद अपने आदेश में कहा कि चूंकि महिला ने अपने हलफनामे में उसके बैंकिंग लेन-देन से जुड़े किसी खाते का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए लगता है कि वह कोई न कोई काम करके आमदनी हासिल कर रही है। कुटुम्ब न्यायालय ने कहा, प्रार्थी (महिला) आमदनी तो अर्जित कर रही है, लेकिन वह कितनी आमदनी अर्जित कर रही है, उसने इसका खुलासा नहीं किया है। इसलिए यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि दम्पति की नाबालिग संतान की परवरिश के लिए वह और प्रतिप्रार्थी (महिला का पति) कितनी राशि वहन करेंगे।

यूक्रेन में शांति के लिए भारत सहयोग को तैयार : मोदी

पीएम ने जेलेंस्की से वार्ता से पहले कहा

भाषा। वारसॉ

युद्धग्रस्त यूक्रेन की अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत का दृढ़ता से मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं किया जा सकता और यह (भारत) क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए हरसंभव सहयोग देने को तैयार है। मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ व्यापक वार्ता करने के बाद यह बात कही। बैठक में, दोनों नेताओं ने भारत-पोलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में तब्दील करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, उन्होंने कौशल प्राप्त श्रमिकों की दोनों देशों के बीच आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा समझौता पर भी हस्ताक्षर किए। एक संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाने के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि सभी देशों को किसी भी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग करने या उसे खतरे में डालने से बचना चाहिए। मोदी ने मीडिया से कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, भारत का दृढ़ता से मानना है कि युद्ध के मैदान में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी भी संकट में निर्दोष लोगों की जान जाना पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा, हम शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है। वारसॉ की अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद, मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा करेंगे और इस यात्रा में उन्हें लगभग 10 घंटे लगेंगे।

प्रधानमंत्री ने वारसॉ में अज्ञात सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

वारसॉ। पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वारसॉ में अज्ञात सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी बुधवार को यहां पहुंचे। यह 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार को लगभग सात घंटे यूक्रेन में रहेंगे। पोलिश भाषा में एक्स पर किए गए एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने वारसॉ में अज्ञात सैनिक की समाधि पर पुष्पचक्र अर्पित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें भी साझा कीं। विदेश मंत्रालय ने कुछ तस्वीरें संलग्न करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वारसॉ में अज्ञात सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की स्मृति को नमन किया।

पूर्वी थाईलैंड में छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी नौ लोगों के मारे जाने की आशंका

भाषा। बैंकॉक

थाईलैंड के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक घरेलू उड़ान का एक छोटा यात्री विमान बृहस्पतिवार दोपहर राजधानी बैंकॉक के मुख्य हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्राधिकरण ने आशंका जताई है कि विमान में सवार सभी नौ लोग मारे गए हैं। बचावकर्मियों को हवाई अड्डे से लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) दूर चाचोएंगसाओ प्रांत में मैंग्रोव दलदल में दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा मिला, जहां पर कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला। मीडिया के मुताबिक, विमान में सात यात्री और दो पायलट सवार थे। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लगभग एक घंटे की खोज के बाद बचावकर्मियों को दुर्गम दलदली इलाके में बुरी तरह क्षत-विक्षत शव मिले। विमान में सवार लोगों की पहचान तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी। विमान में सवार लोगों में हांगकांग के पांच चीनी पर्यटक, दो थाई महिला चालक दल के सदस्य और थाई पायलट और सह-पायलट शामिल थे। हादसे के कारणों का अबतक पता नहीं चल पाया है। थाईलैंड के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि थाई फ्लाइंग सर्विस कंपनी द्वारा संचालित टर्बोप्रॉप विमान सेसना कारवां सी208बी ने अपराह्न स्थानीय समयानुसार 2:46 बजे बैंकॉक के सुवर्णभूमि हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी।

दक्षिण कोरिया में एक होटल में आग से सात लोगों की मौत, 12 घायल

सियोल। दक्षिण कोरिया के शहर बुकेओन में एक होटल में आग लगने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बुकेओन के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के निदेशक किम इन-जे ने कहा कि घायल हुए पीड़ितों में से तीन की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि घायलों का इलाज नजदीक के छह अस्पतालों में किया जा रहा है। बुकेओन के अग्निशमन केंद्र के एक अधिकारी ली सांग-डॉन ने कहा कि बृहस्पतिवार शाम को जब आग लगी तो नौ मंजिला होटल में 23 मेहमान ठहरे हुए थे। यह अभी नहीं पता चल सका है कि आग किस वजह से लगी। ली ने कहा कि आठवीं मंजिल से फैली आग को करीब-करीब बुझा दिया गया है, लेकिन घायलों और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है,।

यूक्रेन ने रोम संविधि का अनुमोदन किया

कीव। यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) की रोम संविधि का अनुमोदन कर इसकी सदस्यता तथा युद्ध अपराधों के लिए रूसी अधिकारियों के खिलाफ और भी मुकदमे चलाने की संभावना खोलने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। यूक्रेन की संसद, वेरखोव्ना राडा ने बुधवार को आईसीसी संविधि का अनुमोदन करने के लिए मतदान किया। इस दस्तावेज पर यूक्रेन सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन संवैधानिक न्यायालय ने 2001 में इसके अनुमोदन को रोक दिया।

उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में वर्षाजनित घटनाओं में आठ लोगों की मौत

पेशावर। उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में भारी मॉनसूनी बारिश के बीच रात भर में वर्षाजनित घटनाओं दो बच्चों समेत कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यहां बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के अधिकारियों ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान, बन्नू, मानसेहरा और मोहमंद जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हुई। अधिकारियों के मुताबिक बन्नू में आसमान से बिजली गिरने से घर की छत गिर जाने से दो बहनों की मौत हो गई। डेरा इस्माइल खान जिले में भी छत गिरने की इसी तरह की घटना में एक महिला और उसके नाबालिग बेटे की मौत हो गई। पहाड़पुर तहसील में एक बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गई।

माइक लिंच का शव जहाज के मलबे में मिला: तटरक्षक बल

पोर्टिसेलो (इटली)। ब्रिटेन के प्रौद्योगिकी कारोबारी माइक लिंच का शव सिसिली अपतटीय क्षेत्र में जहाज के मलबे से बरामद कर लिया गया। इटली के तटरक्षक बल ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी। तटरक्षक बल ने बताया कि बचाव दल ने लिंच के अलावा चार अन्य लोगों के शव भी बरामद किए है जबकि एक महिला अब भी लापता है। ब्रिटेन के झंडे वाला 56 मीटर लंबा जहाज बेयसियन सोमवार सुबह तूफान के कारण तब डूब गया जब यह समुद्र तट से लगभग एक किलोमीटर दूर खड़ा था। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उनका मानना है कि जहाज तूफान में फंस जाने के कारण काफी तेजी से डूबता चला गया। जहाज पर सवार 22 लोगों में से 15 लोग बच गए।

ज़ेलेंस्की ने पहली बार सीमा क्षेत्र का दौरा किया

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दो सप्ताह से अधिक समय पहले अपनी सेना के रूसी इलाके में प्रवेश करने के बाद से सीमावर्ती क्षेत्र की अपनी पहली यात्रा मे बृहस्पतिवार को पूर्वोत्तर यूक्रेनी क्षेत्र सुमी का दौरा किया। यूक्रेन के सैन्य कमांडर के साथ एक बैठक के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी बलों ने रूसी क्षेत्र कुर्स्क में एक और बस्ती पर नियंत्रण का दावा किया है तथा रूस के और अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया है। उन्होने कहा कि बंदी बनाए गए रूसी सैनिकों को रूस द्वारा पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों की रिहाई के बदले छोड़ा जा सकता है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को यह बढ़त ऐसे समय मिली है जब यूक्रेन अपने पूर्वी क्षेत्र डोनेट्स्क में रूस से लगातार हार रहा है।

बोत्सवाना की खदान से मिला 2,492 कैरेट का विशाल हीरा

गाबोरोने (बोत्सवाना)। बोत्सवाना ने दावा किया है कि अब तक का सबसे बड़ा हीरा उसकी एक खदान से प्राप्त हुआ है और बृहस्पतिवार को इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। बोत्सवाना की सरकार का मानना है कि 2,492 कैरेट का यह विशाल रत्न देश में खोजा गया सबसे बड़ा प्राकृतिक हीरा और किसी खदान से निकाला गया दूसरा सबसे बड़ा रत्न है।कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड कॉर्प ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उसने पश्चिमी बोत्सवाना में अपनी कारोवे खदान से असाधारण हीरा बरामद किया है।

यूक्रेन संघर्ष की शीघ्र, न्यायसंगत समाप्ति में अहम भूमिका निभा सकता है भारतः पोलैंड के प्रधानमंत्री

भाषा। वारसॉ

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वार्ता के बाद कहा कि यूक्रेन में संघर्ष की शीघ्र और न्यायसंगत समाप्ति में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मोदी कीव की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी के साथ वार्ता के बाद अपने प्रेस वक्तव्य में टस्क ने कहा कि उन्होंने और भारत के प्रधानमंत्री ने वर्तमान में पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण बने मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। टस्क ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि प्रधानमंत्री (मोदी) ने युद्ध की शांतिपूर्ण, न्यायसंगत, शीघ्र समाप्ति के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जताई है। हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि भारत यहां (यूक्रेन में) एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। पोलिश प्रेस एजेंसी ने उन्हें उद्धृत करते हुए कहा, हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि भारत इस विषय में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम है। टस्क ने कहा कि यह घोषणापत्र विशेष महत्व रखता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही घंटों में कीव की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा, इस यात्रा के संबंध में, हम सभी इससे सहमत हैं कि यह ऐतिहासिक महत्व का हो सकता है। वहीं, मोदी ने कहा कि भारत का दृढ़ता से मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं किया जा सकता और यह (भारत) क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए हरसंभव सहयोग देने को तैयार है। टस्क ने कहा कि इतिहास ने दोनों राष्ट्रों को सीख दी है कि नियमों, सीमाओं, क्षेत्रीय अखंडता, देशों की संप्रभुता, कानून का शासन का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है।

रूस के दक्षिणी हिस्से में स्थित सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला, लगी आग

कीव। रूस के दक्षिणी हिस्से वोल्गोग्राद क्षेत्र में स्थित एक सैन्य ठिकाने पर बृहस्पतिवार को ड्रोन से हमला किया गया जिसके बाद वहां आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय और स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वोल्गोग्राद के गवर्नर आंद्रेई बोचारोव ने सोशल मीडिया मंच टेलीग्राम पर कहा कि मारिनोवका के इलाके में ड्रोन से हमला किए जाने के बाद एक सैन्य ठिकाने में आग लग गई, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बोचारोव ने यह नहीं बताया कि इस ड्रोन हमले से क्या नुकसान हुआ, लेकिन रूस के कई टेलीग्राम चैनल ने बताया कि ओक्त्यबर्स्की गांव में मारिनोवका के पास स्थित सैन्य हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया गया।

क्विक न्यूज

आत्मघाती हमले के बाद ट्रंप ने पहली रैली की

एशेबोरो (अमेरिका)। पिछले महीने हुए आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना मे अपनी पहली रैली की और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया।ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना एविएशन म्यूजियम एंड हॉल ऑफ फेम में रैली को संबोधित करते हुए कहा, अब से 76 दिन बाद, हमारी जीत होगी और हम व्हाइट हाउस जीतेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर पेनसिल्वेनिया में पिछले महीने चुनावी रैली में एक युवक ने गोलियां चलाई थी और एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी थी।जिस मंच से ट्रंप संबोधित कर रहे थे, वह चारों ओर बुलेटप्रूफ ग्लास से घिरा हुआ था। कार्यक्रम स्थल की छतों पर निशानेबाजों को तैनात किया गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के नवंबर में प्रस्तावित चुनाव के लिए प्रचार अभियान के तहत डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में जनसभा की थी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने शिकागो में हैरिस के समर्थन में प्रचार किया।

अमेरिका ने तिब्बतियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

वाशिंगटन। अमेरिकी सरकार की एक शीर्ष अधिकारी ने दलाई लामा से मुलाकात की और राष्ट्रपति जो. बाइडन की ओर से तिब्बतियों के मानवाधिकारों की रक्षा तथा उनके विशिष्ट ऐतिहासिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण के प्रयासों के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। दलाई लामा 28 जून को घुटने की सफल रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद से न्यूयॉर्क में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता की अमेरिकी विदेश विभाग की शीर्ष अधिकारी के साथ बैठक राष्ट्रपति बाइडन द्वारा एक कानून पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ महीनों बाद हुई है, जो तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को बढ़ाने और सुदूर हिमालय क्षेत्र की स्थिति एवं शासन संबंधी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन और दलाई लामा के बीच बातचीत को बढ़ावा देने की बात करता है। चीन ने फरवरी में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा और मई में सीनेट द्वारा पारित रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का विरोध किया था और इसे अस्थिर करने वाला बताया था।

पूरी दुनिया में छाएगी जाइस इमेजिंग की सुविधा

ग्लोबल। वीवो ने हाल ही में वी40 सीरीज़ भारत में लॉन्च की। वीवो वी40 और वी40 प्रो के साथ इसने स्मार्टफोन इनोवेशन में नया बेंचमार्क सेट किया है। पहली बार, वीवो ने प्रो और गैर-प्रो दोनों वेरिएंट पर जाइस के साथ पार्टनरशिप की है, वी सीरीज़ में शानदार कैमरा फैसिलिटी ला रहा है। अपने बेहतरीन अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन, जबरदस्त प्रदर्शन और उन्नत ए आई क्षमताओं के साथ, वी40 सीरीज़ स्मार्टफोन बाजार में एक गेमचेंजर है। कैमरा एक्सीलेंस कैमरा इनोवेशन की अपनी विरासत को जारी रखते हुए, वी40 सीरीज़ अपने जाइस को-इंजीनियर्ड कैमरा सिस्टम के साथ स्मार्टफोन फोटोग्राफी को अगले लेवल तक ले जाती है। वी40 प्रो में एक वर्सिटाइल ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50एमपी जाइस ओआईएस मेन कैमरा, 50एमपी अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 50एमपी टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा शामिल है। दूसरी ओर, वी40 में एक डुअल-कैमरा सिस्टम है जिसमें सेम 50एमपी जाइस मेन और अल्ट्रा वाइड-एंगल कैमरा हैं। दोनों स्मार्टफोन 50एमपी जाइस ग्रुप सेल्फी कैमरा से लैस हैं, जो शानदार सेल्फी देता है। जाइस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट, फेस्टिवल पोर्ट्रेट मोड और स्टूडियो-क्वालिटी आउरा लाइट पोर्ट्रेट जैसी सुविधाएँ ओवरआल कैमरा एक्सपीरियंस को और बढ़ाती हैं।

पसंद बन रहा डिजिटल लॉक

एशिया। डिजिटल लॉक का उपयोग आपके दैनिक जीवन को आसान बनाता है जिससे आपको चाबी की चिंता किए बिना सुविधाजनक और त्वरित पहुँच मिलती है। हाफ़ले का नया आरईएच डिजिटल लॉक आपके मुख्य दरवाजे पर आसानी से फिट हो जाता है, जो सुरक्षा और शैली का उत्कृष्ट मिश्रण है, जो सर्वोत्तम सुरक्षा के साथ प्रीमियम सौंदर्यशास्त्र प्रदान करता है। हाफ़ले ग्लोबल नेटवर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित हाफ़ले इण्डिया वर्ष 2003 से भारत में काम कर रही है। आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, फर्नीचर औरकिचन फिटिंग और एक्सेसरीज के क्षेत्र में एक प्राधिकरण, कम्पनी के पास होम अप्लायंस, इंटीरियर और फर्नीचर लाइटिंगए सैनिटरी सॉल्यूशंस और सरफेस जैसी समन्वित उत्पाद श्रेणियों में भी मजबूत उपस्थिति है, जो खुद को भारत और दक्षिण एशिया में इंटीरियर समाधानों के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है। हाफ़ले इंडिया की देश भर में फैले अपने कार्यालयों और डिज़ाइन शोरूम के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है। शोरूम सभी होम इंटीरियर और सुधार आवश्यकताओं के लिए वन.स्टॉप.शॉप के रूप में कार्य करते हैं। इसकी आकर्षक उपस्थिति के अलावाए यह उन्नत डिजिटल लॉक कई पहुँच विकल्पों के साथ आता है।

गल्फ ऑयल ने डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाई गई

गल्फ सिटी। गल्फऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड ने अपने डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए ग्लोबल लीडरए सेल्सफ़ोर्स को बी2बी व्यवसाय के लिए अपना नया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम प्लेटफ़ॉर्म बनाने की घोषणा की है। सेल्सफोर्स सीआरएम का उपयोग करने का गल्फका निर्णय ग्राहक की सहभागिता और ऑपरेशनल एफिशियंसी बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के इसके उद्देश्य के अनुरूप है। अपनी व्यवसायिक प्रक्रियाओं में सेल्सफोर्स को शामिल करके गल्फका उद्देश्य ग्राहक संवादों का 360 डिग्री व्यू प्रदान करना व्यक्तिगत अनुभव सुनिश्चित करना और ग्राहक की पसंद एवं व्यवहार के आधार पर अनुकूलित मार्केटिंग संदेश प्रदान करना है। इससे गल्फबी2बी व्यवसाय में बेहतर लीड मैनेजमेंट और कस्टमर पुट की मदद से महत्वपूर्ण वृद्धि संभव हो सकेगी। इस एप्लीकेशन में एडवांस्ड एनालिटिक्स और डैशबोर्ड्स संभव बनाकर निर्णय लेने की एफिशियंसी भी काफी बढ़ जाएगी। सेल्सफ़ोर्स ग्राहकों के साथ बातचीत में सुधार लाने और गहरे संबंध विकसित करने के लिए डिज़ाईन किए गए अनेक टूल्स प्रदान करता है। सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म द्वारा गल्फडेटा पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया और व्यक्तिगत मार्केटिंग रणनीतियाँ बनाने में समर्थ हो सकेगा। रवि चावला एमडी एवं सीईओ गल्फऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड ने कहा कि हम ग्राहकों पर केंद्रित केवल मूल्य के लिए नहीं बल्कि अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रहते हैं।

ईयू मिशन के तहत फ्रांसीसी पोत ने लाल सागर में क्षतिग्रस्त तेल टैंकर से 29 नाविकों को बचाया

दुबई। लाल सागर मे संदिग्ध हूती विद्रोहियो द्वारा किए गए सिलसिलेवार हमले मे क्षतिग्रस्त तेल टैंकर पर सवार 29 नाविको को यूरोपीय संघ मिशन के तहत एक फ्रांसीसी विध्वंसक पोत ने बचा लिया है। साथ ही इलाके मे बम ले जाने वाली एक ड्रोन नौका को भी नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यमन के हूती विद्रोहियों पर यूनान के इस टैंकर सोयूनियन पर हमला करने का संदेह है। यह हमला, पिछले कुछ हफ्तो मे लाल सागर में व्यापारिक जहाजो को निशाना बनाकर किए गए हमलो मे सबसे गंभीर हमला है। यह हमला, गाजा पट्टी मे इजराइल-हमास युद्ध के दौरान जहाजों को निशाना बनाने वाले हूती विद्रोहियो के महीनो लंबे अभियान के दौरान हुआ है। इन हमलों से यह अहम व्यापार मार्ग बाधित हुआ है। इस मार्ग से हर साल करीब 1000 अरब अमेरिकी डॉलर के माल की ढुलाई होती है। यूरोपीय संघ के अभियान संचालकों ने बताया कि सोयूनियन ने लाल सागर मे लंगर डाल दिया है और अब अनियंत्रित होकर नही बह रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट नही है कि जहाज मे अब भी आग लगी हुई है या नहीं। जहाज पर फिलीपीन और रूस के नाविक सवार थे। सैन्य अधिकारियों ने बचाव कार्य मे शामिल फ्रांसीसी विध्वंसक पोत का नाम नही बताया।

टेक्सास में 90 फुट ऊंची हनुमान की मूर्ति बनी वहां की नई पहचान

भाषा। ह्यूस्टन

ह्यूस्टन के निकट भगवान हनुमान की 90 फुट उंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है जो अमेरिका के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक नया अध्याय है। यह मूर्ति टेक्सास में नवीनतम पहचान बन गई है जो बहुत दूर से दिखाई देती और यह अमेरिका में तीसरी सबसे उंची मूर्ति है।आयोजकों ने बताया कि इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनियन रखा गया है और यह विश्व की सबसे उंची मूर्तियों में से एक है। इसकी कई अन्य विशिष्टताएं भी हैं: यह भारत के बाहर हनुमान की सबसे उंची मूर्ति है, टेक्सास में सबसे उंची मूर्ति है, अमेरिका में तीसरी सबसे उंची मूर्ति है और इससे उंची मूर्तियां केवल न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (151 फुट) और फ्लोरिडा के हैलैंडेल बीच में पेगासस एंड ड्रैगन (110 फुट) ही हैं। आयोजकों ने बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनियन हनुमान मूर्ति का अनावरण यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर शुगर लैंड स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में 15 से 18 अगस्त तक आयोजित भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह के दौरान किया गया। उनके अनुसार, यह मूर्ति निस्वार्थता, भक्ति और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का यह नाम - स्टैच्यू ऑफ यूनियन - भगवान राम और सीता के पुनर्मिलन में हनुमान की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में रखा गया है। एक बयान में आयोजकों ने कहा, "यह विस्मयकारी संरचना पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध वैदिक विद्वान परम पावन श्री चिन्ना जीयर स्वामीजी के दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने इस परियोजना को उत्तरी अमेरिका के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखा था। उत्सव 15 अगस्त को शुरू हुआ, जिस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उत्सव का मुख्य भाग 18 अगस्त को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ शुरू हुआ। बयान में कहा गया,श्री चिन्ना जीयर स्वामीजी के नेतृत्व में और वैदिक पुजारियों और विद्वानों की देखरेख में किए गए अनुष्ठान, भक्ति और आध्यात्मिकता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन थे।

संयुक्त राष्ट्र की टीम प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की जांच के लिए बांग्लादेश पहुंचेगी

भाषा। ढाका

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना के इस्तीफे से पहले और उसके बाद कम से कम 650 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की जांच के लिए बृहस्पतिवार को बांग्लादेश पहुंचेगी। अखबार डेली स्टार ने ढाका में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के हवाले से बुधवार को कहा, संयुक्त राष्ट्र की तथ्यान्वेषण टीम के आने और (अत्याचारों की) जांच करने से पहले यह संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की प्राथमिक टीम है। हम जांच के लिए रूपरेखा से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र की टीम एक जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुईं मानवाधिकार उल्लंघन की सभी घटनाओं की जांच के लिए विस्तृत नियम और शर्तों पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल कम से कम एक सप्ताह तक यहां रहेगा और नागरिक समाज समूहों, मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों तथा अन्य संबंधित लोगों से मुलाकात करेगा। हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अराजकता फैल गई और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच वह पांच अगस्त को भारत भाग गईं। इससे पहले, सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जुलाई के मध्य से 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने आठ अगस्त को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की 16 अगस्त को प्रकाशित एक प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन और अवामी लीग सरकार के पतन के बाद हुईं घटनाओं में बांग्लादेश में लगभग 650 लोग मारे गए थे। इनमें से लगभग 400 मौतें 16 जुलाई से चार अगस्त के बीच हुईं। कहा जाता है कि अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता से हटने के बाद 5 और 6 अगस्त को लगभग 250 लोग मारे गए।

बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री हसीना व उनके सहयोगियों के खिलाफ एक और मामला दर्ज

ढाका। बांग्लादेश में हाल ही में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में एक फेरीवाले की हत्या के संबंध में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 46 अन्य के खिलाफ बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया गया। इस नए मामले के साथ ही उनके पद से हटने के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 45 हो गई है।सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, अदालत के आदेश के बाद अशुलिया पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।खबर में कहा गया कि पीड़ित शॉन के रिश्तेदार मोहम्मद मोजिबुल हुसैन ने ढाका की वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट राबेया सुल्ताना की अदालत में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि अदालत ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद अशुलिया पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मामले को प्राथमिकी के रूप में स्वीकार करने को कहा। मामले के दस्तावेज के अनुसार, शॉन चार जुलाई को भेदभाव विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुआ था, जिस दौरान उसे गोली मार दी गई और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई।इस मामले के साथ, हसीना पर अब 45 मामले दर्ज हो गए हैं, जिनमें 28 हत्या के, चार मानवता विरोधी अपराध और नरसंहार के तथा एक अपहरण का मामला शामिल है। इसके अलावा, उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में सात अन्य मामले भी दर्ज हैं।
हसीना छात्रों के अभूतपूर्व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा देकर पांच अगस्त को भारत चली गई थीं। हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा की घटनाओं में 230 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और सरकारी नौकरियों में कोटा के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के दौरान कुल मौतों का आंकड़ा 600 पर पहुंच गया था।

कब्ज से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है-अध्ययन

भाषा। सिडनी

अगर आप गूगल पर "कब्ज" और "दिल का दौरा" जैसे शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो एल्विस प्रेस्ली का नाम सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एल्विस को लंबे समय से पुरानी कब्ज की शिकायत थी और ऐसा माना जाता है कि वह मलत्याग करने के लिए बहुत जोर लगा रहा था, जिसके बाद उसे घातक दिल का दौरा पड़ा। हम नहीं जानते कि 1977 में तथाकथित किंग ऑफ रॉक एन रोल के साथ वास्तव में क्या हुआ था। उनकी मृत्यु में संभवतः कई योगदान कारक थे, और यह सिद्धांत कई में से एक है। लेकिन इस प्रसिद्ध मामले के बाद शोधकर्ताओं ने कब्ज और दिल के दौरे के जोखिम के बीच संबंध में गहरी दिलचस्पी ली।

इसमें ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक हालिया अध्ययन शामिल है जिसमें हजारों लोगों का डेटा लिया गया है।क्या कब्ज और दिल का दौरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ?बड़ी आबादी के अध्ययन से पता चलता है कि कब्ज दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है।उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया के एक अध्ययन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 540,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया, जिन्हें विभिन्न स्थितियों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें पाया गया कि कब्ज वाले मरीजों में उसी उम्र के गैर-कब्ज वाले मरीजों की तुलना में उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा अधिक था।अस्पतालों और अस्पताल के आउट पेशेंट क्लीनिकों के 900,000 से अधिक लोगों पर किए गए एक डेनिश अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन लोगों को कब्ज था, उनमें दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया था। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं था कि क्या कब्ज और दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम के बीच यह संबंध अस्पताल के बाहर स्वस्थ लोगों के लिए सही होगा।इन ऑस्ट्रेलियाई और डेनिश अध्ययनों में उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के प्रभावों को भी शामिल नहीं किया गया।

28 मिलियन कपल्स में फर्टिलिटी समस्याएं

भारत में 28 मिलियन कपल्स ऐसे हैं जो फर्टिलिटी समस्याओं से जूझ रहे हैं,और1प्रतिशत से भी कम लोग लेते हैंडॉक्टरी सलाह लेते हैं, यही वजह है कि हम इस बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ का आईवीएफ साइकिल्स का संयुक्त अनुभव का आंकड़ा 120,000 है और अब तक 230,000 पेशेंट्स का उपचार किया जा चुका है। सी.के.बिरला ग्रुप(3 बिलियन डॉलर) की कंपनी और भारत के तीसरे सबसे बड़े आई.वी.एफ (नेटवर्क बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने बेबीसाइंस आईवीएफ क्लीनिक्स का अधिग्रहण कर कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अपनी पकड़मज़बूत की है। यह अधिग्रहण बिरला फर्टिलिटी और आईवीएफ की रणनीतिक विस्तार, जिसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश योजना के अंतर्गतएक प्रमुख कदम है।बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ नेकेरल में एआरएमसी आईवीएफ चेन का अधिग्रहण करने के तीन माह के अंदर यह कदम उठाया है। इस मौके पर, अवंति बिरला, संस्थापक, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने कहा, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ मेंहम कॉनसेप्शन के विज्ञान के साथ देखभाल (केयर) का मेल कराते हैं। मैं खुद अधिकाधिक दंपत्तियों (कपल्स) और महिलाओं के लिए इन सुविधाओं को सुलभ बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हूं। इस अवसर पर, अभिषेक अग्रवाल, चीफ बिजनेस ऑफिसर,बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ,ने कहा, कि अपनी वैश्विक विशेषज्ञता और अत्याधुनिक टेक्नॉलजी का लाभ उठाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाली उत्कृष्ट प्रेग्नेंसी दर प्रदान करने के लिए, हमने भारत भर में विस्तार किया है। डॉ मंजूनाथ सीएस, फाउंडर, बेबीसाइंस् ने कहा,हम राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान बना चुके इस ब्रैंड के साथ जुड़कर बहुत उत्साहित हैं, इससे हमारे पेशेंट्स को इंडस्ट्री में सर्वोत्तम विज्ञान का लाभ मिलेगा।इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में, अक्षत सेठ, वाइस चेयरमैन, सी.के. बिरला हैल्थकेयर ने कहा, इस कदम के साथ, बिरला फर्टिलिटी और आईवीएफ, दक्षिण भारत में जागरूकता बढ़ाने और भरोसेमंदफर्टिलिटीट्रीटमेंट प्रदान करने के लक्ष्य के साथअपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा।

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट की मेजबानी

लंदन। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने गुरुवार को घोषणा की कि ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले महिला टेस्ट की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा जब यह मैदान इन दोनों टीमों के बीच टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। ईसीबी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि जुलाई 2025 में भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के बाद भारतीय टीम 2026 में एकमात्र टेस्ट के लिए वापस आएगी। भारतीय टीम अगले साल 28 जून से 12 जुलाई के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलेगी। टीम इसके बाद क्रमशः 16 (साउथम्पटन), 19 (लंदन) और 22 जुलाई (चेस्टर ली स्ट्रीट) को तीन मैचों की वनडे श्रृंखला खेलेगी। ईसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड गौल्ड ने कहा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारतीय महिला टीम 2026 में लॉर्ड्स में पहले महिला टेस्ट मैच में इंग्लैंड की महिला टीम से भिड़ने के लिए वापसी करेंगी। यह वास्तव में एक विशेष अवसर होगा। भारतीय टीम 2026 में लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच के लिए वापस आएगी। इस मैदान पर इन दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाला यह पहला टेस्ट मैच होगा। इंग्लैंड की महिलाओं ने पिछले तीन वर्षों से लॉर्ड्स में सफेद गेंद वाले मैच खेले हैं, अगले साल एक और मैच निर्धारित है, लेकिन यह पहली बार होगा जब मैदान महिला टेस्ट मैच में भारत की मेजबानी करेगा। भारतीय टीम ने अपनी सरजमीं पर पिछले साल दिसंबर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद इस साल जून-जुलाई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी सरजमीं पर खेले गए टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है।

भारत के इंग्लैंड दौरे पर लीड्स, बर्मिंघम, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर, ओवल करेंगे टेस्ट मैचों की मेजबानी

लंदन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के अपने अगले चक्र का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला के साथ करेगी, जिसका शुरुआती मुकाबला 20 जून को तेज गेंदबाजों अनुकूल हेडिंग्ले में होगा। अगला डब्ल्यूटीसी चक्र 2025 से 2027 तक चलेगा और यह वर्तमान चक्र के फाइनल के ठीक बाद शुरू होगा। मौजूदा डब्ल्यूटीसी फाइनल भी इंग्लैंड में खेला जाएगा। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने रणनीतिक रूप से उन स्थानों पर मैच रखे है जहां इंग्लैंड के स्विंग गेंदबाजों को विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा टेस्ट दो से छह जुलाई तक बर्मिंघम के एजबेस्टन में होगा।तीसरा टेस्ट 10 से 14 जुलाई के बीच लॉर्ड्स मैदान पर होगा, जबकि मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड 23 से 27 जुलाई के बीच चौथे टेस्ट की मेजबानी करेगा। यह दौरा 31 जुलाई से चार अगस्त तक ओवल में अंतिम टेस्ट के साथ समाप्त होगा।श्रृंखला के पहले और दूसरे टेस्ट में एक सप्ताह जबकि तीसरे और चौथे टेस्ट के बीच आठ दिनों का अंतराल है ताकि खिलाड़ियों को तरोताजा होने का पूरा मौका मिल सके।

कृष्णा का पेरिस पैरालंपिक में धैर्य और सकारात्मक खेल से स्वर्ण पदक का बचाव करने पर ध्यान

भाषा। नई दिल्ली

कृष्णा नागर को जिंदगी ने लगातार चुनौतियां पेश की हैं लेकिन इस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को अच्छे से उससे निपटना आता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अनुकूल कर लेते हैं। कृष्णा को बचपन में उनके छोटे कद के कारण चिढ़ाया जाता था लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धियों से इसका जवाब दिया। कृष्णा ने अपने छोटे कद को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया। उन्हें पता था कि उनके लिए द्वेष रखने वालों से निपटने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका था। अपने शुरुआती वर्षों में वित्तीय संघर्षों के बावजूद उन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लंबी कूद और स्प्रिंट सहित विभिन्न खेलों में रुचि दिखाई। बैडमिंटन में उनका सफर 2017 के अंत में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से शुरू हुआ। उन्होंने तोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। इस पदक ने उनके वैश्विक खेलों की शुरुआत को यादगार बना दिया।

क्लब थ्रोअर सूरमा की नजर पैरालंपिक में पदक जीतने पर

नई दिल्ली। ऐसा अक्सर नही होता है कि जीवन बदल देने वाली दुर्घटना से अपाहिज हुआ कोई व्यक्ति उस त्रासदी को अपने लिए वरदान बना दे लेकिन जल्द ही पैरालिंपियन बनने वाले प्रणव सूरमा ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया। वह तब 16 साल के थे जब 2011 मे उनके घर की छत उनके ऊपर गिर गई। उनकी जिंदगी व्हील चेयर तक सिमट गई थी लेकिन उन्होंने हौसला बनाए रखा और अब वह 28 अगस्त से पेरिस मे होने वाले पैरालंपिक खेलो मे पदक जीतने की तैयारी मे लगे हुए है। पेशे से बैंकर सूरमा ने पीटीआई से कहा, मेरी शुरू से खेलो मे रुचि रही है लेकिन मैंने कभी खेल को करियर विकल्प के रूप मे नही लिया लेकिन मै हमेशा अपने जीवन मे कुछ अच्छा करना चाहता था और विडंबना यह है कि मुझे यह तब मिला जब मै लकवाग्रस्त हो गया।

मोहन बागान व ईस्ट बंगाल के बीच जोरदार मुकाबले का गवाह बनेगा लखनऊ

बाबू स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला, तैयारी

लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ पहली बार दो परम्परागत प्रतिद्वंद्वी फुटबॉल टीमों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच जोरदार मुकाबले का गवाह बनेगा। यह मुकाबला आगामी दो सितंबर को राजधानी के के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रदेश के खेल निदेशक आर. पी. सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच दो सितंबर को होने वाले इस मुकाबले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यह मैच दूधिया रोशनी में खेला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुकाबला देखने आएंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ में पहली बार देश की दो बड़ी फुटबॉल टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसमें 10 हजार दर्शकों के जुटने की सम्भावना है। मुकाबले की तैयारियों के तहत स्टेडियम में हाल ही में लगी फ्लड लाइट का परीक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम तथा अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने पिछले दिनों लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में फुटबॉल के विकास की अच्छी सम्भावनाएं बताते हुए, राज्य में इस खेल को बढ़ावा देने की जरूरत जताई थी। इस दौरान उन्होंने राजधानी में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच मुकाबला कराने का प्रस्ताव भी दिया था। इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। खेल निदेशक ने बताया कि दोनों टीमें एक सितंबर को लखनऊ पहुंच जाएंगी। प्रदेश में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिहाज से यह बेहद उत्साहजनक कदम है।

इंदिरा नूई का छह साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद आईसीसी को नई महिला निदेशक की तलाश

दुबई। पेप्सिको प्रमुख इंदिरा नूई का छह साल का कार्यकाल पिछले महीने समाप्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को एक नई महिला स्वतंत्र निदेशक की तलाश है। मौजूद अध्यक्ष (चेयरमैन) ग्रेग बार्कले के तीसरे कार्यकाल के लिए इनकार के बाद विश्व निकाय को एक नए अध्यक्ष की भी खोज करनी होगी। नूई 2018 में [illegible] की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनीं थी। उन्होंने अपना अधिकतम कार्यकाल पूरा कर लिया है। समझा जाता है कि आईसीसी बोर्ड ने पहले ही नूई जैसे हाई-प्रोफाइल नाम की तलाश शुरू कर दी है जो कॉर्पोरेट जगत में सबसे चर्चित चेहरों में से एक थी। आईसीसी नियमों के मुताबिक, निदेशक मंडल एक व्यक्ति का चुनाव करेगा जो एक महिला होनी चाहिए और जिसे निदेशक पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रिकेट के खेल में समानता, विविधता और समावेशित हितों का समय-समय पर उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

कभी कभार थोड़े से भाग्य की जरूरत होती है : द्रविड़

भाषा। मुंबई

महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ मानते हैं कि कभी कभी थोड़ी सी किस्मत भी बड़े मैच के नतीजों को प्रभावित कर सकती है जिसके लिए उन्होंने वनडे विश्व कप फाइनल में भारत को आस्ट्रेलिया से मिली दिल तोड़ने वाली हार और अपनी टीम की टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत का उदाहरण दिया। भारत पिछले साल लगातार 10 मैच में जीत के बाद वनडे विश्व कप फाइनल में पहुंचा था लेकिन टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम जब खिताबी मुकाबले में आस्ट्रेलिया से भिड़ी तो उसके लिए कुछ भी कारगर नहीं रहा। छह महीने बाद कप्तान रोहित शर्मा और द्रविड़ ने मिलकर अधूरी कसर पूरी की। टी20 विश्व कप फाइनल में मजबूत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किस्मत ने भारतीय टीम का साथ दिया। द्रविड़ ने बुधवार को याद किया कि टीम के लिए 29 जून को बारबाडोस में हुए फाइनल में एक निश्चित प्रक्रिया पर डटे रहना और भाग्य का साथ देने की उम्मीद रखना कितना महत्वपूर्ण था। द्रविड़ को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा, मुझे इस पर विचार करने का समय मिला। मुझे उन बहुत सी चीजों को सोचने का समय मिला जो हमने की। आपको कभी कभी अहसास होता है कि आपको इनमें से बहुत सी चीजें करनी होती हैं, आपको प्रक्रिया का पालन करना होता है, आपको सब कुछ सही करना होता है। द्रविड़ ने कहा, कभी कभी आपको थोड़े भाग्य की जरूरत होती है। टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 गेंद फेंकी जानी थी और 30 रन बनाने थे। तब रोहित के बेहतरीन तरीके से रणनीति के कार्यान्वयन और संयम रखने की बात थी। उन्होंने डेविड मिलर को आउट करने के लिए सूर्यकुमार यादव के सीमा रेखा पर लपके हुए कैच का जिक्र किए बिना कहा, हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो एक निश्चित सीमा के अंदर ऐसा कर सके। कभी यह कौशल होता है।

आस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम के लिए अहम होंगे पंत : हेडन

मुंबई। महान बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को लगता है कि जब भारतीय टीम पांच टेस्ट की श्रृंखला के लिए आस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी तो ऋषभ पंत उसके लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे क्योंकि पिछले दौरे पर इस विकेटकीपर बल्लेबाज की जीत की भूख शानदार रही थी। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच यह पांच मैच की श्रृंखला 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी। हेडन ने बुधवार को यहां सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स के मौके पर पत्रकारों से कहा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के अंदर जीत की भूख है और उसकी मसल मेमरी (प्रक्रियात्मक स्मृति) शानदार है। पिछली बार जब वह वहां खेला था तो वह अहम खिलाड़ी रहा था और आस्ट्रेलिया के दर्शकों को भी उसका खेल काफी पसंद आया था। उन्होंने कहा, पंत का खेल रोमांचक और बेहतरीन रहा था। फिर आपके पास अनुभवी खिलाड़ी जैसे विराट कोहली है जो फिर से अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। बल्लेबाजी को देखते हुए मै यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि भारत आस्ट्रेलियाई सरजमी पर उससे भिड़ने के लिए किस तरह की रणनीति बनाएगा। पंत ने 2022 मे गंभीर कार दुर्घटना के बाद क्रिकेट मे सफल वापसी की, उन्होंने 2020-21 मे आस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया था जिसमें उन्होंने 97 और नाबाद 89 रन की शानदार पारियां खेली। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे नाटकीय बदलावों में से एक में कई मुख्य खिलाड़ियों की कमी के बावजूद भारत ने आस्ट्रेलिया को हरा दिया था।

नवारो मॉन्टेरी ओपन के क्वार्टर फाइनल में

मॉन्टेरी (मैक्सिको)। अमेरिका की दूसरी वरीयता प्राप्त एम्मा नवारो ने गुरुवार को यहां तीन सेट तक चले कड़े मुकाबले में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को 3-6, 7-5, 7-6 (2) से हराकर मॉन्टेरी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। नवारो हार्ड कोर्ट पर खेली जा रही इस डब्ल्यूटीए 500 प्रतियोगिता के अंतिम आठ में पोलैंड की नौवीं वरीयता प्राप्त मैग्डेलेना फ्रेच से भिड़ेंगी जिन्होंने एक अन्य मैच में लीना ग्लुशको को 6-7 (2), 6-3, 6-1 से हराया। इससे पहले बुधवार को तीसरी वरीयता प्राप्त एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने स्थानीय खिलाड़ी रेनाटा ज़राज़ुआ को 6-3, 6-4 से हराया। अलेक्जेंड्रोवा का सामना सातवीं वरीयता प्राप्त चीन की यू युआन से होगा, जिन्होंने पेट्रा मार्टिच को 6-4, 6-1 से पराजित किया।

शिवानी जिला ओपन तैराकी 1 सितंबर को

लखनऊ। लखनऊ एमेच्योर तैराकी एसोसिएशन के तत्वावधान में शिवानी पब्लिक स्कूल द्वारा प्रथम शिवानी जिला ओपन तैराकी चैंपियनशिप आगामी 1 सितंबर 2024 को भारतीय खेल प्राधिकरणए क्षेत्रीय केंद्र साई लखनऊ सरोजनीनगर लखनऊ के तरणताल में आयोजित होगी। शिवानी ग्रुप के सीईओ सुधीर दुबे व लखनऊ एमेच्योर तैराकी एसोसिएशन के अध्यक्ष रविन कपूर ने बताया कि इस चैंपियनशिप के दौरान कुल 40 स्पर्धाओं का आयोजन होगा। इसमें ग्रुप 1 अंडर-17, ग्रुप 2 अंडर.14 ग्रुप 3 अंडर.11ग्रुप4,अंडर-9 और ग्रुप 5 अंडर-7 वर्ग में बालक व बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।

विद्याधर और कार्तिक ने वारियर्स को दिलाई जीत

बेंगलुरु। विद्याधर पाटिल और सीए कार्तिक की कसी गेंदबाजी की बदौलत मैसूर वारियर्स ने गुरुवार को यहां महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 में शिवामोगा लायंस पर 28 रन की आसान जीत दर्ज की। लायंस की टीम 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 151 रन पर सिमट गई जिसमें विद्याधर ने 29 रन देकर तीन और कार्तिक ने 31 रन देकर तीन विकेट झटके। मैसूर वारियर्स ने कप्तान करुण नायर के 45 रन, जे सुचित के 22 रन और मनोज भंडागे ने 23 रन की बदौलत अच्छा स्कोर खड़ा किया। कार्तिक ने भी 30 रन की पारी खेली। लायंस के तेज गेंदबाज एच एस शरत ने 29 रन देकर चार विकेट चटकाकर अच्छा स्पैल डाला लेकिन वारियर्स की टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही।

इनफोकस इंडिया पब्लिक स्कूल सुब्रतो कप सब जूनियर क्वार्टरफाइनल में

बेंगलुरु। पश्चिम बंगाल के इनफोकस इंडिया पब्लिक स्कूल ने गुरुवार को यहां मिजोरम के गवर्नमेंट चांगफिंगा मिडिल स्कूल को 2-0 से हराकर 63वें सुब्रतो कप सब जूनियर लड़कों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। ग्रुप एच के इस मैच में विजेता टीम के लिए प्रीतम और राजदीप ने गोल दागे। झारखंड के जेएनवी ने ग्रुप डी में हिमाचल प्रदेश के मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल को 2-1 से मात दी।

मीराबाई चानू और नीलकांत शर्मा सम्मानित

इंफाल। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू और हॉकी खिलाड़ी नीलकांत शर्मा को बुधवार को यहां मणिपुर पुलिस ने सम्मानित किया। यहां जारी बयान के अनुसार पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने यहां एक समारोह में मीराबाई और नीलकांत को सम्मानित किया।

सिंकफील्ड कप: गकेश ने प्रज्ञानंदा के खिलाफ बाजी ड्रॉ खेली

सेंट लुई (अमेरिका)। विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम टूर्नामेंट सिंकफील्ड कप के तीसरे दौर में हमवतन आर प्रज्ञानंदा के खिलाफ मुश्किल परिस्थितियों में होने के बावजूद बाजी ड्रॉ कराई। एक समय लग रहा था कि यह बाजी आसानी से ड्रॉ हो जाएगी लेकिन तभी गुकेश गलती कर बैठे। प्रज्ञानंदा हालांकि इसका फायदा नहीं उठा पाए और आखिर में दोनों भारतीय खिलाड़ी अंक बांटने पर सहमत हो गए। यह दोनों अभी समान 1.5 अंक लेकर संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञानंदा ने 2022 के बाद क्लासिकल बाजी में गुकेश को नहीं हराया है। फ्रांस के अलीरेज़ा फ़िरोज़ा ने भी कुछ विषम पलों से गुजरने के बाद हमवतन मैक्सिम वाचिएर-लाग्रेव के खिलाफ बाजी ड्रॉ कराई। फिरोजा दो अंक लेकर रूस के इयान नेपोम्नियाचची के साथ अभी शीर्ष पर बने हुए हैं। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसात्तोरोव भी अच्छी स्थिति में दिख रहे थे लेकिन उन्हें एक गलती बेहद महंगी पड़ी जिसका फायदा उठाकर फैबियानो कारूआना टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने में सफल रहे।तीसरे दौर में दूसरे विजेता नेपोम्नियाचची थे, जिन्होंने नीदरलैंड के अनीश गिरी के खिलाफ अपेक्षाकृत आसान जीत हासिल की।

मीनू-प्रिया ने आस्ट्रेलिया ए को दिया झटका

भारत ए ने महज 212 रन पर समेटा

भाषा। गोल्ड कोस्ट (आस्ट्रेलिया)

स्पिनर मीनू मणि के पांच और प्रिया मिश्रा के चार विकेट की मदद से भारत ए महिला टीम ने गुरुवार को यहां चार दिवसीय एकमात्र महिला अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन आस्ट्रेलिया ए को पहली पारी में महज 212 रन पर समेट दिया। कप्तान और ऑफ स्पिनर मीनू ने 58 रन देकर पांच और लेग स्पिनर प्रिया ने 58 रन देकर चार विकेट झटके जिससे आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी इकाई ने सभी 10 विकेट गंवा दिए। भारत ए ने स्टंप तक दो विकेट गंवाकर 100 रन बना लिए जिससे वह 112 रन से पिछड़ रही है। आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों के सामने संघर्ष करती नजर आईं। सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वोल (71 रन, 95 गेंद, 12 चौके) ने तेजी से रन बटोरे लेकिन बाएं हाथ की स्पिनर मन्नत कश्यप का शिकार बन गईं जिसके बाद आस्ट्रेलियाई टीम ने 94 रन तक चार विकेट गंवा दिए थे। फिर निचले क्रम की बल्लेबाजी मैतलान ब्राउन (30 रन) और ग्रेस पार्सन्स (35 रन) ने मेजबानों को 200 रन के पार कराया। इसके बाद भारत ने प्रिया पूनिया (07) का विकेट जल्दी गंवा दिया और टीम का स्कोर 13 रन पर एक विकेट हो गया। फिर शुभा सतीश भी योगदान दिए बिना आउट हो गईं। दो विकेट पर 47 रन के स्कोर पर भारत को मजबूत भागीदारी की जरूरत थी। श्वेता सेहरावत और तेजल हसाबनिस ने तीसरे विकेट के लिए अब तक 53 रन जोड़ दिए हैं। श्वेता 40 और तेजल 31 रन बनाकर खेल रही हैं।

आदित्य,अयान, प्रांजल व दिव्यांशु फाइनल में

सीआईएससीई-यूपी-यूकेरीजनल बाक्सिंग टूर्नामेंट

लखनऊ। लखनऊ जोन ए के आदित्य सिंह अलेरिया, मोहम्मद अयान खान, प्रांजल जोशी, दिव्यांशु बिष्ट ने सीआईएससीई यूपीयूके रीजनल बाक्सिंग टूर्नामेंट में अपने.अपने वर्गो में सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत के साथ फाइनल में स्थान सुरक्षित किया। सेंट थॉमस मिशन हाईस्कूल, लखनऊ द्वारा केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाक्सिंग हाल में आयोजित तीन दिवसीय टूर्नामेंट के पहले दिन लखनऊ जोन बी के अविरल गुप्ता, उन्नत गुप्ता, यजदान ने भी सेमीफाइनल में जीत दर्ज की। टूर्नामेंट का उद्घाटन आज मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने दीप प्रज्जवलन करके किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्वागत स्कूल के प्रबंधक फादर जयसन जोसेफ ने पुष्पगुच्छ भेंटकर किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्या डाण्रुपम दुबे तथा लखनऊ के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अजय कुमार सेठी की भी गरिमामयी मौजूदगी रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने अपने आर्शीवचन में कहा कि खेल का आज जीवन में महत्व काफी बढ़ गया है। इसी के चलते अब ये कहा जाने लगा है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे, तब भी बनोगे नवाब। पहले दिन खेले गए अंडर.14 आयु वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबलों में 34.36 किग्रा में कानपुर उत्तर के अक्षत सिंह ने कानपुर दक्षिण के आर्यन द्विवेदी को व लखनऊ जोन ए के आदित्य सिंह अलेरिया ने मेरठ के नुकुल को हराया। 28-30 किग्रा भार वर्ग में लखनऊ जोन बी के अविरल गुप्ता ने कानपुर. दक्षिण जोन के अहद खान को व मेरठ के अमन ने कानपुर उत्तर के अणर्व मिश्रा को हराया। 30-20 किग्रा वर्ग में लखनऊ जोन बी के उन्नत गुप्ता ने कानपुर दक्षिण के अग्रज पाण्डेय को व लखनऊ जोन ए के मोहम्मद अयान खान ने कानपुर उत्तर के अंकित मिश्रा को हराया। 40.42 किग्रा में मेरठ के इंद्रजीत सिंह ने कानपुर दक्षिण के प्रथम शुक्ला को व लखनऊ जोन ए के दिव्यांशु बिष्ट ने कानपुर उत्तर के रेहान अख्तर को हराया। 48.50 किग्रा भार वर्ग में कानपुर उत्तर के शौर्य वर्द्धन ने कानपुर दक्षिण के मयंक यादव को व मेरठ के अविरल दीक्षित ने लखनऊ जोन ए के अक्षत द्विवेदी को हराया। इसके अलावा अन्य सेमीफाइनल मुकाबलों में 36.38 किग्रा में लखनऊ जोन ए के प्रांजल जोशी ने कानपुर उत्तर के क्षितिज मिश्रा कोए 42.44 किग्रा में कानपुर उत्तर के वैभव कुमार शर्मा ने कानपुर दक्षिण के विनायक तिवारी कोए 44.46 किग्रा में मेरठ के अणर्व सिंह ने कानपुर दक्षिण के सूर्यांश कुमार को व 46.48 किग्रा में लखनऊ जोन बी के यजदान ने लखनऊ जोन ए के मयंक चौरसिया को हराया।

पुरानी दिल्ली 6 ने दिल्ली लायंस को सात विकेट से हराया

नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली 6 ने लगातार दो मैच में हार के बाद वापसी करते हुए वेस्ट दिल्ली लायंस को सात विकेट से हराकर दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना खाता खोला। बुधवार की रात को खेले गए मैच में पुरानी दिल्ली 6 ने लक्ष्मण (41 रन देकर तीन विकेट) और आयुष सिंह ठाकुर (27 रन देकर दो विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम को निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 141 रन पर रोक दिया। इसके बाद अर्पित राणा की 43 गेंदों में नाबाद 56 रन की पारी की बदौलत पुरानी दिल्ली 6 ने 17.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। राणा के अलावा सनत सांगवान ने 25 और वंश बेदी ने 18 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाए।

25 अगस्त से होने वाले यूपी टी-20 लीग के लिए टीमे लखनऊ पहुंचने लगी हैं। वहीं टीमों ने अभ्यास भी करना शुरू कर दिया है। यूपी टीम ने इकाना पर पसीना बहाना शुरू कर दिया हे।

क्विक न्यूज

किशोर ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में उम्मीदें बरकरार रखी, हरीश बाहर

माले (मालदीव)। हरीश मुथु को यहां एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के पुरुष ओपन वर्ग के क्वार्टर फाइनल में तीसरे स्थान पर रहकर निराशा का सामना करना पड़ा जबकि किशोर कुमार ने अंडर-18 वर्ग में अंतिम आठ चरण के लिए क्वालीफाई किया। मुथु और किशोर दोनो प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं जो 2026 एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाइंग स्पर्धा है। यहां थुलुस्धू में आयोजित प्रतियोगिता के चार श्रेणियों में आठ भारतीय सर्फर प्रतिस्पर्धा कर रहे है। तमिलनाडु के हरीश को क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की जोई सतरियावान और जापान के काइसेई अडाची से कड़ी टक्कर मिली। इन दोनों ने क्रमशः पहले और दूसरे स्थान स्थान के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया जबकि हरीश खिताबी दौड़ से बाहर हो गए। किशोर के सामने शुक्रवार को खेले जाने वाले क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपी के जॉन चैन और मालदीव के सैय्यद सलाहुद्दीन की चुनौती होगी।

सतीश जापान ओपन के दूसरे दौर में हारे

योकोहामा (जापान)। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश कुमार करुणाकरन ने गुरुवार को जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में थाईलैंड के कंटाफोन वांगचारोएन के खिलाफ हारने से पहले कड़ी चुनौती पेश की। सतीश (23 साल) 70 मिनट तक चले मुकाबले में दुनिया के 40वें नंबर के खिलाड़ी से पहले गेम की बढ़त गंवाकर 21-18 18-21 8-21 से हार गए। इस तरह टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती भी खत्म हो गई। सतीश बुधवार को शुरूआती मैच में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन के रिटायर होने के बाद दूसरे दौर में पहुंचे थे। सतीश ने अपना पहला बीडब्ल्यूएफ टूर्नामेंट 2023 में ओडिशा मास्टर्स से जीता था।

आईकू युवाओं को जोड़ेगा

बेंगलुरू। आईकूने एक बार फिर अपने पूरी तरह से लोडेड आईकू जेड 9एस सीरीज, जिसमें आईकू जेड 9एस प्रो 5जीऔर आईकू जेड 9एस 5जी शामिल हैं, के लॉन्च के साथ इंडस्ट्री में नई मिसाल कायम की है। आईकू जेड 9एस सीरीज़ मेगाटास्कर्स के लिए पूरी तरह से लोडेड है मुख्य रूप से कॉलेज के छात्र और युवा पेशेवर जिन्हें तेज़ कनेक्टिविटी और सीमलेस एंटरटेनमेंट की आवश्यकता होती है। आईकू जेड 9एससीरीज़ उन्हें आसानी से मल्टीटास्क करने में सक्षम बनाएगी, जिससे उन्हें अपने व्यस्त जीवन को बेहतर ढंग से मैनेज करने और दिन भर कनेक्टेड रहने में मदद मिलेगी।लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, आईकूके सीईओ निपुन मार्या ने कहा आईकू जेड 9एस सीरीज़ कॉलेज के छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए बनाई गई है जो असली मेगाटास्कर्स हैं, जो अपने व्यस्त ऐकडेमिक, प्रोफेशनल और सामाजिक जीवन को संतुलित करते हैं। आईकू जेड 9एस सीरीज़ असाधारण प्रदर्शन, उन्नत कैमरा क्षमताओं और आकर्षक डिज़ाइन का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करती है जो हमारे युवाओं की तेज-तर्रार जीवन शैली के पूरक है और निश्चित रूप से इस श्रेणी में नए मानक स्थापित करेगी।अमेज़ॅन इंडिया के वायरलेस और होम एंटरटेनमेंट के निदेशक रंजीत बाबू ने कहा हमें फीचर-रिच आईकू जेड 9एससीरीज़ को पेश करके आईकूके साथ अपनी चल रही भागीदारी को मजबूत करने में खुशी हो रही है, जिसमें आईकू जेड 9एस प्रो 5जीऔर आईकू जेड 9एस 5जी शामिल हैं।

गेम्स और वीडियो चैट का ले सकेंगे आनंद

नई दिल्ली। भारत के सर्वश्रेष्ठ 5जी स्मार्टफोन ब्रांड मोटोरोला ने मोटो जी45 5जी के लॉन्च की घोषणा की। मोटो जी45 5जी ने अपने दमदार स्नैपड्रेगन 6एस जेन3 प्रोसेसर के साथ भारत में किफायती 5जी स्मार्टफोन बाजार में धूम मचा दी है, जो बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए वीओएनआर के अलावा इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा 13 5जी बैंड्स के साथ बेहतरीन परफॉरमेंस देता है। अत्यंत पतले बेज़ेल्स और मॉडर्न पंच होल डिस्प्ले वाले बड़े आकार के स्क्रीन की वजह से इस स्मार्टफोन पर मूवी, गेम्स और वीडियो चैट देखने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है।अल्ट्रा-प्रीमियम डिजाइन वाले मोटो जी45 5जी का लुक शानदार है, जिसे जी-सीरीज के स्मार्टफोन में पहली बार 3 खूबसूरत पैन्टोन क्यूरेटेड कलर वेरिएंट तथा वीगन लेदर फ़िनिश के साथ पेश किया गया है। साथ ही यह इस सेगमेंट में सबसे पतला और सबसे हल्का डिवाइस भी है। मोटोरोला इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, टी.एम. नरसिम्हन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मोटो जी45 5जी को लॉन्च करते हुए हमें बेहद प्रसन्नता हो रही है, जो किफायती सेगमेंट में मोटोरोला का सबसे तेज़ और सबसे सक्षम 5जी स्मार्टफोन है। हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का फायदा हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, और देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को किफायती मूल्य पर सबसे शानदार 5जी अनुभव उपलब्ध कराना ही हमारा उद्देश्य है।

खेल व शिक्षा में योगदान के लिए उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार

गोरखपुर। यंग फोक्स अकादमी की संस्थापक उषा मस्करा को शीर्ष 30 प्रेरणादायक महिला पुरस्कार 2024 में दिवा प्लैनेट द्वारा प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाल शिक्षा के क्षेत्र में मस्करा ने समर्पण और नवाचार के आधार पर पिछले 28 सालों में उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए तथा अपने काम से गोरखपुर और उसके बाहर अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया है। इस कार्यक्रम में उनके काम को सम्मानित किया गया। दूरदर्शी नेतृत्व और अभिनव शैक्षिक प्रथाओं के माध्यम से इन बच्चों के भविष्य को मस्करा आकार दे रही है। उनकी इसी प्रतिबद्धता को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मस्करा ने लंबे समय से इस क्षेत्र में काम किया है, नई शिक्षण विधियों को शामिल किया है और ऐसा स्थान बनाया हैं जहां बच्चे सीखने और खेलने के संतुलित वातावरण में पनप सकें। मस्करा ने लगभग तीन दशक पहले सिर्फनौ छात्रों के साथ यंग फोक्स अकादमी की स्थापना की थी। प्रारंभिक बाल्यावस्था की विकास के लिए एक पोषणकारी और समग्र वातावरण को बढावा देने के उनके जुनून से प्रेरित होकर यह स्कूल अब 150 से ज़्यादा छात्रों की सेवा करने लगा है।।

नवीन पटनायक ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम को सम्मानित किया

भुवनेश्वर। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस महीने की शुरुआत में पेरिस में ओलंपिक खेलो में लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कुछ सदस्यों को गुरुवार को यहां सम्मानित किया।पटनायक की अगुवाई वाली ओडिशा की पिछली सरकार ने भारतीय हॉकी को बढ़ावा देने मे अहम भूमिका निभाई थी। ओडिशा 2018 से राष्ट्रीय पुरुष और महिला टीमों को प्रायोजित कर रहा है। पटनायक ने उम्मीद जताई की भारतीय टीम 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतेगी।पटनायक ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप स्वर्ण पदक लाएंगे। इस मौके पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की के साथ सुमित, ललित कुमार उपाध्याय, अभिषेक और संजय मौजूद थे।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी-33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522-4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह।
पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।